

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 मार्च, 1985

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 25 मार्च, 1985

पृष्ठ संख्या

स्थगित तारांकित प्र न संख्या 817 पर अनुपूरक प्र न (पुनरारम्भ)	(12)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(12)4
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(12)40

तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	
24-3-1985 को चण्डीगढ़ में हत्या किए गए व्यक्तियों के परिवारों को संवेदना संदे ।	(12)52
अध्यक्ष द्वारा घोशणा— स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के भाोक प्रस्ताव के बारे में प्रधान मंत्री के उत्तर संबंधी	(12)53
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— रोहतक में पेय जल के संकट संबंधी	(12)52
वक्तव्य— लोक स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(12)54
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(12)59
वर्ष 1985-86 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(12)61

हरियाणा विधान सभा

भाक्रवार, 22 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1 चण्डीगढ मे 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

स्थगित तारांकित प्र न संख्या 817 पर अनुपूरक प्र न (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, before the questions listed for today are asked, the supplementaries on Starred Question @No. 817 listed in the name of Prof. Sampat Singh for 22-3-1985 will be asked first.

श्री वीरेन्द्र सिंह: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कपडे के लिए जो टैंडर्ज मांगे गए, वे किस किस से मांगे और कपडे का क्या रेट था ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, 1982 में पुलिस के लिए जो कपडा खरीदा गया उसके लिये पहले तीन कोटे न आये और उन फर्मों के नाम हैं, मैसर्ज ने नल वूलन मिल्ज, चण्डीगढ, मैसर्ज कानुपर वुलन मिल्ज, कानपुर और मैसर्ज न्यू एगरटन वूलन मिल्ज, धारीवाल। स्पीकर साहब, मै0 नै नल वूलन मिल्ज, चण्डीगढ का दर 79.00 रूपए प्रति मीटर था, मै0 कानपुर वूलन मिल्ज, कानपुर का रेट 64.44 रूपए प्रति मीटर था लेकिन इनका टैंडर टैस्ट रिपोर्ट व सैम्पल न होने के कारण

अस्वीकृत कर दिया गया। मै0 न्यू एगरटन, वूलन मिलज, धारीवाल का रेट 84.40 रूपए प्रति मीटर था। मै0 नै नल वूलन मिलज, चण्डीगढ से 79.00 रूपए के भाव से 2818 मीटर कपडा 222622 रूपये का खरीदा गया। स्पीकर साहब, इसके बाद पांच कोटे नल आए। पहला मै0 नै नल वूलन मिल, चण्डीगढ का दूसरा मै0 पानीपत वलून मिल, खडा का, तीसरा मै0 केपकोन, नई दिल्ली का, चौथा मै0 न्यू एगरटन वूलन मिल, धारीवाल का और पांचवा मै0 कानपुर वूलन मिलज, कानपुर का। इनके रेट क्रम ा: इस प्रकार से है: 79.00 रूपए, 72.90 रूपए, 84.00 रूपए, 92.25 रूपए और 96.00 रूपए प्रति मीटर। मै0 नै नल वूलन मिल, चण्डीगढ का कोटे नल स्वीकृत किया गया और 11050 मीटर कपडा 872950.00 रूपये का खरीदा गया। मै0 नै नल वूलन मिल, चण्डीगढ का ही 72.00 रूपए वाला ए सैम्पल मस्टर पैटर्न के अनुरूप नहीं था। फिर तीन टैंडर आए। इनमें से एक मै0 नै नल वूलन मिलज, चण्डीगढ का था और दूसरा मै0 स्वास्तिक वूलन मिलज, पानीपत का था और तीसरा न्यू एगरटन वूलन मिलज, धारीवाल का था। इनहोंने 80 रूपए प्रति मीटर कीमत कोट की थी। मै0 स्वास्तिक वूलन मिलज ने 58.44 रूपये प्रति मीटर रेट कोट किया था लेकिन सैम्पल मस्टर पैटर्न के अनुरूप नहीं था। अतः अस्वीकृत किया गया। इनमें से मै0 नै नल वूलन मिलज, चण्डीगढ को आर्डर प्लेस किया गया और 3839 मीटर कपडा खरीदा गया। इसके बाद ग्रेट कोट क्लोथ खाकी तीन हजार मीटर लिया गया। इसमें तीन टैंडर आए। एक मै0 नै नल वूलन मिलज,

चण्डीगढ का, दूसरा मै० पानीपत वूलन मिल्ज, खरड का और तीसरा मै० न्यू एगरटन वूलन मिल्ज धारीवाल का। इनके रेट क्रम 1: 64.00 रूपए, 71.67 रूपए और 77.50 रूपए प्रति मीटर थे। मै० नै नल वूलन मिल्ज चण्डीगढ को 192000.00 रूपए का आर्डर प्लेस किया गया। इसके बाद 3500 मीटर कपडा खरीदा गया। इसके लिए चार टैंडर आए। एक मै० नै नल वूलन मिल्ज, चण्डीगढ का दूसरा मै० स्वास्तिक वूलन मिल्ज, पानीपत का तीसर मै० कानपुर वूलन मिल, कानपुर का और चौथा मै० न्यू एगरटन वूलन मिल्ज, धारीवाल का। इन्होंने क्रम 1: रेट कोट किए: 66.00 रूपए और 56.00 रूपये प्रति मीटर। 5660 वाला सैम्पल मस्टर पैटर्न के अनुसार नहीं था। दूसरा रेट 58.44 रूपए, तीसरा 83.00 रूपये और चौथा 92.00 रूपये प्रति मीटर था। मै० नै नल वूलन मिल्ज, चण्डीगढ को 231000.00 रूपए का आर्डर प्लेस किया गया। स्पीकर साहब, इसके बाद अंगोला चार हजार मीटर खरीदा गया। इसमें चार टैंडर आए। मै० नै नल वूलन मिल्ज, चण्डीगढ ने 55.00 रूपए प्रति मीटर रेट कोट किया। मै० पानीपत वूलन मिल्ज खरड ने 55.90 रूपए प्रति मीटर रेट कोट किया, मै० न्यू एगरटन वूलन मिल्ज धारीवाल ने 59.80 रूपए प्रति मीटर रेट कोट किए और मै० कानपुर वूलन मिल्ज ने 60.00 रूपए प्रति मीटर रेट कोट किया गया। इसके बाद कोटन ड्रिल खाकी 25000 मीटर खरीदा गया। इसके लिये तीन टैंडर आए। पहला मै० गोयल कारपोरे न चण्डीगढ (एलगन मिल) दूसरा मै० एलगन मिल, कानपुर और तीसरा मै० जे०के० मार्किटिंग कलकत्ता का थरा।

पहले वाले ने 8.68 रूपए प्रति मीटर रेट कोट किया। दूसरे ने 8.03 रूपए रेट कोट किया लेकिन इसके साथ टैस्ट रिपोर्ट और सैम्पल नहीं भेजा। तीसरे ने 8.45 रूपए प्रति मीटर रेट कोट किया लेकिन इसने भी टैस्ट रिपोर्ट और सैम्पल नहीं भेजा। इसमें मै0 गोयल कार्पोरे इन चण्डीगढ को 217000.00 रूपए का आर्डर प्लेस किया गया।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जितना पढा है उतना काफी है। स्पीकर साहब, जवाब में बताया गया है कि कुछ के कोटे इन लोयर भी थे और एक दो के रिजैक्ट भी किए गए क्योंकि उन्होंने सैपल नहीं भेजे थे और एक दो फर्ज के सैम्पल अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं थे। मतलब यह है कि वह कपडा अप टू दी मार्क नहीं था। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी में कोई टैक्नीकल आदमी टैक्सटाइल का ऐक्सपर्ट भी बैठाया गया था या नहीं ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, 1982 में कोई हाई पावर्ड कमेटी नहीं थी। मई, 1983 में कमेटी बनाई गई थी। उससे पहले पांच आदमी कमेटी में बैठते थे। इन पांच आदमियों में एक सप्लार्ज एण्ड डिस्पोजल विभाग का आदमी होता था, एक टैक्सटाइल ऐक्सपर्ट बैठता था, एक हमकमे का सीनियर अधिकारी बैठता था और दो डिपार्टमेंट के आदमी बैठ कर फैसला करते थे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: जो टैक्सटाइल का ऐक्सपर्ट होता था उसका नाम क्या है ?

चौधरी भजन लाल: उसका नाम इस वक्त मेरे पास नहीं है। स्पीकर साहब, पांच आदमियों की कमेटी बनी हुई है। जो चीज परचेज की जाती है उसमें उस चीज की जिस आदमी को जानकारी होती है, उसको भामिल किया जाता है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जो सूचना सदन को दी गई है। उसमें बताया गया है कि कुछ फर्ज के रेट ऊंचे थे और कुछ के नीचे भी थे। मेरी सप्लीमेंटरी श्री वीरेन्द्र सिंह के सवाल से मिलती जुलती है। मुख्य मंत्री जी सैंपल की बात कर रहे थे, टैंडर जिसका नीचा हो उसकी भी बात कर रहे थे, कपडे के स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री के जवाब से पता लगता है कि जो सब से ज्यादा रेट थे उसको भी इन्होंने छोड़ दिया और जो सब से नीचे वाला रेट था उसको भी छोड़ दिया और नीचे से ऊपर वाला जो रेट था वह कपडा लिया गया। इसका मतलब यह है कि कपडा खरीदने में डिस्क्री न की बात हुई। जिस मिल का कपडा लेना चाहें वह लिया जा सकता है। रेट ऊंचा और नीचा होने का कोई फर्क नहीं है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस मिल का सबसे लोएस्ट टैंडर था उसका कपडा क्यों नहीं लिया गया उससे ऊंचे रेट का कपडा क्यों खरीदा गया ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, बाकयदा औडिट होता है और इसमें किसी अधिकारी के गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर साहब, टैंडर इंवाइट किए जाते हैं। सारी चीजें देखी जाती हैं। जब इ तहार निकालते हैं तो उसमें दिया जाता है कि सैम्पल साथ लगा होना चाहिए और दूसरी कंडी ांज पूरी करनी चाहिए। जो सैंपल होता है उसका टैस्ट होता है। कुछ लोग सम्पल नहीं भेजते और कुछ के सैम्पल जो चीज मांग रखी है उसके मुताबिक नहीं होते तो ऐसी हाल में वह चीज लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर साहब, बाकायदा औडिट होता है अगर किसी को इग्नोर किया जाए तो उसके बारे में जवाब देना पडता है

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, प्रो० सम्पत सिंह ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं आया है। ये टाल मटोल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इसमें टाल मटोल की क्या बात है ? टैंडर के साथ सैम्पल मांगे जाते हैं और अगर कोई टैंडर की कंडी ांज को पूरी नहीं करता तो आप क्या करेंगे ?

चौधरी ओम प्रका ा: मुख्य मंत्री महोदय ने अलग अलग फर्मर्ज के नाम लिए हैं जिनसे कि कपडा खरीदा गया है। स्पीकर साहब, ने ानल लैवल पर एक टैक्सटाइल कार्पोरे ान है। क्या सरकार द्वारा इस बात पर विचार किया जाएगा कि जितना भी

कपडा खरीदना हो वह ने इनल टैक्सटाईल कार्पोरे इन से ही खरीदा जाए ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, 57 लाख का कपडा जो भारत सरकार का बना हुआ है वह भी लिया गया है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कपडा खरीदने का कमेटी ने जो फैसला किया वह फैसला मुतफिका था या किसी मैम्बर का डाइसैन्टिंग नोट भी था ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, कमेटी का यूनानिमस फैसला था और कोई डाइसैन्टिंग नोट नहीं था। स्पीकर साहब, जो सरकारी अदायरे हैं उनको पहल दी जाती है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने अभी अपना जवाब देते हुए यह बताया कि जब हम टैंडर काल करते हैं तो उस के लिये कुछ कंडी ान्ज होती हैं जिनको फुलफिल करना पडता है। मैं आपके द्वारा उनसे यह जानना चाहता हूं कि वे कौन सी ऐसी कंडी ान्ज होती हैं ? हाउस के मैम्बर्ज को भी उन कंडी ान्ज की जानकारी तो होनी चाहिये।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, कई तरह की कंडी ान्ज होती हैं, जैसे पहली क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाता है, कपडे का तना कितना होना चाहिये, उसकी डयूरे इन कितनी

होगी, कितना खिचाव वह कपडा बर्दा त कर सकता है आदि आदि। इन सभी बातों को सामने रखकर कपडा खरीदा जाता है।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब आज की क्वै चन लिस्ट को टेक अप किया जाएगा।

Disturbances upon the assassination of Mrs. Indira Gandhi

***818. Smt. Chandravati, Prof. Sampat Singh, Sh. Hira Nand Arya:** Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state-

(a) whether any disturbances took place in the State after the assassination of Mrs. Indira Gandhi during the period from 31st October 1984 to 10th November 1984; if so, the number of persons, if any, murdered in the State in the said disturbances together with the names of the places where such murders were committed;

(b) the amount of property, if any, lost due to arson/looting during the said disturbances and the amount of looted property, if any, recovered so far;

(c) the names and addresses of the persons against whom cases of murder/attempt to murders, looting and arson have been registered together with the details of offences in each case;

(d) the amount of compensation, if any, paid to the persons who suffered losses due to arson/looting, as referred to above; and

(e) whether any cases, out of those referred to in part (a) and (c) above are still untraced; if so, the number thereof ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): पूछी गई सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: मैम्बार साहेबान, जैसा इस क्वै चन के जवाब में बताया गया है, मुझे सैपरेट लैटर भी आया है। It think we all agree that. इससे कम्युनल भावना और बढ़ेंगी। कई ऐसी बातें हैं जो सरकार कहना नहीं चाहती। इससे मैं भी सहमत हूँ और मेरा ख्याल है कि सारा हाउस भी इससे सहमत होगा। इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि इस मसले पर हम ज्यादा हिंसक न न करें तो अच्छा होगा।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, जुडिाियल इंक्वायरी तो ये करवा सकते हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा सरकार का काम नहीं है। यह तो भारत सरकार का मसला है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह ठीक है कि ये उन लोगों के नाम और पते न बताएं लेकिन जो इतनी ज्यादा ट्रेजडीज हुई है उनके बारे में तो बताएं। (और एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सरकार के साथ एग्री न करें लेकिन मेरे साथ तो एग्री करेंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: आप मेरी सबमिशन सुन लें अगर आपको जंच जाए तो ठीक है। इन रायट्स के लिए जो कम्पनसेशन रखी है वह है कि जिसका मकान बरबाद हो गया या जो मर गया है उसकी फैमिली को 10 हजार रूपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिवाय एक दो केसिज को छोड़ कर किसी को भी कम्पनसेशन नहीं मिलता है। एक फैमिली जो 17 मैम्बर्स की थी उसके 16 आदमियों को मिसिंग दिखा दिया गया (विधन) इस तरह से 10 हजार रूपए एक फैमिली को देना, यूँ ही आंसू पोंछने वाली बात है। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य जरा ज्ञान से या सोच समझ कर देखते तो इनको यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिये था। इन्होंने यह कह दिया कि किसी को भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। यह गलत है। सरकार ने 10 हजार रूपया फी फैमिली के हिसाब से मरने वाले की फैमिली को और 10 हजार रूपया मकान वगैरह जिनके जल गये हैं, बरबाल हो गये हैं, उनको दिये हैं। इस तरह से 55 लाख रूपये की सहायता सरकार ने इसके लिये दी है और ये कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया है।

चौधरी धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत है। श्री मांगे राम विधायक का बहादुरगढ में मकान था जो कि लगभग एक लाख का होगा वह पूरी तरह से बरबाद हो गया था लेकिन उनको केवल 1600 रूपये मुआवजे के तौर पर दिये गये हैं।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर सर, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया कि लोगों को राहत के तौर पर सरकार ने 55 लाख रूपये की सहायता दी है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि जो 43 लाख रूपये की लूटिंड प्रॉपर्टी की रिकवरी हुई है, क्या वह पैसा भी इस पैसे में भामिल तो नहीं है ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इन्होंने तो सप्लीमेंटरीज पूछनी भुरु कर दीं यह बात ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सरकार ने 10 हजार रूपये फी फ़ैमिली के हिसाब से मरने वाले की फ़ैमिली को और 10 हजार रूपया जिनका मकान नश्ट हो गया है उनको सहायता के तौर पर दिया है। इस तरह से टोटल राशि 55 लाख रूपया बनती है जो कि सरकार की ओर से सहायता के तौर पर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: साहेबान आपने सवाल के आगे लिखा जवाब पढ लिया है। मैंने भी रिकवैसटिंग मूड में यह कहा कि आप सब मेरे से सहमत होंगे लेकिन लीगल पोजी इन यह है कि अगर

सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो मैं उसके लिये सरकार को फोर्स नहीं कर सकता। इसलिये मैंने वे लफज पहले इस्तेमाल नहीं किये मैंने कहा कि अगर मैम्बर्ज सहमति प्रगट करें सप्लीमेंटरी न पूछें तो ठीक होगा। (गोर एवं व्यवधान)

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन थी। इस आपके साथ बिलकुल सहमत हैं कि भायद इन्फर्मेसन पब्लिक इंट्रैस्ट में नहीं है लेकिन रूलज आफ प्रोसीजन के अनुसार जब आप किसी क्वेश्चन को ऐडमिट कर लैते हैं तो क्या कोई मंत्री या मुख्य मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि हम इसी इन्फर्मेसन नहीं देंगे या यह सूचना देना पब्लिक इंट्रैस्ट में नहीं है ? क्या यह बात कहना चेयर पर ऐसपॉसिबल नहीं है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मेरी भी एक सबमिशन है कि चीफमिनिस्टर साहब डैथ्स के बारे में भले न बताएं लेकिन दूसरी बातें तो बता दें। उन्होंने यह कहा है कि इन सब बातों को बताना पब्लिक इंट्रैस्ट में नहीं होगा। मैं तो आपके द्वारा उनसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो 55 लाख रूपये की राशि लोगों को राहत के तौर पर दी है उसमें 43 लाख रूपया जो लूटिड प्रोपर्टी का इकट्ठा हुआ है, वह भी शामिल है या नहीं ? क्या क्लेम की गयी प्रोपर्टी वारिसों को चली गयी है कि नहीं ? (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो प्रोपर्टी रिकवर हुई है, वह उनके मालिकों को अवय मिलेगी यदि वह उनकी होगी उन्हें यह साबित करना होगा।

श्री अध्यक्ष: दहिया साहब, आपने अपनी बात कही और मेरी रूलिंग चाही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई दफा क्वैचन ऐडमिट होने के बाद सरकार रिप्रेजेंट करे या सरकार हाउस में यह कहती है कि इन्फर्मेण्ड देने से हालात बिगड़ेंगे और स्पीकर खुद इस बात को महसूस करे कि यह क्वैचन ऐडमिट नहीं होना चाहिए था तो उन हालात में स्पीकर यह नहीं समझता कि उसको डिस्ओबे किया गया है। मैं चूँकि इस बात से सहमत हूँ इसलिये मैंने यह बात कही है।

Construction of Water Tanks

***860 Ch. Balvir Singh Grewal:** Will the Minister of State for Public Health be pleased to state-

(a) whether any life span is fixed for the water supply tanks constructed by Public Health Department; if so, the details thereof;

(b) districtwise number of water tanks existing at present in the rural areas together with the year of construction of each one of them and the amount of expenditure incurred on the construction thereof in the State:

(c) whether any of the water supply tanks, out of those referred to in part (b) above, got damaged before they

completed their life span, if any fixed; if so, details thereof togetherwith the action, if any, taken against the officer/official/constructor, if any, held responsible therefor; and

(c) the per capita litres of water being supplied at present in the rural and urban areas separately togetherwith the criteria fixed thereof ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) जी हां, 50 वर्ष।

(ख), (ग) तथा (घ) सूचना अनुबन्ध 1, 2 तथा 3 के रूप में पटल पर प्रस्तुत है।

अनुबन्ध 1

जिलावार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के लिये बनाये गये टैंक-

क्र० सं०	निर्माण वर्ष	एस० और एस० टैंक	संख्या		
			क्लीयर वाटर टैंक	हाई लेवल टैंक	ओवर हैड सर्विस रैजरवायर
जिला अम्बाला					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैंकों की संख्या				
2	1966-67				
3	1967-68				
4	1968-69				
5	1969-70				
6	1970-71				2

7	1971-72				
8	1972-73				1
9	1973-74				2
10	1974-75				1
11	1975-76				2
12	1976-77				3
13	1977-78				1
14	1978-79				
15	1979-80		1		
16	1980-81				5
17	1981-82				3
18	1982-83				8
19	1983-84				2
20	1984-85 (अपटू 12-84)				3
	कुल		1		33

	1-11-66 तक अनुमानित राशि				
	1-11-66 से 12/84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)		0.06		24.61
जिला भिवानी					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैकों की संख्या	4	1	1	1
2	1966-67				
3	1967-68	1	2	1	
4	1968-69				
5	1969-70				

6	1970-71	7	6	6	6
7	1971-72	6	3	3	3
8	1972-73	2	2	1	
9	1973-74	2	2	2	
10	1974-75	2	2	1	1
11	1975-76	10	10	7	7
12	1976-77	5	6	43	
13	1977-78	3	2	2	2
14	1978-79	5	6	4	3
15	1979-80	5	4	4	4
16	1980-81	6	4	2	4
17	1981-82	1	1	1	3
18	1982-83	9	5	3	5
19	1983-84	4	2	2	
20	1984-85 (12 / 84)	2	7	7	

	कुल	74	65	51	42
	1-11-66 तक अनुमानित राशि	2.58	0.03	0.02	0.06
	1-11-66 से 12/84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)	129.46	23.29	10.25	34.88
जिला फरीदाबाद					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैंकों की संख्या				
2	1966-67				
3	1967-68				
4	1968-69				

5	1969-70				
6	1970-71				
7	1971-72				
8	1972-73				
9	1973-74				
10	1974-75				
11	1975-76				
12	1976-77				
13	1977-78				
14	1978-79				2
15	1979-80				
16	1980-81				
17	1981-82				2
18	1982-83				6
19	1983-84				

20	1984-85 (12/84)				
	कुल				10
	1-11-66 तक अनुमानित राशि				
	1-11-66 से 12/84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)				19.26
जिला गुड़गांव					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैकों की संख्या				1
2	1966-67				
3	1967-68				

4	1968-69				
5	1969-70				
6	1970-71				
7	1971-72				1
8	1972-73				1
9	1973-74				
10	1974-75				2
11	1975-76				
12	1976-77				
13	1977-78				
14	1978-79				
15	1979-80				
16	1980-81				1
17	1981-82				4
18	1982-83				2

19	1983-84				5
20	1984-85 (12 / 84)				4
	कुल				21
	1-11-66 तक अनुमानित राशि				0.20
	1-11-66 से 12 / 84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)				31.39
जिला हिसार					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैकों की संख्या	22	21	19	8
2	1966-67				

3	1967-68	4	2	2	
4	1968-69	1	1	1	
5	1969-70	1	2	1	1
6	1970-71	9	8	5	2
7	1971-72	4	4	2	
8	1972-73	8	6	4	3
9	1973-74	2	4	4	1
10	1974-75	7	2	3	4
11	1975-76	2	2	2	1
12	1976-77	7	7	7	
13	1977-78	7	7	5	
14	1978-79	10	9	7	2
15	1979-80	19	10	13	4
16	1980-81	14	21	17	7
17	1981-82	28	28	18	10

18	1982-83	37	59	40	14
19	1983-84	10	4	2	4
20	1984-85 (12 / 84)	7	2	5	6
	कुल	199	207	157	67
	1-11-66 तक अनुमानित राशि	6.82	2.10	0.84	1.12
	1-11-66 से 12 / 84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)	201.44	72.81	30.34	90.39
जिला जीन्द					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैकों की संख्या	3	3	1	

2	1966-67	1	1		
3	1967-68				
4	1968-69	2	1	1	2
5	1969-70	2	2	1	
6	1970-71	8	4	3	
7	1971-72	7	6	5	2
8	1972-73	10	10	9	1
9	1973-74				1
10	1974-75	2	2	1	3
11	1975-76	4	4	3	1
12	1976-77				1
13	1977-78	1	1	1	
14	1978-79	3	3	2	
15	1979-80				2
16	1980-81	3	3	3	3

17	1981-82	10	12	7	3
18	1982-83	13	17	12	4
19	1983-84	8	8	7	3
20	1984-85 (12 / 84)	12	13	10	1
	कुल	89	90	66	27
	1-11-66 तक अनुमानित राशि	1.85	1.31	0.04	
	1-11-66 से 12 / 84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)	109.91	21.46	10.60	45.20
जिला करनाल					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैकों की				

	संख्या				
2	1966-67				
3	1967-68				
4	1968-69				
5	1969-70				
6	1970-71				1
7	1971-72				
8	1972-73				
9	1973-74				
10	1974-75				2
11	1975-76				
12	1976-77				
13	1977-78				
14	1978-79				
15	1979-80				

16	1980-81	2	1		3
17	1981-82				
18	1982-83	2	2	2	
19	1983-84	3	4	4	
20	1984-85 (12 / 84)	1	2	2	
	कुल	8	9	8	6
	1-11-66 तक अनुमानित राशि				
	1-11-66 से 12 / 84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)	21.69	4.03	2.56	4.76
जिला कुरुक्षेत्र					
1	1-11-66 से				

	पहले वरतमान टैंकों की संख्या				
2	1966-67				
3	1967-68				
4	1968-69				
5	1969-70				
6	1970-71				
7	1971-72				
8	1972-73				1
9	1973-74				
10	1974-75				3
11	1975-76				3
12	1976-77				
13	1977-78				
14	1978-79				

15	1979-80				1
16	1980-81				
17	1981-82				
18	1982-83				1
19	1983-84				
20	1984-85 (12 / 84)				
	कुल				9
	1-11-66 तक अनुमानित राशि				
	1-11-66 से 12 / 84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)				6.52
जिला महेन्द्रगढ़					

1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैंकों की संख्या				3
2	1966-67				
3	1967-68				2
4	1968-69				1
5	1969-70				1
6	1970-71				3
7	1971-72				1
8	1972-73				
9	1973-74				2
10	1974-75				1
11	1975-76				
12	1976-77				
13	1977-78				1

14	1978-79				1
15	1979-80		2		2
16	1980-81		1		6
17	1981-82		11		3
18	1982-83		5		
19	1983-84				
20	1984-85 (12 / 84)				4
	कुल		21		31
	1-11-66 तक अनुमानित राशि				0.42
	1-11-66 से 12 / 84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)		12.80		40.18

जिला रोहतक

1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैंकों की संख्या	1	1	1	1
2	1966-67				
3	1967-68	1	1	1	
4	1968-69		1	1	1
5	1969-70	1	2	2	2
6	1970-71				
7	1971-72	4	5	2	2
8	1972-73	9	11	7	3
9	1973-74	1	1	1	
10	1974-75	4	4	4	3
11	1975-76				1
12	1976-77				

13	1977-78	3	3	3	
14	1978-79	3	4	2	
15	1979-80	5	3	4	2
16	1980-81	6	5	5	1
17	1981-82	15	14	4	
18	1982-83	19	19	7	2
19	1983-84	13	14	4	
20	1984-85 (12/84)	8	14	14	2
	कुल	73	102	63	20
	1-11-66 तक अनुमानित राशि	0.70	0.08	0.03	0.20
	1-11-66 से 12/84 के अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों)	202.12	28.35	10.45	19.88

	में)				
जिला सिरसा					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैकों की संख्या	10	10	9	6
2	1966-67				
3	1967-68				
4	1968-69				
5	1969-70				
6	1970-71				
7	1971-72				
8	1972-73				
9	1973-74				
10	1974-75				
11	1975-76	3	2	1	1

12	1976-77	2	3	2	1
13	1977-78	10	8	7	1
14	1978-79	21	13	10	5
15	1979-80	5	3	3	2
16	1980-81	11	17	9	7
17	1981-82	10	14	9	1
18	1982-83	14	20	14	6
19	1983-84	5	6	3	2
20	1984-85 (12 / 84)	7	12	9	1
	कुल	98	108	76	33
	1-11-66 तक अनुमानित राशि	2.41	1.36	0.44	2.17
	1-11-66 से 12 / 84 के अन्तर्गत	132.07	35.68	14.07	40.07

	अनुमानित राशि (लाखों में)				
जिला सोनीपत					
1	1-11-66 से पहले वर्तमान टैकों की संख्या	1	1	1	1
2	1966-67	1	1	1	1
3	1967-68				
4	1968-69				
5	1969-70				
6	1970-71				
7	1971-72				
8	1972-73				
9	1973-74				
10	1974-75				

11	1975-76				
12	1976-77				
13	1977-78	2	4	4	1
14	1978-79				
15	1979-80	6	10	6	
16	1980-81	8	12	8	
17	1981-82	1	2	1	
18	1982-83	2	3	2	
19	1983-84				
20	1984-85 (12 / 84)				
	कुल	21	33	23	3
	1-11-66 तक अनुमानित राशि	1.35	0.38	0.19	0.70
	1-11-66 से 12 / 84 के	59.60	13.11	5.27	6.10

	अन्तर्गत अनुमानित राशि (लाखों में)				
--	---	--	--	--	--

अनुबन्ध 2

जिले का नाम	ग्रामीण पेयजल वितरण योजना का नाम	क्षतिग्रस्त टैंकों की संख्या	क्षतिग्रस्त टैंक की किस्म	जिस वर्ष में टैंक का निम्पण हुआ	जिस वर्ष में टैंक क्षतिग्रस्त हुआ	अधिकारी / कर्मचारी / ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही
हिसार	1. बानमधारी	1	स्टोरेज तथा सैडिमेंटे टैंक	1970	1978	किसी भी अधिकारी / कर्मचारी / ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि टैंक को क्षति बिना किसी अनुमान के स्टोरेज तथा सैडिमेंटे टैंक के तल के ऊपर अधिक
	2. भटटू	1	"	1970	1978	
	3. बडोपल	1	"	1977	1978	
	4. पेटवार	2	"	1970	1978	

	5. थुराना	2	"	1971	1978	जलस्तर बढ़ने के कारण हुई है।
	6. भाटोल	1	"	1964	1978	
रोहतक	1. भलोत	1	"	1962	1982	यथोपरि
जींद	1. बेलेरखा	2	"	1970	1982	यथोपरि
	2. सिमला	1		1973	1982	
	3. बालु	1		1970	1982	
भिवानी	1. तिगड़ाना	1	"	1975	1984	स्टोरेज तथा सैडिमेंट्स टैंक की एक तरफ की ईंटों की लाईनिंग का कुछ भाग नीचे की लाईनिंग की अनिश्चित स्थिरता के

						कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इस टैंक की मुरम्मत कर दी गई है और कोई अधिकारी / कर्मचारी / ठेकेदार जिम्मेवार नहीं है।
	2. बरवा	1	"	1974	1984	जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, परन्तु टैंक की अभी मुरम्मत हो रही है।
सिरसा	1 अलिका	1	ओवरहैड सर्विस रिजर्वायर	1980	1980	पानी की ऊंची टैंकी टैस्ट करते समय गिर गई और ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर पुनः बनाई गई। इससे सरकार को कोई हानि नहीं

						ॐ २०१२
अम्बाला	1 मढोवाला	1	"	1982	1982	

अनुबन्ध 3

जल वितरण की निम्नलिखित प्रति दर मात्रा निर्धारित की गई है :-

1	न्यूनतम आव यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के बजट से चलाई जाने वाली ग्रामीण जल वितरण योजनाएं	45 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
2	भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जाने वाली ग्रामीण जल वितरण योजनाएं	40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
3	10,000 तक की जनसंख्या वाले भाहर	70-90 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
4	10,000 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले भार	90-100 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

5	50,000 से अधिक जनसंख्या वाले भार	100-190 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
---	-------------------------------------	--

ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न योजनाओं में वर्तमान प्रति दर मात्रा 10 लिटर से 40 लिटर के बीच में है। यह बिजली की उपलब्धि, नहरों पर आधारित योजनाओं के लिए नहरी पानी की उपलब्धि जलघर के निम्नण के प चात जनसंख्या में वृद्धि, स्टैंडबाई उपकरणों की प्राप्ति, एवं नलकूपों के मिलने वाले पानी की कमी हो जाने पर निर्भर करता है। भाहरी तथा वितरण योजनाओं में उपरोक्त कारणों के कारण एवं बढौतरी की योजनाओं के लिए भूतकाल में उपलब्ध कराई धनराि 1 के कारण वर्तमान प्रति व्यक्ति मात्रा 40 से 150 लिटर के बीच में है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, अभी माननीय मंत्री मोदया ने बताया कि जो टैंक बनते हैं, उनकी लाईफ 50 वर्ष की होती है लेकिन कई टैंक ऐसे भी हैं जो जिस साल में बने, उसी साल में टूट गये, इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, वैसे तो मैंने प्रार्थना की थी कि 50 साल का टंकी का समय अनुमानित होता है लेकिन कुछ केसिज में ये पहले गिर गये। जैसे हिसार में वानमधोरी, भटटू, बडोपल, पेटवार, थुराना और भटोल हैं। इनके पानी का स्तर काफी ऊपर आ गया और इनमें नीचे का पानी भामिल होने से इनको दोबारा ठीक करना पडा। अब इनका काम रुका नहीं

हुआ है। इसी तरह से रोहतक में एक भालोट गांव है। वहां भी नीचे का वाटर लैवल ऊपर आने से खराबी आई थी। उसमें किसी अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदार का कसूर नहीं था और उसे ठीक कर दिया है। इसी तरह से जीन्द में बेलरखा, सिमला और बालू गांव हैं। इनकी भी यही स्थिति थी। इसी तरह से भिवानी में तिगडाना और बरवा हैं। इनमें एक साइड से थोड़ी दीवार नीचे चली गई थी। उसको थोड़े से खर्च से डिपार्टमेंट ने रिपेयर कर दिया था। इसी तरह से सिरसा में अलीका गांव है। यह टैंक टैस्ट करते वक्त गिर गया था। इसका सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पडा, ठेकेदार ने इसको दोबारा बना दिया है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, एक तो इन टैंकों की कंस्ट्रक इन में सारे का सारा सब स्टैंडर्ड मैटिरीयल लगाया जाता है दूसरे में गांवों और भाहरों में पानी की डिस्पैरिटी के बारे में जानना चाहता हूं कि वहां एक और दस की डिस्पैरिटी क्यों है ? गांवों में प ुओं के पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है और प ुओं में बीमारी फैल रही है। मैं अपने जिले भिवानी की बात बता रहा हूं कि वहां पर जोहडों में पानी बिल्कुल नहीं है। पहले पब्लिक हैली का पानी आता था अब वह भी नहीं आता। इसलिये गांवों और कस्बों में यह डिस्पैरिटी क्यों है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इन्सान के भारीर के लिए पानी सब से जरूरी चीज है लेकिन हमारे कुछ जिलों में हालात ऐसे हैं जहां पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। वहां पर या

तो नहर का पानी लिया जाता है या कुंओं का पानी लिया जाता है। इसका कारण कुछ तो बिजली की दिक्कत की वजह से है और कुछ नहरों में कम पानी की वजह से है। जैसे आजकल भाखडा में पानी कम है इस वजह से नहरों में पानी टाइम पर नहीं आता। लेकिन सरकार इस मसले पर पूरी गम्भीरता से विचार कर रही है। पानी थोडा है तो थोडी भाक्ल में सब जगह दे रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने कुछ गांवों के नाम बताए जाहं कि टैंक खराब हो गए। इन्होंने पेटवार और थुराना गांवों का भी नाम लिया जो कि मेरे हल्के में हैं। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि ये दोनों टैंक कब से खराब हैं, क्या इनको यह भी इलम है कि इन गांवों में वाटर सप्लाई अभी भी नहीं हो रही है ? टैंक फटने की वजह से वहां पर जहरीला पानी हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन टैंकों के लिए कितना पैसा मंजूरव किया गया है और ये कब तक तैयार हो जाएंगे ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, वहां पर वाटर सप्लाई तो नहीं रूकी है लेकिन पानी की खराबी की वजह से दिक्कत जरूर है। पेटवार के लिए 3 लाख 60 हजार रुपए का एस्टीमैट बनाया हुआ था और थुराना के लिए 2 लाख 30 हजार रुपए का। दोनों की मुरम्मत करवा दी है और पानी चालू है।

श्री फतेह चन्द विज: अभी मंत्री जी ने बताया कि भाहरों में 100-190 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की सप्लाई दे रहे हैं। यह एवरेज इन्होंने किस आधार पर निकाली है और दूसरे पानीपत में कितने लीटर पानी दिया जा रहा है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, पानीपत में तो मैं भी काफी जाती रहती हूँ। वहाँ तो पानी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पर ट्यूबवैल्ज कामयाब हैं। मेरे नोटिस में तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैम्बर साहब चाहते हैं तो हम इन्क्वारी करवा लेंगे और कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जैसे कि अभी मंत्री महोदया ने बताया कि एक वाटर वर्क्स की कंस्ट्रक्शन के वक्त दीवार पड गई और उसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने वह ठेकेदार से दोबारा बनवा ली। स्पीकर साहब, जब कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम चलात है तो वहाँ पर ओवरसीयर, एस0डी0ओ0, एक्सीयन यानी इनका एक जिम्मेदार आदमी मौके पर रहता है और देखता है कि कोई सब स्टैंडर्ड मैटिरीयल तो नहीं लग रहा है। अब यह तो एक दीवार गिरी है और वक्त आएगा तो बाकी और दीवारें भी गिरेंगी। अगर कोई दीवार में घटिया सीमेंट लगा या किसी दूसरे काम में घटिया या कम सीमेंट लगा तो क्या सरकार ने उस अफसर की तहकीकात की कि उसकी सुपरवीजन ठीक न होने की वजह से ऐसा हुआ है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, सारी स्टेट में कोई पौने दो हजार के करीब टैंक बने हुए हैं। उनमें से सिर्फ दो टैंकों के बारे में जानकारी आई है। वैसे भी हम जितनी देर टैस्ट नहीं होता उतनी देर ठेकेदार को पेमेंट नहीं करते। इसीलिये ये दोनों टैंक ठेकेदार को दोबारा बनाने पड़े। बाकी सुपरवीजन के लिए पूरी हिदायतें हैं कि अच्छी तरह से की जाए और अच्छा माल लगाया जाए। इसी से यह जाहिर होता है कि पौने दो हजार टैंकों में से सिर्फ दो की जानकारी आई है।

चौधरी फूल चन्द: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी के ज्ञान में यह बात है कि अम्बाला जिला में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें पीने के पानी की दिक्कत है। वे असल में प्रोब्लम विलेज हैं लेकिन किसी एक अधिकारी की गलती की वजह से उनको प्रोबलम विलेज नहीं लिखा गया। वहां पर पानी नहीं है। क्या मंत्री महोदया इन गांवों का दोबारा सर्वे करवा कर वहां पर वाटर सप्लाई चालू करवाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, जहां जहां भी ऐसी बात नोटिस में आई है वहां हमने दोबारा सर्वे कराया है। माननीय सदस्य मेरे को लिखकर दे दें। वैसे हम अपने तौर पर भी सर्वे करवाते रहते हैं, लेकिन मैम्बर साहब अगर कोई स्पैशल गांव बताएंगे तो उनका भी सर्वे जरूर करवाया जाएगा। अगले दो सालों में हम सभी प्रोब्लम विलेजिज में पानी दे देंगे और इस योजना के अन्त तक भोश सभी जगह पानी दे देंगे।

श्री ए०सी० चोधरी: स्पीकर साहब, फरीदाबाद में डीग वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है और वह तकरीबन 60 किलोमीटर लम्बी लाइन फीड करती है। उसमें से आधे से ज्यादा ट्यूबवैल का पानी पीने के काबिल नहीं है। दूसरे सीकरी में तीन साल पहले गवर्नमेंट ने एक रैजरवायर मंजूर किया था लेकिन वह अब तक नहीं बन पाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस स्कीम को कब तक कार्यान्वित कर सकेंगे ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, एक एक गांव की तो मेरे पास डिटेल नहीं है लेकिन हमारी अपनी तरफ से कोर्पोरेशन होती है कि कहीं पर पानी खराब न दिया जाए। हमारी कोर्पोरेशन यह होती है कि पानी को अच्छी तरह से साफ करके और टैस्ट करके दिया जाए लेकिन माननीय सदस्य अगर कोई प्रोब्लम अलग से लिख कर बताएंगे तो उसका भी इन्तजाम करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहती हूँ कि वाटर कैरियर के लिए जो पाइपें बिछाई जाती हैं, क्या उनको टैस्ट करके बिछाया जाता है ? मुझे दादरी में लोगों ने एक दो जगह पर यह बताया है कि उनको बनाने में जो सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है वह ठीक नहीं होता और उनके अंदर होकर जो पानी जाता है, वह सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, वाटर कैरियर पाइपों को टैस्ट करके ही लगाया जाता है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने बताया था कि जो प्रोब्लम विलेजिज हैं उनको पीने का पानी दिया जाएगा। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि जिन गांवों में आज से 20-25 साल पहले पांच गेलन पानी देने की स्कीम थी और आज भी वहां पर केवल पांच गेलन पानी ही दिया जा रहा है जबकि उनकी आबादी बढ़ चुकी है ऐसे गांवों को प्रोब्लम विलेजिज मान करके ज्यादा पानी दिया जाएगा ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, जिस वक्त उन गांवों में वाटर सप्लाई स्कीम बनी थी उस समय वह उस वक्त की आबादी के हिसाब से बनी थी इसलिए वहां पर पानी की कुछ कमी है और उन गांवों के लोगों के हिस्से में पानी कुछ कम आता है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि कोई और ऐसी स्कीम बने जिससे उन गांवों में लोगों को पानी कुछ ज्यादा मात्रा में मिल सके।

मास्टर शिव प्रसाद: मंत्री महोदया ने सवाल के जवाब में बताया है कि भाहरी जल वितरण योजनाओं में उपरोक्त कारणों एवं बढौत्तरी की योजनाओं के लिए भूतकाल में उपलब्ध कराई धन राशि के कारण वर्तमान प्रति व्यक्ति मात्रा 40 से 150 लीटर के बीच में है। स्पीकर साहब, भाहरों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां

पर बिजली नहीं जाती है और पीने का पानी भी पूरी मात्रा में नहीं पहुंचता है। भाहरों में जहां पर आफिसर्ज कालोनी हैं उनमें 24 घंटे पानी और बिजली रहती है और पीने के अलावा पानी उनकी खेतीबाड़ी के काम में भी आता है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एवरेज निकाली है यह आफिसर्ज कालोनी के पानी की सप्लाई के हिसाब से निकाली है या जिन इलाकों में पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता उसके हिसाब से निकाली है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि किसी भी भाहर में किसी आफिसर्ज के लिए अलग से वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं है और न ही डिपार्टमेंट की ओर से आफिसर्ज कालोनीज को वाटर सप्लाई की स्कीम दी हुई है। जिस समय सारे भाहर को पानी देने का टाईम होता है उस समय सबको बराबर पानी मिलता है। हमारी यह भी कोशिश होती है कि जिन जगहों पर पीने का पानी किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाता है वहां चाहे डिपार्टमेंट को अपने टैंकों से पहुंचाना पड़े, पीने के लिए पानी पहुंचाया जाता है। डिपार्टमेंट की यह कोशिश होती है कि पीने का पानी सब को मिले।

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने मेन सवाल के जवाब में एक जगह पर लिखा है “ एर जल वितरण योजनाओं में उपरोक्त कारणों एवं बढौत्तरी की योजनाओं के लिए भूतकाल में उपलब्ध कराई धनराशि के कारण वर्तमान प्रति व्यक्ति

मात्रा 40 से 150 लीटर के बीच में है”। स्पीकर साहब, पिछले एक सप्ताह से रोहतक भाहर में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या रोहतक भाहर के लोगों को इस मात्रा में पीने का पानी मिल रहा है, अगर कम मात्रा में मिल रहा है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने इस बारे में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस भी दिया हुआ है, उसके द्वारा मैं इनको सारी स्थिति के बारे में बता दूंगी। स्पीकर साहब, भालोट डिस्ट्रिक्ट में पानी कम आता है और देर में आता है। रोहतक भाहरमें वाटर सप्लाई के दो टैंक हैं। एक टैंक में 21 दिन की सप्लाई से ज्यादा पानी नहीं रख सकते क्योंकि वह इतनी ही कैपेसिटी का टैंक है और दूसरे टैंक की कैपेसिटी 10 दिन तक का पानी रखने की है उस नहर में पानी देर में आने से रोहतक भाहर में पीने के पानी की थोड़ी दिक्कत आई थी इसलिए एक हफ्ता हम लोगों को 10 गेलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से ज्यादा पानी नहीं दे सके। इसके अलावा 23 तारीख को साढ़े बारह गेलन के हिसाब से और 24 तारीख को 14 गेलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी दिया है और यह उम्मीद है कि इतना पानी तो हम देते रहेंगे। लेकिन जब तक पानी रखने की कैपेसिटी नहीं बढेगी तब तक हम पानी ज्यादा नहीं दे सकेंगे।

**Repairs/overhauling of vehicles in the Irrigation (Drainage)
Departement**

***855 Sh. Kitab Singh:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of trucks, cars and jeeps existing at present in the Irrigation Department (Drainage Circles) in Haryana togetherwith total amount of expenditure incurred on their repairs to date;

(b) whether any of the vehicles, as referred to in part (a) above, have been overhauled; if so, the number thereof togetherwith the number of kilometres covered by each such vehicle at the time of overhauling and the amount of expenditure incurred for the said purpose separately; and

(c) the quantity of oil and mobil oil consumed by each one of the vehicles, as referred to in part (a) above, separately, during the period from 1-8-82 to 1-1-85 ?

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न के लिए गवर्नमेंट ने ऐक्सटेंशन मांगी है जो कि ग्रांट कर दी गई है। इस बारे में सम्बंधित मंत्री से आया पत्र इस प्रकार है :-

Interim reply

D.O. No. 33/3/85/IW-5

“S.S. Surjewala Irrigation & Power Minister,

Govt. of Haryana,

Chandigarh.

March 22, 1985

Dear Sh. Tara Singh Jil,

Kindly refer to Starred Assembly Question No. 855 regarding repairs/overhauling of vehicles in the Irrigation (Drainage) Department asked by Sh. Kitab Singh, M.L.A. which is due for answer on 25-3-1985.

2. In order to supply correct/complete information we require to collect the same from the field officers as also from other concerned Departments. It will take some time. I shall, therefore, be grateful if you kindly allow us 15 days' extension for replying this question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(S.S. Surjewala)

Shri Tara Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Shortae of electricicy in the State

***839 Sh. Hari Chand Hooda, Sh. Mahendra Partap Singh:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-the steps, if any, taken or proposed to be taken to remove the prevailin critical shortae of electricicy in the State ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): The following steps have been taken to meet with the shortage of electricity-

(i) Improvement in generation of Thermal Power Stations at Panipat and Faridabad.

(ii) Securing maximum power from Central/common pool projects against our own share.

(iii) Meticulous implementation of new regulatory measures to ensure equitable and just distribution of available power to all consumers.

(iv) Allocation of funds for the early completion of the on going projects.

(v) Completion of State-II of Panipat and Yamuna Nagar Hydro electric Project.

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन सारे प्रिकारों के बावजूद भी बिजली की इतनी कमी क्यों है ?

चौधरी भाम सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, बिजली की जो कमी है वह तीन चार कारणों से है। पहला कारण तो यह है कि इस वर्ष बारिश न होने की वजह से ऐग्रीकल्चर सेक्टर को मैक्सिमम बिजली की सप्लाई रही है। पिछले साल भी बारिश नहीं हुई और इस साल भी नहीं हुई जिसके कारण ऐग्रीकल्चर सेक्टर को बिजली की अधिक सप्लाई देनी पड़ी। दूसरा कारण यह है कि

भाखडा रिजरवायर में पानी का लैवल बहुत कम था जिसके कारण बिजली की जनरे 1न कम हुई। इसलिए हाइड्रो प्रोजैक्ट से हमें 30 लाख यूनिटस बिजली हर रोज कम मिली। तीसरा कारण यह था कि सेंट्रल प्रोजैक्टस से भी हमें बिजली का पूरा हिस्सा नहीं मिला।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो बिजली के मुतल्लिक बहुत से सवाल पूछे जा चुके हैं और मंत्री जी ने उनका जवाब दिया है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेन सवाल के जवाब में इन्होंने बिजली की कमी को दूर करने के लिए जो कदम उठाए गए बताए हैं, क्या उनसे बिजली की जनरे 1न में सुधार हुआ है और उन स्टैप्स को बिजली बोर्ड ने इम्पलीमेंट किया है ? हमारे जो पावर हाउसिज हैं उनमें कैपेसिटी के मुताबिक बिजली की जनरे 1न नहीं हो रही है। हमारी स्टेट के मुकाबले में दूसरी स्टेटस में बिजली की जनरे 1न की क्षमता ज्यादा रही है। स्पीकर साहब, बम्बई में प्राइवेट सैक्टर में जो बिजली दी हुई है उसमें कमी की कोई दिक्कत पैदा नहीं होती। क्या हमारी सरकार ने प्राइवेट सैक्टर के पावर हाउस में जो पूरी बिजली पैदा नहीं होती। क्या हमारी सरकार ने प्राइवेट सैक्टर के पावर हाउस में जो पूरी बिजली पैदा हो रही है, का अध्ययन कराया है या करवाने का विचार है जिससे हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकें, और बिजली की कमी न रहे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: सर, हमारे थर्मल प्लांटों की जनरे 1न पिछले अक्टूबर से अब तक सबसे ज्यादा रही है। पानीपत के दोनों यूनिट 60 प्रति 1त प्लांट लोड पर काम कर रहे हैं। पानीपत और फरीदाबाद के थर्मल प्लांटों को मिला कर हमारी बिजली रोजाना 54-55 प्रति 1त पैदा हो रही है जबकि आल इण्डिया लैवल पर 50 प्रति 1त प्लांट लोड बहुत बढ़िया माना जाता है। मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि हमारे इन दोनों प्लांटों ने कुल 64 लाख यूनिट बिजली पैदा की है। जब से ये प्लांट लगे हैं तब से लेकर आज तक इतनी बिजली पहले कभी पैदा नहीं हुई थी। कल जो बिजली तैयार हुई थी, वह एक रिकार्ड था। इस वक्त हमारे सारे यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल बिजली जो अवेलेबल है उसका 60 प्रति 1त भाग आज के दिन हरियाणा में पैदा हो रहा है। हमें हाइड्रो या दूसरी जगहों से कम बिजली मिल रही है।

श्री मंगल सैन: इनकी टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी क्या थी ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: सर, इसका जवाब तो मैं पहले भी डिटेल दे चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं कि टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी पर कोई म ीन कभी काम नहीं करती। (विघ्न) मैंने पहले बताया है कि आल इण्डिया लैवल पर 50.55 प्रति 1त प्लांट लोड फैक्टर बहुत बढ़िया माना जाता है जबकि

हमारे यहां पर 60 प्रति घंटा के आसपास बिजली पैदा हो रही है। आज के दिन हमारे सारे प्लांट काम कर रहे हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया है कि हमारी बिजली की उत्पादन में इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन महीनों में इन थर्मल प्लांटस में कितनी इम्प्रूवमेंट रिकार्ड की गई है ?

चौधरी भाम शेर सिंह सुरजेवाल: स्पीकर साहब, पिछले तीन महीनों की रिकार्ड इम्प्रूवमेंट इस प्रकार है— दिसम्बर 1983 में 760 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई थी जबकि दिसम्बर 1984 में 1220 लाख यूनिट पैदा हुई। जनवरी 1983 में 910 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई जबकि दिसम्बर 1984 में 1290 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई। फरवरी 1983 में 1300 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई थी जबकि इस साल फरवरी में 1360 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई है।

श्री किताब सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि उपभोक्ताओं को न्याय संगत बिजली दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसे उपभोक्ता या आवेद्यक सेवाएं हैं जिनको 16-16 घंटे लगातार बिजली दी जाती रही है ?

चौधरी भाम शेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, ऐसा कोई उपभोक्ता नहीं है जिसको 16 घंटे या 16 घण्टे से ज्यादा

बिजली मिलती हो। हां, जो रैगुलेटरी मैयर सिस्टम है, उसके मुताबिक जो एसिं टायल सर्विसिज जैसे होस्पिटल, टैलीफोन ऐक्सचेंज, रेलवे आदि उनको जरूर लगातार बिजली देने की को टा टा करते हैं। बाकी जो कंटिनुअस प्रोसैस में इन्डस्ट्रीज आदि हैं उनको 60 प्रति ता कट लगा कर बिजली देते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को सप्ताह में तीन दिन बिजली देते हैं यानि ये इण्डस्ट्रीज सप्ताह में तीन दिन बंद रहती हैं। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पूरे प्रान्त में जो डिफरेंट कन्ज्यूमर्ज हैं जैसे लाईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और ऐग्रीकल्चर सैक्टर आदि के लिए बिजली की मिनिमम सप्लाई नए टाइम टेबल के मुताबिक कर रहे हैं। हमने नया टाइम टेबल बनाया है जिससे यह फायदा हुआ कि पहली बार किसानों को दिन के समय बिजली मिलती भुरु हुई जिसकी वजह से वाटर मैनेजमेंट काफी अच्छा हो सका है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ है। नए टाइम टेबल के हिसाब से ट्रीपिंग और फलकचुए टान भी काफी हद तक एलीमिनेट हुई है। स्पीकर साहब, इसके अलावा हम तीन सैक्टरों के जरिये बिजली सप्लाई करते हैं। दो सैक्टरों को हम दिन में बिजली देते हैं और एक सैक्टर को रात के समय बिजली देते हैं। इनको भी हम वीकली रौटेट करते रहते हैं जिससे रात वालों को भी दिन के समय बिजली मिल सके।

चौधरी हुकम सिंह फोगट: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सेंट्रल पूल से हमें अपने हिस्से की बिजली की मात्रा पूरी क्यों नहीं मिल रही ?

चौधरी भाम े र सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, सेंट्र के प्रोजैक्ट संगरौली, बदरपुर और बैरासूल आदि हैं जो फिजिकली आउट साइड दी स्टेट है। जहां पर ये प्रोजैक्टस स्टेट में ही हैं, वहां भी बिजली की दिक्कत है। इनसे हमें अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता। ऐसी जगह पर जो बिजली पैदा होती है, वह कोमन ग्रिड होती हैं आप दिल्ली को ही ले लें। वह रास्ते में पडती है। वहां पर उनको बिजली की ज्यादा जरूरत होती है जिस कारण हमें बिजली कम मिलती है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से दो तीन सप्ताह के बीच में थोड़े से समय को छोड कर हमें सेंट्रज प ज से काफी बिजली मिलती रही है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने यूनियन ऐनर्जी मिनिस्टर से बात की और मैंने और सी0एम0 साहब ने यूनियन स्टेट मिनिस्टर आफ एनर्जी से भी बात की जिसकी वजह से हमें बिजली अपने भोयर की मिल पाई है।

मास्टर राम सिंह: स्पीकर साहब, पैडी के सीजन के अंदर रादौर हल्के में बिजली कम मिलती है जबकि साथ लगते हल्के इन्द्री में 24 घंटे बिजली मिलती है। इन्द्री हल्के मे भायद थर्मल प्लांट से बिजली आती है और हमारे हल्के में बी0बी0एम0बी0 से बिजली आती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता

हूं कि क्या इन्द्री हल्के की सरप्लस, बिजली को रादौर हल्के में सप्लाई करने का प्रबंध करेंगे ताकि वहां के किसानों की भी बिजली की दिक्कत दूर हो सके ?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अब इनको अबदुलापुर ग्रिड लाईन से बिजली मिलने लगी है। हमने दोनों इलाकों को जोडने की बात कही थी लेकिन अब इस इलाके के लोग इन्द्री के इलाके के साथ जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि वे मौजूदा परिस्थितियों से संतुष्ट हैं।

Wages to Social Forestry Labourers

***891 Smt. Basanti Devi:** Will the Minister of State for Forest and Jails be pleased to state-

(a) whether it is a fact that social forestry labourers in the State are not being paid their wages regularly; and

(b) if so, the details of such labourers as were not paid their wages on the due dates during the year 1984-85 (to-date) ?

Forests and Jails Minister (Sh. Goverdhan Dass Chauhan):

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्रीमती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, क्या इनके नोटिस में है कि फौरैस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड के लेबर को अगस्त 1984 से तनख्वाह नहीं मिली ? स्पीकर साहब, फौरैस्ट बोर्ड सडकों पर पेड लगवाता है। मैंने यह काम करने के लिए 4-5 आदमी लगवाये थे। इन आदमियों ने 4-5 महीने काम किया और फिर वापिस आकर मुझे कहने लगे कि हमें चूंकि तनख्वाह नहीं मिलती इसलिए हम वहां पर काम पर जाना नहीं चाहते। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यदि इनके नोटिस में ऐसी कोई बात है तो उसको ये क्या इन्तजाम करने जा रहे हैं ?

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, यदि बहन जी यह बताएंगी कि ये आदमी कहां कहां लगवाये थे और किस किस को तनख्वाह नहीं मिली तो मैं इसकी जरूर इन्कवायरी करवाऊंगा और उनको उनके पैसे दिलवाऊंगा।

चौधरी धीर पाल सिंह: क्या मंत्री महोदय की नालेज में है कि फौरैस्ट विभाग में जिला भिवानी, रोहतक या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो एम्पलाईज काम पर लगाये जाते हैं, वे किसी कानून के तहत लगाये जाते हैं या ऐसे ही लगा लेते हैं ? सन 1983 में कई कर्मचारियों को मजदूरी एक साल की इकट्ठी मिली है और 1984 की मजदूरी बकाया रहती है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन मजदूरों को इनका वेतन कब मिलेगा ?

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, यह सो ल फौरैस्टरी का क्वै चन है जिसका मैंने अभी जवाब दिया है। जो क्वै चन इन्होंने अब पूछा है, इसके लिए ये सैपरेट नोटिस दें, जवाब दे दिया जाएगा। अगर इनकी नौलेज में कोई ऐसी बात है तो बता दें मैं इसको डिपार्टमेंट से ऐग्जामिन करवा लूंगा और अगर किसी मजदूर के साथ कोई ज्यादाती है तो दूर कर दी जाएगी, किसी के साथ कोई ज्यादाती नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का मेन क्वै चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप किस महकमे की बात कर रहे हैं ?

चौधरी धीर पाल सिंह: फौरैस्ट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। जो लोग डेली वेजिस पर काम करते हैं उनको वेतन नहीं मिला।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी धीर पाल सिंह जी ने कहा कि जो लोग डेली वेजिज पर लगे हुए हैं, उनको तन्खाह नहीं मिली है। मैं आज इस बात का पता लगवाऊंगा कि जिन लोगों को तन्खाह नहीं मिली है, इसकी वजह क्या है ? आखिर मामला क्या है ? मैं इन्हें वि वास दिलाता हूं कि उनको तन्खाह 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी यदि उन्होंने काम किया होगा।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, डेली वेजिज पर जो मजदूर लगे हुए होते हैं, उनको पेमेंट करते समय कुछ मजदूरों के

अंगूठे ज्यादा अमाउंट पर लगवा लेते हैं लेकिन असल में तनखाह कम देते हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय इस बात की इन्क्वायरी करवायेंगे कि कितने लोगों के झूठे अंगूठे लगवाये हैं ?

चौधरी भजन लाल: बहन जी, आपको कितने लोगों ने लिख कर दिया है ? जिन लोगों ने आपको लिखायत लिख कर दी है, आप मेहरबानी करके उनकी दरखास्तें हमारे पास भिजवा दें। (व्यवधान) वेग और बेमायनी बात कहने के कोई मायने नहीं हैं। वे दरखास्तें हमें भिजवा दें, हम इन्क्वायरी करवा कर देख लेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: मैंने मानकवास गांव की बात आपको बताई थी और इसके साथ ही और भी उदाहरण दिये थे। मानकवास गांव में 4 लाख का अमाउंट इन्वॉल्वड है, आप इसकी इन्क्वायरी करवायें।

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, सड़कों के किनारे कीकर के पेड लगे हुए हैं जो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्या सरकार कीकर के दरख्तों की जगह सफेदा वगैरा के अच्छे दरख्त लगायें ताकि फसल खराब न हो ?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं बनता।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1984-85 में जिन लोगों ने मैनुअल लेबर के रूप में काम किया है, उनको टोटल कितना पैसा लेबर का दिया गया है ?

श्री गोवर्धन दास चौहान: 1984-85 में 258.20 लाख रुपया दिया है, कोई केस पेंडिंग नहीं है।

Defective lining of Kahanaur Branch of the Canal

***925 Ch. Om Parkash:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether it is in the notice of the Government that due to defective lining of the Kahanaur branch of the canal, the farmers of villages Chimani, Dubaldhjan, Kahanaur and Siwani are not getting their full share of irrigation water;

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to enable the said farmers to get their full share of water together with the time by which they are likely to get the same; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to hold an enquiry into the wrong/defective lining of the branch of canal, as referred to in part (a) above; if so, the time by which it is likely to be held ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala):

(a), (b) & (c) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(A) The lining of Kahanaur Disty. is not defective. There is no shortage of irrigation water to the farmers of

villages Chimni, Dubaldhan, Kahanaur and Siwani, located below RD 154, when Kahanaur Disty. runs with full supply. But, there is some shortage when the Disty. runs partially.

(B) To improve supply during the partial running of the Channel, the Head Regulators of Dhaurana and Pilana Minors which off take at RD 154 Kahanaur Disty. have been remodelled. It is expected that the farmers of villages Chimani, Dubaldhan, Kahanaur and Siwani will hence forth get their due share during partial supply also.

(c) Does not arise in view of (a) above.

चौधरी ओम प्रकाश : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि काहनौर डिस्ट्रिब्यूटरी की लाईनिंग डिफैक्टिव नहीं है। यह सही नहीं है। पिछले 3 सालों से चिमनी गांव के लोगों को नहर का पानी आबपा ही करने के लिए नहीं मिल रहा। इस डिस्ट्रिब्यूटरी पर 5 आउटलैट ग्राम चिमनी के लिए लगे हुए हैं। 3 आउटलैटस में 1 परसेंट भी पानी नहीं आता है और 2 आउटलैटस में मुकल से 20-30 परसेंट तक पानी आता है। जितना पानी चाहिए उतना कभी नहीं आया जिसकी वजह से धुराना और पिलाना माइनर्ज में पानी बहुत कम आता है। अगर आप नेकड आई से देखेंगे तो जज कर सकते हैं कि जब हम चिमनी गांव की तरफ जाते हैं तो लाइनिंग ऊंची दिखाई देती और जब काहनौर गांव की तरफ जाते हैं तो लाइनिंग नीची नजर आयेगी जिसकी वजह से चिमनी गांव की तरफ पानी नहीं जाता।

क्या मंत्री महोदय इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे कि यह लाइनिंग डिफैक्टिव क्यों है ?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, घुराना पिलाना माईनर आर0डी0 154 डिस्ट्रिब्यूटरी से निकलती है। इन दोनों माइनर्ज के जो हैड हैं, इनके लैवल डिस्ट्रिब्यूटरी के लैवल से थोडा नीचे हैं, क्योंकि दोनों माइनर्ज कच्चे हैं और काहनौर डिस्ट्रिब्यूटरी अब पक्की हो चुकी है तथा दोनों हैड री मौडल कर दिए गए हैं। हैड री मौडल करने से पहले जब इनमें पूरा पानी होता था तो दोनों माइनर्ज की टेल पर बराबर पानी होता था। जब आधा पानी रह जाता था, या पानी कम होता था तो माइनर्ज पानी फालतू लेती थीं और टेल पर पानी कम जाता था। अब री मोडल करने के बाद ये ईक्वल लैवल पर कर दी हैं। जब पूरा पानी चलता है तो ये प्रोपो नेटली पानी लेती है, पानी कम होगा तो कम लेंगी और ज्यादा होगा तो ज्यादा लेंगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पिछले तीन साल से चिमनी गांव को पानी नहीं मिला, मैं आपके सामने इरीगे ान की फिगर्ज रखना चाहता हूं। 1982-83 में आर0डी0 154, डाउन स्ट्रीम से जिसके बारे में इनका सवाल है, खरीफ में 1204 एकड में आबपा ि हुई है और रबी में 1404 एकड में आबपा ि हुई है। टोटल 2608 एकड बनता है। इसी तरह से 1983-84 में खरीफ की आबपा ि 1136 एकड, रबी में 1331 एकड और टोटल 2467 एकड बनती है। इस साल पहले से कम आबपा ि हुई है और इसका कारण यह

था कि पिछले दिनों पानी की बहुत कमी रही क्योंकि यमुना नदी में बहुत कम पानी आया, इसी वजह से पूरा पानी नहीं गया जिसकी वजह से आबपा में थोड़ा सैट बैक रहा। कम डिस्चार्ज के वक्त हो सकता है टेल पर पानी कम गया हो, लेकिन अब री माडलिंग कर दी गई है। अब पानी कम जाने का सवाल नहीं है।

चौधरी हुकम सिंह फोगट: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले साल पिलाना माईनर से कितनी आबपा में हुई है और कितने एरिया में हुई है ? इसी तरह दुबलधन माईनर से कितनी आबपा में हुई और कितने एरिया में हुई है ?

चौधरी भाम शेर सिंह सुरजेवाल: स्पीकर साहब, मेरे पास सारे माइनर की आबपा में की फिगर नहीं हैं। जो सवाल पूछा था मैंने खास तौर पर उसी की फिगर मंगवाई थी।

चौधरी ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो फिगर दी हैं, मैं उन से डिफर करता हूँ। क्योंकि स्पॉट पर पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: उनके पास रिकार्ड है और ये रिकार्ड के बेस पर आपको बता रहे हैं।

चौधरी ओम प्रकाश: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिब्यूटरी की लाइनिंग से पहले पानी की सप्लाई की क्या पोजीशन थी ? क्या पानी टेल तक पहुंचता था या नहीं

पहुंचता था ? इसकी री माडलिंग की बी और री माडलिंग करने के बाद अब पोजी न में सुधार हुआ है या नहीं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाल: अध्यक्ष महोदय, इसकी री माडलिंग 1985 में की है। पूरी डिस्ट्रिब्यूटरी की परसैंटे आफ इरीगे न की पोजी न में बता देता हूं। पूरी काहनौर डिस्ट्रिब्यूटरी से 95 परसैंट, आर0डी0 जीरो से 154 तक 96 परसैंट और आर0डी0 156 से टेल तक 91 परसैंट है। री माडलिंग 1985 में की गई है, इसके बाद सिचुए न ठीक है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, सारी री माडलिंग डिफैक्टिव है क्योंकि स्टेट के हर जिले से इस बात की िाकायत है कि सारी की सारी री माडलिंग डिफैक्टिव है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: बहन जी, री माडलिंग हैड को दोबारा बनाने को कहते हैं। भायद आपका मतलब लाइनिंग से है। मैं आपको बता देता हूं कि दो साल पहले लाइनिंग की थी, इसके बारे में सरकार को िाकायतें मिली थीं, िाकायतें वेरियस लैवल से मिली थीं और हमने लाइनिंग को दोबारा डिजाइन करके, लैवलिंग करके बनाया। माईनर और कैनल की कंस्ट्रक् न का डिजाईन दोबारा ऐग्जामिन करवाया और वाईड स्केल पर हर डिस्ट्रिब्यूटरी और माइनर की रिपोर्ट मंगवाई। कई आफिसर जिन में एस0ई0 लैवल के आदमी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की और जहां डिफैक्टिव लाइनिंग थी, उसको

रैक्टीफाई करवाया। जहां गलती थी उसकी री लाईनिंग करने के उपाय किये गये। कुछ कॅसिज बाकी रहते थे, वे भी क्लीयर हो गये होंगे आगे के लिये स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल एन् टायोर किया जा रहा है और यह आफिसर्ज की जिम्मेदारी है। अगर क्वालिटी और लैवल में कोई गलती हुई तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और इस वक्त ऐसे ही सरकार कर रही है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि इनके पास गिरदावरी की जो फिगरज हैं, उससे यह जाहिर होता है कि इस चैनल में पानी कम नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूँ। लिफ्ट इरीगे टन के ट्रांसफार्मर्ज के कंडक्टर्ज इस किस्म के हैं जो पम्प हाउस को पूरा नहीं चला पाते और और परिणामस्वरूप पम्प हाउस बन्द हो जाता है। जुई, निगाना और सिवानी में ऐसी ही स्थिति है। क्या मंत्री महोदय, उन कंडक्टर्ज को और उस सिस्टम को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे और यदि कोशिश करेंगे तो कब तक करेंगे ?

चौधरी भाम सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, लिफ्ट इरीगे टन में बहुत से ऐसे पावर हाउस हैं जहां जो बिजली घर बिजली सप्लाई करते हैं उनके ट्रांसफार्मर्ज की क्षमता कम है। इस बारे में मैंने मीटिंग की है और जिले के एम0एल0एज0 से भी बात हुई है। हम नारनौल में 220 के0वी0 बिजली घर की कंस्ट्रक् टन कर रहे हैं। मई जून तक वह तैयार हो जाएगा। उसके बाद दादरी

और भिवानी के जितने भी बिजली घर हैं जो लिफ्ट इरीगे इन के लिए बिजली सप्लाई करते हैं उनकी पोजी इन पहले से बेहतर होगी। उम्मीद है कि उसके बाद वे पूरी बिजली सप्लाई कर पाएंगे।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों
के

लिखित उत्तर

Non Payment of Wages to factory labourers

***961 Sh. Devi Dass:** Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state-the names of such factories, in district Sonapat, where the labourers have not been paid their wages or are on strike or on lay off for the last tow months together with the reasons therefor and the number of labourers involved ?

श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री (श्री राजे 1 कुमार): (1)
निम्नलिखित 6 कारखानों के श्रमिकों को अभी तक वित्तीय कठिनाईयों के कारण वेतन नहीं दिया गया है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	प्रभावित श्रमिकों की संख्या
-------------	---------------	--------------------------------

1	मै० कपूर रबड़ प्रा० लि०, सोनीपत	65
2	औरगेनो रबड़ प्रा० लि०, सोनीपत	59
3	औरगेनो केमिकल प्रा० लि०, सोनीपत	23
4	मै० इलैस्टो केम प्रा० लि०, सोनीपत	36
5	मै० एबन स्केल कं०, सोनीपत	67
6	मै० ओम विविंग फैक्ट्री, सोनीपत	106

(2) दिनांक 16-3-85 तक कोई हड़ताल या ले आफ नहीं थी।

Waterlogged and saline Land in the State

***967 Ch. Kundan Lal:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the area of waterlogged and saline land in the State separately;

(b) the area of the canal irrigated land, out of the land, as referred to in part (a) above, as has become water logged; and

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken to reclaim the said lands ?

Interim reply

D.O. No. 7/14/85-IW(1)

“S.S. Surjewala Irrigation & Power Minister,
Govt. of Haryana,
Chandigarh.

March 22, 1985

Dear Sh. Tara Singh Jil,

Kindly refer to Starred Assembly Question No. 967 regarding repairs/overhauling of vehicles in the Irrigation (Drainage) Department asked by Sh. Kundan Lal, M.L.A. which is due for answer on 25-3-1985.

2. In order to supply correct/complete information we require to collect the same from the field officers as also from other concerned Departments. It will take some time. I shall, therefore, be grateful if you kindly allow us 15 days' extension for replying this question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(S.S. Surjewala)

Shri Tara Singh,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.”

**Upgradation of Primary School of Mithi Surera of District
Sirsa**

***980 Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the primary school Mithi Surera in district Sirsa, to Middle School during 1985-86 ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): वर्ष 1985-86 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाने का मामला अभी तक विचारा नहीं गया है। इसलिये प्राथमिक विद्यालय मिठठी सुरेरा जिला सिरसा का स्तर बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठा है।

Advertisement to newspapers etc.

***938 Sh. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state- the criteria, if any, laid for sending Government advertisements for publication in various newspapers/magazines ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को सरकार विज्ञापन देते समय, विभागों तथा सरकारी संस्थाओं की जरूरतों तथा व्यापारिक हितों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही पत्र एवं पत्रिकाओं की सरकूले उन उनके पाठक, विज्ञापन दर तथा अन्य वाजिब तर्कों को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि विज्ञापन देने वाले विभागों और संस्थाओं को उचित एवं प्रतियोगी लागत पर व्यापक प्रचार दिलवाने का मकसद हल हो सके।

Construction of 'Thokars' on Western Bank of Yamuna

***977 Master Ram Singh:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct 'thokars' on the Western bank of river Yamuna before coming rainy season; and

(b) if so, the time by which the siad 'thokars' are likely to be constructed ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला):

(क) नहीं।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

**Supply of Floor mats and furniture to the schools in
district Bhiwani**

***861 Ch.Balvir Singh Grewal:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether there are any schools in district Bhiwani which have not been provided floor mats and furniture as per their requirements; and

(b) if so, the names of such schools togetherwith the time by which the said material is likely to be made available to all such schools ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(क) हां।

(ख) स्कूलों के नामों की सूची अनुबन्ध "ए" के रूप में सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है। फर्नीचर की कमी निकट भविष्य में दूर करने के प्रयत्न किये जाएंगे।

अनुबन्ध "ए"

जिला भिवानी के उच्चतर माध्यमिक/उच्च तथा माध्यमिक विद्यालयों जिनमें फर्नीचर/टाट पट्टी की कमी है, की सूची।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	
1	भिवानी (लड़के)
2	भिवानी (क)
3	चरखी दादरी (ल)
4	चरखी दादरी (क)
5	रानीला
राजकीय उच्च विद्यालय	
1	बड़े सरा
2	बलयाली
3	बामला
4	बामला (क)

5	बापोडा
6	बड़सी
7	बवानी खेड़ा (क)
8	बीरन
9	चांग
10	चांग (क)
11	देवसर
12	धनाना
13	धनाना (क)
14	धनी माहू
15	धारेडू
16	दिनौद
17	गारनपुरा
18	हालूवास
19	ई वरवाल

20	जमालपुर
21	झांवरी-खरखडी
22	कौंट
23	थिलौड
24	तिगड़ाना
25	तो ाम
26	तो ाम (क)
27	किरावड़
28	कितलाना
29	कुंगड़
30	कैला
31	लोहारी जाटू
32	मढाना
33	मानहेरू
34	मिलकपुर नं0 2

35	मिरान
36	मिथातल
37	मुंढाल खुर्द
38	नन्द गांव
39	निमड़ी वाली
40	पालूवास
41	पपोसा
42	पुर
43	रतेरा
44	सरल
45	सुई
46	सै
47	तालू
48	नवा राजगढ़
49	निमली

50	अचीना
51	आदमपुर ढांढी
52	अटैला
53	बिरही कलां
54	चांदवास
55	चंदेनी
56	चांगरोड
57	चरखी
58	चीपर
59	चिडिया
60	चिडिया (क)
61	ढानी फोगाट
62	झोझू कलां (क)
63	झोझू कलां
64	कदमा

65	कल्याण
66	लोहावाडा
67	मिसरी
68	मोडी
69	नन्धा
70	पिचोपा कलां
71	पैटावास कलां
72	रानीला (क)
73	साजरवास
74	सांवड
75	सरपगढ
76	बडवा
77	बडालू
78	बडवास
79	भेरा

80	भजल
81	विधवान
82	बहल
83	बुढेरा
84	चहड कलां
85	दाब ढानी
86	देवराला
87	ढिगवा जाटान
88	दावरका
89	गोलपुरा
90	गिगनऊ
91	गुरेरा
92	झुंपा खुर्द
93	काकरौली सुनारा
94	केरु

95	कैऊई
96	खरखरी
97	लैधा
98	लीलस
99	लोहारू
100	लोहारू (क)
101	मढौली कलां
102	पाडी
103	रोढान
104	मिथि
105	सिवानी मंडी
106	सिवानी मंडी (क)
107	संदवास
108	सोहन सरा
109	गोपालवास

माध्यमिक विद्यालय	
1	अलखपुरा
2	आलमपुर
3	बजीना
4	भुरटाना
5	बापोड़ा (क)
6	दरयापुर
7	ढांग कलां
8	ढांग खुर्द
9	दुर्जनपुर
10	ढानी मिरान
11	दुलहैडी
12	घुसकनी
13	गोला गढ़
14	हेतमपुरा

15	ईसरवाल (क)
16	जमालपुर (क)
17	केहरपुरा
18	कालूवास
19	खानक
20	कितलाना (क)
21	कोहाड
22	लोहाणो
23	लोहारी जाटू (क)
24	मालहेरू (क)
25	मिताथल (क)
26	मढान
27	प्रेम नगर
28	बड़सी (क)
29	सांगरवास (क)

30	राजगढ़
31	रेवाड़ी खेड़ा
32	रिवास
33	रूपगढ़
34	सांगा
35	सांगवान
36	सिवाडा
37	सुंगरपुर
38	तालू (क)
39	तिगड़ाना (क)
40	तिगड़ी
41	आर्यनगर
42	ऊण
43	अचीना (क)
44	बधवाना

45	बलकरा
46	कलरोढ
47	बिगोवां
48	डोहकी हरिया
49	डोहकी
50	गुड़ाना
51	हड़ौदी
52	झिझर
53	कालूवाला
54	खेड़ीबुरा
55	मकडाना
56	मानकवास
57	मोरवाला
58	मालकोस
59	पालड़ी

60	रासीवास
61	रावलधी
62	सांवर (क)
63	भामकलां
64	सिसवाला
65	तिवाला
66	भारीवास
67	बिधनोई
68	भानगढ़
69	चन्दावास
70	छपरा रांगड़ान
71	देवराला (क)
72	ढानी ामा
73	ईन्दीवाली
74	जुई खुर्द (क)

75	कैरू (क)
76	कदमा (क)
77	कलोड़ बुढ़ा
78	लाड़
79	माई खुर्द
80	नकी पुर
81	नौरंगाबाद जाटान
82	नालोई
83	ओबरा
84	पातवान
85	सैहर
86	सिधवना
87	सिधानी
88	धरनवास
89	पैहलादगढ़

90	रोहनात
91	बैहणी खुर्द
92	सौपकासनी
राजकीय प्राथमिक विद्यालय	
1	अलखपुरा
2	विदोला
3	बदलवाला
4	भूशाण
5	बासछपरा
6	बरवा
7	बखातावरपुर
8	चंगाणा
9	खापर जोगिया
10	बागांवाला
11	दमदम

12	ढाणी कटवार
13	ढाणी बलारा
14	ढाणी रिवास
15	ढाणी दरियापुर
16	धारण
17	ढाणी माहू
18	धूलकोट
19	ढाणी रामजस
20	देवसरिया
21	गैन्डावास
22	गारनपुरा
23	हसीन
24	झांवरी खरखड़ी
25	झूली
26	खरखड़ी सोहन

27	कतवार
28	खडियावास
29	खोवा
30	जैनावास
31	कितराला
32	मीरान
33	मनसरवास
34	मोहिला
35	निगाणमलां
36	पटौदी
37	पिन्जोखेड़ा
38	रूपाणा
39	सिवाणी खेड़ा
40	सिम्बली
41	सिधाण

42	सलीमपुर
43	साहलेवाला
44	तो ाम
45	ओरंगनगर
46	बवानी खेड़ा
47	बलयाली
48	बढैसरा (क)
49	बोहल
50	चोरटापुर
51	ढाणी खु ाल
52	ढाणी कै ाला
53	दुजैनपुर
54	जताई
55	खेड़ी दौलतपुर
56	कुंगड़ खेड़ी

57	कुंगड़ (क)
58	जिता खेड़ी
59	मुंढाल कलां
60	मुंढाल (क)
61	पुर (क)
62	रतेरा (क)
63	सुखपुरा
64	सुपाड़
65	सिकन्दरपुर
66	सोमरा खेड़ा
67	भिवानी-1
68	भिवानी-2
69	भिवानी-3
70	वी0टी0एम0 भिवानी
71	बंसी भिवानी

72	बिरवान भिवानी
73	ढाणी मौलियाण
74	ढाणी हनुमान भिवानी
75	गंगा राम जैन भिवानी
76	जौनपाल भिवानी
77	कृष्णा नगर भिवानी
78	लाहड़ भिवानी
79	मांगन भिवानी
80	माडल भिवानी
81	नरसान भिवानी
82	राम नगर भिवानी
83	सरधानन्द भिवानी
84	तैयब भिवानी

85	धिराणा
86	देवसर (क)
87	मालवास देवसर
88	कोहड
89	कुसम्भी
90	दिनोद (क)
91	ढाणी मिरान
92	टिटवाण
93	गोबिन्दपुरा
94	हलुवास
95	ढाणा नरसाण
96	अजीतपुरा
97	नंगल
98	गौरीपुर
99	माधवीर

100	राजपुरा खरखड़ी
101	जितवाणवास
102	उमरावत
103	ढाण लाढनपुर
104	बढ़ाला
105	पुरनपुरा
106	ढाणी भांकर
107	नंगला
108	खौरपुरा
109	पत्थरवाली
110	असलवास मरथ
111	असलवास दुबिया
112	लैहाणा
113	हरिपुर
114	भखडद्या

115	नाथूवास
116	ढाणी सुलेखा
117	हरसुख
118	नौरगांवाद
119	ढाणी नौरगांवाद
120	घोघड़ा
121	खुलपुरा
122	नन्द गांव (क)
123	बिरन (क)
124	हालूवास (क)
125	सांगा (क)
126	लोहाणी (क)
127	ढाणी अहीर
128	ढाणी चांग
129	गुढ़ा

130	देवावास
131	तलवाणी
132	कलई
133	गढ़वा
134	भोहरपुरा
135	नूनसर
136	भोहरयारपुर
137	ढाणी ओबरा
138	बुद्ध भाली
139	घंघाला
140	ढाणी भाखड़ा
141	मोतीपुरा
142	सैणीवास
143	सैणीवास (क)
144	चैहड़ कलां (क)

145	चैहड़ खुर्द
146	सेहरला
147	निनाण
148	हरियावास
149	ढाणी केहर
150	खापर वास
151	लारियावाली
152	बिजलाणावास
153	ढांगढ़
154	लैहंगा
155	मोरखा
156	गढ़वा
157	मंदौली खुर्द
158	मताणी
159	सिवाच

160	सुरपुरा कलां
161	सुरपूरा खुर्दग
162	सिदधीवास
163	सिरसीवास
164	पाजू
165	नंगला
166	सोहरड़ा जदीद
167	सोहरड़ा कदम
168	कासणी कलां
169	कासणी खुर्द
170	गोकुलपुरा
171	पटवाण (क)
172	बिसरवास
173	ढाणी रहीमपुर
174	गोपालवास

175	ढाणी टोड़ा
176	ढाणी मनसुख
177	लोहारू
178	सोहंसरा (क)
179	फडतियातल
180	फरटीया भीमा
181	फरटीया केहर
182	ढाणी ढोला
183	समसावास
184	गोथरा
185	कु लपुरा
186	दमकोरा
187	झांझरा भोरों
188	झांझरा टोड़ा
189	झंपा कलां

190	हसनपुर
191	खरखड़ी (क)
192	अलाऊदीनपुर
193	ढाणी लछमन
194	ढाणी पुरन
195	बड़दूचैना
196	बलदूमुगल
197	किसकन्दा
198	जेवली
199	हांसावास कलां
200	हांसावास खुर्द
201	रुदरौल
202	ऊण
203	नौरगांवास ठाकरान
204	डगरौली

205	बदराल
206	ढाणी खूबी
207	कनहेरा
208	रामलवास
209	गोकुल
210	बुझेहरी
211	ढाणी गुजरान
212	वरदू जोगी
213	बिठाण
214	वैहरान
215	दिगया सामयान
216	जुई कलां
217	कुरैल अवास
218	पोखरवास
219	वाहमणीवाली

220	लालावास
221	लाढावास
222	मानपुरा
223	ढाणी जोगी
224	ढाणी गोरखा
225	खोरदा
226	भढवा
227	गोबिन्दपुरा
228	बढवास (क)
229	बढेसरा
230	धनासरी
231	ढाणी सुरजगढ
232	बिसलवास (क)
233	भागेसुरी
234	वासरानिला

235	कानहेटी
236	निमली (क)
237	बाँद खुर्द
238	रनकौली
239	निमड़ी
240	सन्तरोड़
241	फोगट
242	मालकोस (क)
243	ऊण (क)
244	हिन्डौल
245	सौंफ
246	कोहलावास
247	लाम्बा
248	मकराणी
249	गोठता

250	सन्तोखपुरा
251	दातोली
252	चांगरोड़ (क)
253	बालरोड़ (क)
254	मानोवली
255	ढाढी छिलर
256	कल्याणा
257	कलाली
258	झोझी खुर्द
259	मयरा
260	बलाली
261	बादल
262	असावड़ी
263	रामवास
264	निहालगढ़

265	कुवज नगर
266	टोटी नगर
267	वजीणा
268	बदवाणा गेट
269	भैरवी
270	विदध भैरवी
271	चरखी (क)
272	ढाणी रावलधी
273	ढाणी फोगट (क)
274	गतेहगढ़
275	धिकारा
276	हरजन आक्षम
277	जै श्री
278	कम्बोद
279	खातीवास

280	खेड़ी सावल
281	मिर्च
282	मिसरी (क)
283	मैहरान
284	पातूवास
285	राम नगर
286	साहूवास
287	पटवास खुर्द
288	अखितयारपुरा
289	झरवई
290	चापड़ा
291	नरसिंहवास
292	संतागपुर
293	पांढवाण
294	खेड़ी वतार

295	बरसाणा
296	अटेला कलां
297	बिलावल
298	विन्दरावन
299	हड़ौदा खुर्द
300	हड़ौदा कलां
301	मंडी आर्य
302	मंडी केहर
303	पिचौपा कलां
304	मंडी पराणु
305	बेरला
306	हुई
307	जगरामवास
308	काकरोला हटी
309	गोती

310	काकरोली
311	जीतपुरा
312	पचगांव
313	ऊनावास
314	भाड़ीवास
315	लाड़ावास
316	कड़ी ढाढरनी
317	कड़ी दास
318	कड़ी तोखा
319	कड़ी मोढ़
320	ददमा
321	भोपाली
322	कड़ी आदू
323	सिरसा
324	दुदीवाला

24-3-1985 को चण्डीगढ़ में हत्या किए गए व्यक्तियों के

परिवारों को संवेदना संदे ।

15.00 बजे ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, बड़े दुःख से मुझे सदन में एक बात कहनी पड रही है। कल भाम को 19 सैक्टर में हमारी पार्टी के चण्डीगढ़ भाखा के उप प्रधान श्री कृष्ण लाल मनचन्दा को दो उग्रवादियों ने उनके घर पर दस्तक देकर और उनके बाहर आने पर गोलियों से भून दिया और रात को वे गोलियों के घाव की वजह से दुनियां को छोड़ कर चले गए। वे एक नौजवान थे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और सारा परिवार उन पर निर्भर करता था। साहब, उग्रवाद की इस सारे क्षेत्र में ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जिससे कई सरकारों को सुलटना पड रहा है। केन्द्रीय सरकार भी बहुत चिन्तित है। तो मेरी अर्ज है कि जो निर्दोश व्यक्ति मारा गया है और इन कारणों से मारा गया है कि वह भायद उग्रवादियों के मन के मुताबिक काम नहीं करता होगा, उसके संबंध में मैं औबचुअरी रैफरेंस देना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मैं लीडर आफ दी हाउस से कहना चाहूंगा कि वे मेरी बात को मान जाएं। मैं दूसरे ग्रुप्स के नेताओं से भी प्रार्थना करूंगा के वे भी मेरे सुझाव से सहमत हों ताकि हम भाोक प्रस्ताव पास कर सकें, दो मिनट का मौन धारण कर सकें और उस भाोक प्रस्ताव

को भाोक संतप्त परिवार को भेज सकें क्योंकि इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जो बात डाक्टर साहब ने की, उसका दुःख सबको है। हमें भी बडा भारी दुःख है लेकिन ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि इस तरह का प्रस्ताव यहां लाया जाए। (विधन) डा० साहब जितना दुःख आपको है उतना ही हमें भी है। हम दुःख में भामिल होते हैं। इस तरह का प्रस्ताव लाने से एक नई प्रथा पड़ जाएगी और उससे हमारे लिए बडी मुक्ति हमें पा के लिए खडी जो जाएगी। फिर भी स्पीकर साहब, यदि ठीक समझें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, अखबार की खबरों के अनुसार तो एक मखन सिंह नाम का लडका भी मारा गया है।

चौधरी भजन लाल: जी हां, वह यूनिवर्सिटी के स्टुडेंट्स का ऐक्स लीडर था।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, बडे दुःख की बात है कि इस तरह की घटनाएं दुबारा से भुरू हो गई हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि डा० मंगल सेन जी ने जो बात कही है वह मंजूर की जाए क्योंकि लोगों की भावनाओं को ही हम व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव डा० मंगल सेन जी ने रखा है उसके बारे में वैसे तो लीडर आफ दी हाउस ने

ठीक ही फरमाया कि हमारी प्रथा एम0पीज0 और एम0एल0एज0 आदि को ही औबिचुअरी रैफरेंस देने की रही है। लेकिन आजकल का वातावरण है, उसके हिसाब से इस औगस्ट हाउस की यह फललिंग है कि इसका अच्छा ही असर होगा। इसलिए मैं भी आपसे गुजारि ा करूंगा कि इस केस में हमें औबिचुअरी रैफरेंस देना चाहिए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, सबको बडी संवेदना है लेकिन सवाल भावुकता का नहीं है। हाउस चलाने के कुछ कायदे और नियम होते हैं। यह ठीक है कि इनका जो साथी मरा है वह बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। उनके निधन का उनके परिवार को सबसे बडा दुःख हो सकता है कुछ और लोगों को भी बहुत दुःख हो सकता है लेकिन इस हाउस में औबिचुअरी रैफरेंस केवल एक क्लास, एक कैटगरी के लोगों को देने का तरीका बना हुआ है। यह तरीका आज से नहीं बल्कि जब से असैम्बलीज और पार्लियामेंट बनी हुई हैं तब से हैं। अगर सारी बातों को खत्म करके, पुरानी मर्यादा को तोड़ कर हम नई बात भुरू करते हैं तो उसका अन्त नहीं होगा। हमारा दे ा बहुत बडा है। यहां रोज ब रोज कोई न कोई घटना होती रहती है। कभी रेल ऐक्सीडेंट, कभी बस ऐक्सीडेंट और कभी इस तरह की दुर्घटना। मेरी बस बात से ये यह न सोचें कि ट्रेजरी बैंचिज को इस दुर्घटना का दुःख नहीं है। हमें पूरी संवेदना है लेकिन हाउस की कार्यवाही

चलाने में भावुकता की कोई गुंजाइ 1 नहीं होनी चाहिए और हमें कोई नई प्रथा नहीं डालनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे मनचन्दा जी के गुजर जाने का काफी दुःख है। मखन सिंह तो मेरी बिरादरी का था। वह मेरे बडा क्लोज था। 32 गांलियां उसको लगी हैं। बाप उसका पैरालीसिज के अटैक से बिस्तर पर पडा था। कहते हैं कि जिस वक्त उसने यह बात सुनी उसकी आंखें उल्ट गईं भायद वह भी चलाना कर जाए। दुःख तो हम सबको है, आपको भी है और मुझे भी है लेकिन जैसा सुरजेवाला जी ने कहा मैं भी रूल्ज का पाबन्द हूं। मेरा ख्याल है कि सारा हाउस सहमत होगा कि इस बारे में जितना हम कह चुके हैं हमारी जितनी फीलिंग्ज रिकार्ड पर आ गई हैं, उतना ही काफी है।

श्री मंगल सैन: उनको करवे कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कनवे कर देंगे।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा—

स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के भाोक प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री के उत्तर संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, on behalf of the whole House. I sent a condolence message to Sh. Rajiv Gandhi, Prime Minister of India, in respect of Late Smt. Indira Gandhi, our illustrious Prime Minister.

I have received a letter from Sh. Rajiv Gandhi, Prime Minister of India dated 20th March, 1985 which reads-

“Thank you for your letter of 11th March, 1985. Please convey to the Members of the Haryana Vidhan Sabha my appreciation of thier gesture in honour of Smt. Indira Gandhi. I value their sympathy and yours.”

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

रोहतक में पेयजल के संकट संबंधी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे दो काल अटैं उन मो अन्ज सर्वश्री ओम प्रका 1 (बेरी) और डा0 मंगल सैन की ओर से रोहतक में ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस के बारे में मिले हैं। I have admitted both these motions. श्री ओम प्रका 1 जी अपना मो उन पढ़ दें। The other motion will be deemed to have been read.

चौधरी ओम प्रका 1: स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से रोहतक भाहर में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है और यदि यही हालत रहे और पीने के पानी की सप्लाई में पूरा सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दो तीन दिनों में स्थिति बहुत ही गम्भीर हो जाएगी। अब रोहतक भाहर के निवासियों को पीने के पानी की सप्लाई केवल

एक घंटे के लिए की जाती है जो बिल्कुल अपर्याप्त है। इस स्थिति से लोग अत्यन्त परेशान व बेचैन हैं।

इसी तरह से झज्जर भाहर में भी पर्याप्त रूप से पीने का पानी सप्लाई नहीं किया जाता है और जो पानी सप्लाई किया जाता है वह पीने के काबिल नहीं है क्योंकि यह पानी न तो कलोरीनेट किया जाता है और न ही पूरी तरह से फिल्टर किया जाता है और इस पानी में एक ट्यूबवैल का कड़वा पानी भी मिला दिया जाता है जो ट्यूबवैल वाटर वर्कस पर नगरपालिका झज्जर ने लगा रखा है। इस ट्यूबवैल का पानी आदमी की तो बात क्या, पशुओं के भी पीने के काबिल नहीं है। हालात यहां तक खराब हैं कि कई बार तो अकेले इसी ट्यूबवैल का पानी सीधे तौर पर लोगों के पीने के लिये सप्लाई कर दिया जाता है। ऐसा घटिया पानी पीने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। पीने के पानी की सप्लाई झज्जर भाहर के एक तिहाई भाग में तो कतई पहुंचती ही नहीं है। पीने के पानी से वंचित रहने वाले लोग दिल्ली गेट, सिलानी गेट, दिवान गेट, पन्सारी मोहल्ला, गोसियान मोहल्ला तथा साथ लगते दूसरे मोहल्लों में रहते हैं। झज्जर भाहर में ग्रांडड वाटर मीठा नहीं है। इस कारण से समस्या और भी विकट है। घटिया पानी पीने से अनेक बीमारियां फैलने की आशंका है और यह नागरिकों के साथ सरासर अन्याय व भेदभाजक है। यह एक अत्यावश्यक लोक महत्व का विषय है और

इस बारे में जन स्वास्थ्य मंत्री को सदन में एक वक्तव्य देने के लिये कहा जाये ।

श्री मंगल सैन: इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि रोहतक भाहर में विगत पांच दिनों से पीने के पानी की सप्लाई न होने के कारण दो लाख की आबादी में हाहाकार मच गई है। एक कटोरी पानी भी दिन भर में पीने का नगरपालिका के नलों में नहीं आता। नगरपालिका के अधिकारियों के अपराधपूर्ण रवैये के कारण रोहतक भाहर की जनता प्यासी मर रही है। नगरपालिका ने जो पीने का पानी नहर विभाग से लेकर सप्लाई करना चाहिए था, वह नहीं किया तथा इस कारण यह पानी का अभाव बन गया है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कृपया सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इस स्थिति पर कैसे और कब तक काबू पाएंगे।

वक्तव्य—

लोक स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव सम्बंधी

श्री अध्यक्ष: आप कब तक जवाब दे देंगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): अभी दे देती हूं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप इजाजत दे दें तो मैं अपना काल अटैं इन नोटिस पढ दूं।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आपका काल अटैं इन नोटिस भी रोहतक में पीने के पानी की समस्या के बारे में हैं। मैंने तीन तीन, चार चार काल अटैं इन नोटिसिज को इकटठा किया हुआ है। अगर आपको पढने की इजाजत दे दूं तो दूसरे मैम्बरान एतराज करेंगे और कहेंगे कि उन्हें भी नोटिस पढने की इजाजत होनी चाहिये। ऐसा करने से मेरे लिये थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जायेगी इसलिये आप सवाल पूछ लेना।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): स्पीकर साहब, इससे पूर्व कि मैं सदन में रोहतक तथा झज्जर भाहरों में पेयजल की स्थिति के बारे में वक्तव्य दूं, मैं सदन को यह सूचित करना चाहती हूं कि सरकार स्थिति के बारे में पूरी तरह सजग है तथा पेयजल की सप्लाई पूरी मात्रा में तथा समय पर करने के लिये आव यक कदम उठा रही है जो कि हमारी पहुंच के बाहर न हों।

1. रोहतक भाहर

रोहतक भाहर को दो जलघरों से, जिनका नाम पुराना जलघर तथा दूसरा जलघर है, से पानी दिया जा रहा है। पुराने जलघर से जो कि नगरपालिका द्वारा मेनटेन किया जा रहा है। रोजाना 22 लाख गैलन पानी दिया जाता है तथा दूसरे जलघर से

जो कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेनटेन किया जाता है, 11 लाख गैलन प्रतिदिन पानी दिया जाता है। इस तरह 180000 की जनसंख्या को 18 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी दिया जाता है। पानी की सतह ऊपर उठने तथा जमीन में नमी होने के कारण पुराने जलघर की क्षमता अब 10 दिन की है जिससे 22 लाख गैलन पानी प्रति दिन दिया जाता है और दूसरे जलघर की क्षमता 21 दिन है जिससे 11 लाख गैलन प्रतिदिन दिया जाता है। पहले सिंचाई विभाग द्वारा नगरपालिका जलघर को नहर का पानी बन्द समय में भी दिया जाता था ताकि जलघर की क्षमता में कमी की पूर्ति की जा सके। यह सुविधा पिछले एक साल से कम हो गई तथा 10-3-85 से नहरी सिस्टम से सप्लाई कम होने के कारण बन्द हो गई।

भालोट सब ब्रांच का फीडिंग चैनल का बंद रहना, 25-2-1985 से भुरू हो गया है। यह मालूम हुआ है कि यह अब 24 दिन रहेगा। इस कारण पानी की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी गई थी ? फिर भी 25-2-85 तक मिलता रहा। उसके बाद यह बिल्कुल बंद हो गया। भाहर में जल संकट बचाने के लिये दोनों जलघरों से पानी नियमित मात्रा में देना भुरू कर दिया गया है। दिनांक 9-3-85 को पानी की सप्लाई 26 लाख गैलन प्रतिदिन थी और धीरे धीरे 15 लाख गैलन प्रतिदिन, दिनांक 18-3-85 से हो गई जो कि 8 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन के बराबर है। यह कम

मात्रा फिर भी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करती है।

भाहर को तीन भागों में बांटा गया और पिछले कुछ दिनों से पानी एक घण्टा प्रति दिन दिया गया। रोहतक में और स्रोत नहीं है जिसके साथ पानी की सप्लाई में वृद्धि हो सके। कुछ स्थानों पर पानी टैंकरों द्वारा भी दिया जाता है।

नहर के पानी की सप्लाई 21-3-85 को रोहतक पहुंच गई है और जैसे सप्लाई बढ़ती है पीने के पानी की व्यवस्था सुधरेगी।

नहर बंद रहने का अगला समय भी 24 दिन का होगा। 3 से 4 दिन की अन्य सुरक्षित गुंजाइश के लिये जल वितरण को उस मात्रा में रखा जायेगा ताकि भाहर को नहर के चालू होने तक पेयजल सुविधा प्रदान की जा सके।

इस भाहर को कम से कम औसतन पेयजल सुविधा 10 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन सम्भव हो सकेगी। समस्यायुक्त क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये पानी के टैंकरों को नियमित तौर पर लगाया जाना जारी रखा जाएगा।

इसमें संदेह नहीं कि रोहतक भाहर की पेयजल वितरण प्रणाली कठिन है लेकिन यह निश्चित किया जा रहा है कि पेयजल सुविधा सभी क्षेत्रों में उपलब्ध हो।

2. झज्जर भाहर

झज्जर भाहर को दो जलघरों से पानी दिया जा रहा है, जिनका नाम नगरपालिका जलघर, जिसकी नगरपालिका स्वयं अनुरक्षण करती है तथा दूसरा मंडीकरण बोर्ड जलघर है, जिसका अनुरक्षण जल स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है।

नगरपालिका का जलघर जो कि नहरी पानी पर आधारित है, से अधिकतर जल दिया जाता है। जलघर की सीमा के अंदर लगे दो नलकूपों से पानी की सप्लाई की मात्रा बढ़ाई जा रही है। नहरी पानी के भण्डार टैंकों की 1.9 लाख गैलन प्रति दिन देने की, 21 दिन की क्षमता है। नलकूप 70 हजार गैलन प्रति दिन पानी सप्लाई करते हैं। अतः पानी की कुल सप्लाई 2.6 लाख गैलन प्रतिदिन है।

मण्डीकरण बोर्ड जलघर, सब्जी तथा अनाज मंडी के लिये है। क्योंकि अभी इस मंडी का विकास नहीं हुआ है। इसलिये भाहर के कुछ भाग के लिये 50 हजार गैलन पानी प्रतिदिन इस्तेमाल किया जा रहा है।

पानी की कुल सप्लाई 3.1 लाख गैलन प्रति दिन निकाली गई है जिससे कि 26000 की जनसंख्या को औसतन 12 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सप्लाई किया जा रहा है।

सिंचाई विभाग ने 24-2-85 से अधिक समय तक नहर के पानी को बंद कराने की घोशणा की है। हालांकि पानी 24 दिन

के लिये बंद होने की घोशणा की गई है फिर भी यह कम से कम 2 दिन और लग जाते हैं क्योंकि पानी का लम्बा सफर है।

नहर के पानी का भण्डार सीमित होने के कारण नगरपालिका जलघर में नहर का पानी 15-3-85 को खत्म हो गया। इस तिथि के बाद नगरपालिका के जलघर के ट्यूबवैल से पानी की मात्रा कम हो कर 70 हजार गैलन प्रतिदिन रह गई तथा मण्डीकरण बोर्ड जलघर से 50,000 गैलन प्रतिदिन पानी मिलता है। यह कुल सप्लाई लगभग 4.7 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आज तक की जा रही है।

नहरी पानी को फिल्टर तथा क्लोरीनेट किया जाता है जबकि नलकूप के पानी को केवल क्लोरीनेट किया जाता है। नगरपालिका जलघर पर आम हालात में ट्यूबवैल का पानी नहर के पानी में मिला कर सप्लाई किया जाता है। नलकूप का पानी खारा है परन्तु जब नहरी पानी में मिला दिया जाये तब ये खारापन महसूस नहीं होता।

भाहर के 75 प्रति ात भाग को नगरपालिका के जलघर से पानी दिया जाता है बाकी हिस्सों को मण्डीकरण बोर्ड जलघर से पानी दिया जाता है। 15-3-85 के बाद भाहर के अधिकां ा भाग को नलकूप का पानी क्लोरीनेट कर के दिया जा रहा है तथा बाकी के भागों को जहां मण्डीकरण बोर्ड के जलघर से सप्लाई होती है नहर का पानी पूरी तरह छान कर तथा क्लोरीनेट करके

दिया जाता है। पानी की क्वालिटी ऐसी नहीं है जो कि पीने के काबिल न हो। चाहे वर्तमान पानी की सप्लाई 4.7 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, फिर भी बराबर वितरण किया जा रहा है। केवल दो क्षेत्रों दीवान गेट तथा पन्सारी मोहल्ला, जो कि ऊपरी स्तर पर है, में पानी की स्थिति प्रायः कठिन है। इन क्षेत्रों की आबादी 3000 है। दूसरे क्षेत्र दिल्ली गेट, सिलानी गेट तथा गोसाइयां मोहल्ला भाहर के अन्य भागों के साथ पानी प्राप्त कर रहे हैं।

नलकूप का पानी खारा है परन्तु यह खारापन बहुम क म हो जाता है जब इसको भाहर के पानी में मिला दिया जाये और फिर यह निर्धारित मिकदार में होता है। नलकूप के पानी की वर्तमान क्वालिटी जो कि सीमित समय में सप्लाई होता है इतनी सचेतक नहीं है जो कि सेहत के लिये हानिकारक होगी।

सिंचाई विभाग अधिकारियों ने सूचित किया है कि नहरी पानी का बहाव 20-3-85 की रात से भारु हो गया है और यह झज्जर क्षेत्र 22/23-3-85 को पहुंच जायेगा।

नहर के बन्द रहने के अगले समय में नहर के पानी की सप्लाई ऐसे निर्धारित की जायेगी ताकि नहर के चालू होने के समय तक चल सके। औसतन सप्लाई 10 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रखी जायेगी। नलकूप के पानी को नहर के पानी में ऐसी मात्रा में मिलाया जायेगा ताकि यह पीने के लिये बिल्कुल ठीक

हो। समस्यायुक्त क्षेत्रों में खासतौर पर पानी की सप्लाई मोबाईल टैंकरों से की जायेगी।

चौधरी ओम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में जो कुछ कहा है, उससे कई सवाल पैदा होते हैं। इन्होंने कहा है कि अब 4.7 गैलन पर हैड के हिसाब से हर रोज पानी दिया जा रहा है। सवाल नं० 860 में दिये गये जवाब के मुताबिक जो पर कैपिटा पानी के रेटस तय किये हुए हैं, उनके मुताबिक जहां पापुले 10 हजार से 50 हजार तक हो, वहां पर 90 से 100 लीटर पर कैपिटा तक पर डे पानी दिया जाता है। मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि एक आदमी को कम से कम निरन्तर अ योर्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल सके, उसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है और आईन्दा भी उनको यह वाटर सप्लाई मिलती रहे, इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, वेसे तो मैंने डिटेल में जवाब में बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं यह अर्ज कर दूं कि नहर के पानी की कमी के कारण पीने के पानी की समस्या के बारे में सारे हाउस को पूरी तरह से ज्ञान है। भाखड़ा में पानी का स्टोरेज बरि 1 न होने की वजह से बहुत कम हो गया है। इसलिये कुछ न कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। अगर किसी प्रदे 1 में या दे 1 में किसी चीज की कमी होती है तो हमें थोडे में भी गुजारा करना पड़ेगा। एक टाईम ऐसा था कि हमारे प्रदे 1 में

लोग पानी रेलों और ऊंटों पर भी बड़ी दूर दूर से लाया करते थे। अब जबकि मजबूरी की हालत है, तब हमें कम पानी से ही गुजारा करना पड़ेगा।

चौधरी ओम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि झज्जर में कुछ इलाके हैं जैसे दीवान गेट और पन्सारी मोहल्ला आदि जो ऊंचे हैं। 50 हजार गैलन पानी मार्किटिंग बोर्ड के जलघर से सप्लाई होता है क्योंकि वहां पर अनाज मंडी और सब्जी मंडी पूरी तरह नहीं बनी है। अभी वहां पर मंडी बनाई जा रही है, इसलिये इन दो क्षेत्रों को पीने का पानी मिल रहा है। जब यह मंडी बन जायेगी, क्या उसके बाद भी इन इलाकों को इस जलघर से पानी मिलना जारी रहेगा या सरकार कोई अन्य इन्तजाम करेगी? अगर कोई अन्य इन्तजाम करने का प्रोग्राम है तो क्या इसके लिये दूसरे वाटरवर्क्स बनाने का कोई विचार सरकार कर रही है या जो प्रैजेन्ट वाटर वर्क्स म्युनिसिपल कमेटी का है उसको बढा कर ही कोई इन्तजाम किया जायेगा ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, पानी की समस्या हमें तो ऐसी रहेगी नहीं, वर्षा भी होगी। कुदरत भी इंसान का साथ देती है। ऐसी बात नहीं है कि पानी का कोई इन्तजाम ही नहीं किया जायेगा। सरकार को कुछ न कुछ साधन तो ढूँढने पड़ेंगे। इस इलाके को पानी देने के लिये कुछ न कुछ इन्तजाम अवश्य किया जायेगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आदरणीय बहिन जी ने हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते समय बड़ी उदारतापूर्वक यह कहा है कि पानी की सप्लाई करना सरकार का काम है और पानी की सप्लाई के बारे में चिन्ता न करें, आ वास्त रहें। स्पीकर साहब, मैं उनके भावों को दोहराते हुए कि लोगों को पीने का पानी देना सरकार की एक पायस ड्यूटी है ताकि लोग पानी के लिये तड़पते न रहें उनसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। रोहतक भाहर में दो वाटर वर्क्स हैं, एक पुराना है और एक नया बनाया गया है। आबादी के हिसाब से दोनों वाटर वर्क्स भी रोहतक के लिये नाकाफी हैं। क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि मिनिमम कितना पानी रोहतक भाहर में मिलता रहेगा ? मैं बहिन जी से यह भी जानना चाहूंगा कि कितना अ योर्ड पानी रोहतक को दिया जायेगा ? रा वाटर का चूंकि वहां पर कोई बडा स्टोरेज टैंक नहीं है जहां पर कि पानी को ज्यादा देर तक के लिये स्टोर किया जा सके, हम यह भी चाहते हैं कि इसके लिये भी कोई न कोई प्रबन्ध भीघ्र ही किया जाये। स्पीकर साहब, म्युनिस्पल कमेटी का मामला है और सरदार प्यारा सिंह जी कान्फीडेंस में भी नहीं लिये जा रहे हैं। वह बेचारे मेरी तरफ देख रहे हैं और मेरे सवाल की ताईद में सिर भी हिला रहे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगर पालिका का जो स्टोरेज टैंक है, इसकी कैपेसिटी बढ़ायें। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि अगर इनका ऐसा कोई प्रोग्राम है तो यह बतायें कि इसके लिये कितना पैसा लगेगा ? क्या यह इस काम को जल्दी ही करेंगे ? रोहतक की आबादी 2

लाख के लगभग है। पहले जब यह टैंक बना था, उस समय रोहतक की आबादी 30,000 थी। अब चूंकि गांव से लोग भाहर में आ गये हैं और इसकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, क्या इसके लिए और टैंक बनाने का भी प्रोग्राम है ? सब जगह पीने का पानी नैसैसिटी आफ लाईफ है। पीने के लिये, नहाने के लिये और कई अन्य कामों के लिये पानी आव यक है। मैं यह 4-5 बातों पर मंत्री महोदया से रोानी डलवाना चाहूंगा क्योंकि इनका अपना मकान भी रोहतक में ही है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, दो स्कीमें रोहतक भाहर के लिये सोची गयी है। एक तो दोनों वाटर वर्क्स को मिलाने के लिये है, उसके लिये 22 लाख रूपये का ऐस्टीमैट बन गया है। इन दोनों टैंकों को, जिनकी क्षमता क्रम 1: 21 दिन और 10 दिन की है, मिलाने की हमारी स्कीम है। जैसे ही बजट पास होता है और हमें पैसा मिलेगा, हमें वैसे ही उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में ही, इस स्कीम पर काम भुरू कर देंगे। डाक्टर साहब ने एक और वाटर टैंक बनाने की बात कही है। उसके लिये हमारे अधिकारी एक दूसरी स्कीम बनाकर बम्बई देकर आये हैं और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि इसी साल यानी 1985-86 के बीच में ही वह ऋण हमें मिल जायेगा। रोहतक के लिये पानी बढ़ाने का हम काम जल्दी ही भुरू कर देंगे जिससे कि वाटर टैंक्स की कैपैसिटी बढ़ जायेगी।

श्रीमती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने यह तो माना है कि झज्जर में खारा पानी हैं इन्होंने यह भी कहा है कि वह इतना खारा नहीं है कि उसे इस्तेमाल ही न किया जा सके। स्पीकर साहब, बनारसी दास जी भी यहां बैठे हुए हैं। वह बोलते नहीं हैं। चाय बनाते हैं तो चाय फट जाती है, दाल बनाते हैं तो दाल ठीक नहीं बनती और जो भी काम उस पानी से करते हैं, वह ठीक नहीं होता। मेरी मंत्री महोदया से यह रिक्वेस्ट है कि वह इसके लिये कुछ करें।

श्री अध्यक्ष: आपके हल्के की बात ओम प्रकाश जी ने कर दी है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

चौधरी ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मैं स्लैक कोल के 19 रैक्स की माल डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में आपको एक काल अटेंशन मोड दे रखा है उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष: मैंने गवर्नमेंट से कमेंट्स मांग रखे हैं।

चौधरी ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटेंशन मोड भिवानी, रोहतक और जीन्द डिस्ट्रिक्ट में गेहूं और चने की फसल पानी और बिजली की कमी की वजह से बरबाद होने के बारे में था, उसका क्या बना है ?

श्री अध्यक्ष: वह मैंने 27 तारीख के लिये ऐडमिट कर लिया है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, जींद में फर्टीलाईजर पर जो सबसिडी दी जा रही है, उसमें बहुत घपला हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने डिस अलाउ कर दिया है

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं इन मो इन महेन्द्रगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में आपकी सेवा में दिया था उसका जवाब मुझे मिल गया है लेकिन मैं उसके बारे में एक दरखास्त करना चाहता हूँ। मेरे पास वहां की फोटो है। आप खुद देख सकते हैं कि वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: जो मैंने फ़ैसला कर दिया है, उसके ऊपर कृपया यहां बात न करें। वह मैंने डिस अलाऊ कर दिया है।

श्री राम बिलास भार्मा: सर, यह लिखा है कि कूड़ा उठा लिया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगर कोई बात है तो आप मुझसे चैम्बर में मिल लेना।

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं इन मो इन बहुत ही गरीब आदमियों के लिये दिया था कि सफाई मजदूरों को भी पैं इन दी जाये ।

श्री अध्यक्ष: वह तो डिस अलाऊ हो गया है । (व्यवधान व भाोर)

श्री मनफूल सिंह: उसी के बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब मिल गया होगा । (व्यवधान व भाोर)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैंने क्वै चन पेपर्ज में इररैगुलैरिटीज और मास कापिंग के बारे में एक काल अटैं इन मो इन दिया थ । उसका क्या बना है ?

श्री अध्यक्ष: मैंने गवर्नमेंट से कमेंटस मांगे हुए हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने भी कुछ काल अटैं इन मो ांज भिजवाये थे ।

श्री अध्यक्ष: कब भिजवाये थे ?

श्रीमती चन्द्रावती: आज ही भिजवाये हैं ।

श्री अध्यक्ष: अभी वे मिले नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, आई0आर0डी0 प्रोग्राम के तहत लड़कियों के लिए क्राफ्ट सैन्टर्ज खुल हुए हैं। मेरे पास एक दरखास्त आई जिसमें लिखा है कि गवर्नमेंट उनको बंद करने जा रही है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप गवर्नमेंट को कहें कि वह इन लड़कियों के सैन्टर्ज को बन्द न करें।

श्री अध्यक्ष: ऐसी दरखास्त या कोई नोटिस अभी मुझे नहीं मिला है। आप बैठिए।

वर्ष 1985-86 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now we resume discussion on the budget Sh. Lachhman Singh.

Sh. Lachhman Singh (Kalka): Thank you Mr. Speaker;

स्पीकर साहब, इसी महीने की बीस तारीखको फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पे 1 किया उसके ऊपर मैं अपने ख्यालात जाहिर करना चाहता हूँ और वहीं से भुरु करूंगा जहां से फाइनेंस मिनिस्टर ने भुरु किया था। 31 अक्टूबर का दिन न सिर्फ हिन्दुस्तान की हिस्टरी में ही स्याह दिन है बलिव यह दिन दुनियां की हिस्टरी में भी काला दिन है लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दे 1 के अंदर जो वाक्यात हुए वे हम सभी के दिलों को हिला देने वाले हैं। इस बारे में काफी जिक्र हो चुका है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा।

स्पीकर साहब, हरियाणा भी उस आग की लपेट से नहीं बच सका। आज इस बारे में एक सवाल था और उसके बारे में यह कह दिया गया कि इस बारे में इंफरमे इन देना जनहित में नहीं है। स्पीकर साहब, करोड़ों रूपए का नुकसान हुआ और पैंतालीस लाख रूपए के करीब का लूटा हुआ माल बरामद हुआ और 286 आदमी पकड़े गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे छोड़ दिए गए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि कम से कम स्पे टाल कोर्ट्स बनाकर उन आदमियों को सजा मिलनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो स्पे टाल कोर्ट्स कायम करके उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने दिन दिहाड़े बेकसूर लोगों का माल लूटा और करीब 125 आदमियों को मारा। वे लोग भाहरों, कस्बों और गांवों के रहने वाले थे। मेरी तो चीफ मिनिस्टर साहब से यही दरखास्त है कि स्पे टाल कोर्ट्स के थू उनको सजा देनी चाहिए। स्पीकर साहब, जिस तरह से पंजाब में हुआ उसी तरह से ये भी बेगुनाह लोग थे। उनका कोई कसूर नहीं था। वे लोग राजस्थान से आ रहे थे और इन ट्रांजिट मारे गए। 19 गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचाया गया। मैं चाहता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब के दिल में जरा भी उन लोगों के प्रति और उन गुरुद्वारों के प्रति दर्द है तो उनको जो मुआवजा दिया गया क्या वे पता करेंगे कि जो कुछ दिया गया है वह सही मिला है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे हाउस में यह बता बताएंगे या वे मुझे पर्सनली बताएंगे।

स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हाउस में बजट पे 1 किया है, अब मैं उसके मुताल्लिक कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। बडी ऐस्केलेटिड फिगर्ज फाइनेंस मिनिस्टर ने हाउस में पे 1 की हैं। इसमें कोई भाक नहीं है कि वे एक इंटैलीजेंट आदमी हैं। स्पीकर साहब, इन्होंने 114.32 करोड रूपए का बजट में घाटा दिखाया है। और उसको पूरा करने के बारे में बताया है कि सत्तर करोड रूपया तो एस0वाई0एल0 कैनाल के लिये मिल जाएगा और पैंतालीस करोड रूपया कंसाइनमेंट गुडज जिसके बारे में भारत सरकार ने अभी कानून नहीं बनाया है उससे मिल जाएगा। स्पीकर साहब, 1981 से यानी दो तीन साल से एस0वाई0एल0 का काम चल रहा है और हरियाणा सरकार ने चालीस करोड रूपया दिया है तो फिर कौन सी वजह है कि भारत सरकार अब सत्तर करोड रूपया देगी। स्पीकर साहब, जहां तक कंसाइनमेंट टैक्स की बात है वह तो सेंट्रल सेल्ज टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हरियाणा सरकार को कुछ पैसा नहीं मिलेगा और यह जो 114.32 करोड का घाटा है यह 225 करोड रूपए का घाटा हो जाएगा जिससे कि हरियाणा की इकोनोमिक कंडी 1न भौटर हो जाएगी। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से दरखास्त करूंगा कि वे नए साधन जुटाएं और अपने रिसोर्सिज को टेप करें। हमारी जो सातवीं प्लान हैं वह 3200 करोड रूपए की है और इसके बारे में फ़ैसला अगले महीने होगा। स्पीकर साहब, इसमें भी कट लगेगा क्योंकि हमारे अपने कोई मैचिंग रिसोर्जिज नहीं है जो स्टेट के बजट को मैच नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर 3200 करोड रूपए का

प्लान बनाकर कैसे सैंक इन करायेंगे। मुझे डर है कि प्रायरिटी सैंक्टर जिस पर हरियाणा की जिन्दगी का दारोमदार है, जब प्लान सैंक इन होगा तो भारत सरकार उस पर कट लगायेगी।

स्पीकर साहब, हरियाणा के अंदर इरीगे इन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इरीगे इन मिनिस्टर साहब बहुत इंटैलीजेंट आदमी हैं। स्पीकर साहब, अगले इलैक् इन होने में अभी दो साल बाकी हैं और एस0वाई0एल0 नहर इस असैम्बली की मियाद में हरियाणा में नहीं आयेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में अपने रिसोर्सिज फाइंड आउट करने चाहिए। ग्राउंड वाटर को टेप करें और हिमाचल से कालका और ताजेवला तक छोटे छोटे डैम बनाए। सरकार ने पांच सात डैम बनाए हैं लेकिन जिस रफतार से सरकार को इस काम में इंट्रैस्ट लेना चाहिए उस रफतार से यह सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है। पता नहीं इसका क्या कारण है ? मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वे इस काम में इंट्रैस्ट लें और यह इलाका ऐसा नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए। यह बहुत बियटीफुल इलाका है। नारायणगढ्य, कालका से ताजेवाला तक का इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका बन सकता है। स्पीकर साहब, एस0वाई0एल0 नहर के पानी में अभी देर लगेगी। हमारी सरकार को चाहिए कि वे यमुना कैनाल और रिवर गंगा के पानी के बारे में यू0पी0 सरकार से बात करें और पानी के साधन जुटाये तभी हरियाणा के किसान का भला होगा और वह पूरी तरह से और मेहनत कर सकेगा।

स्पीकर साहब, अब मैं इंडस्ट्रियलाइजे इन के बारे में कहना चाहता हूँ। हरियाणा कुदरती तौर पर बड़ा खुला किस्मत है कि दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहां पर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कालके के अंदर चार सौ पांच सौ एकड़ जमीन ऐक्वायर की गई थी और उसका दफा चार का नोटिफिकेशन भी हो गया था लेकिन पता नहीं कि किस वजह से उस काम में आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मेरी दरखास्त है कि चीफ मिनिस्टर साहब, इस तरफ ध्यान दें। स्पीकर साहब, मैं एक बात चीफ मिनिस्टर साहब और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि परवाणू का जो इंडस्ट्रियल काम्प्लैक्स है वहां का पौल्यूटिड वाटर कालका में जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसको पौल्यूट कर रहा है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट है। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार इस बारे में पूरी कोशिश करे और हिमाचल गवर्नमेंट को मजबूर करे कि वहां से जो पौल्यूटेशन आ रहा है वह उसको रोके जिससे कि कालका के अंदर बीमारी न फैले। दूसरी बात यह है कि बरोटीवाला से मडावाला में पौल्यूटेशन आ रहा है। इसको भी रोकने की जरूरत है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब, इस बारे में हिमाचल सरकार से बात करें।

स्पीकर साहब, अब मैं टैक्स इन के बारे में कहना चाहता हूँ। सरकार ने अपने रिसोर्सिज को टैप किए बगैर टैक्स

लगा दिए हैं और इन टैक्सों से कुछ इंक्रीज होने वाला नहीं है। स्पीकर साहब, सरकार ने ट्रांसपोर्ट के किराये बढ़ाये हैं और इस बढ़ौतरी को जस्टीफाईड करने के लिये कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और डीजल की कीमत बढ़ी है। स्पीकर साहब, इस बढ़ौतरी के कारण 146 कमौडिटीज की कीमत और बढ़ जाएगी। इसमें कोई भाक नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है लेकिन जब तक स्टेट अपने रिसोर्सिज को टैप नहीं करेगा तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बारे में मैं सरकार को राय देना चाहता हूँ कि सरकार अपने इन्टरनल रिसोर्सिज टैप करे। स्पीकर साहब, जब कभी स्टेट की इकौनोमी खराब हो और स्टेट के फाइनेंसिज में क्राइसिज हो तो इसके लिये खर्च में पैसा बचाना आवयक है। स्पीकर साहब, इस संबंध में मैं दो चार बातें कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, कार्पोरेट इंज और बोर्डर्स में प्राइवेट आदमियों कबो चेयरमैन बनाया हुआ है। उनके अंदर न तो कोई टेक्नोलोजी है और न उनको मैनेजमेंट को कोई तजुर्बा है। स्पीकर साहब, अब तो ऐन्टी डिफैक्टानल बिल भी पास हो गया है। इसलिये कोई डर की बात नहीं है और इन लोगों की, इन प्राइवेट आदमियों को हटा देना चाहिए और जो ऐक्सपर्ट लोग हैं उनको वहां लगाना चाहिए। ऐसा करने से लाखों रूपए की सरकार को बचत होगी। स्पीकर साहब, जब फाइनेंसियल क्राइसिज हो, तो हमें गुजारा करने के लिये एक एक पैसा बचाना जरूरी है। हमें छोटी कार का प्रयोग करना चाहिए। मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर के लिए बड़ी कार का होना जरूरी है बाकी

मिनिस्टर्ज के लिये ऐम्बैसेडर या फिएट कार काफी है। स्पीकर साहब, अब तो हमारे प्राईम मिनिस्टर और सैंटर के दूसरे मिनिस्टर ऐम्बैसेडर कार ही प्रयोग करते हैं। देखा गया है कि घास लेने के लिये भी कारें जाती हैं। स्पीकर साहब, इस तरह के खर्चों पर कंट्रोल किया जाए। अगर इस तरह से थोडा थोडा पैसा भी बचाएंगे तो काफी बचत हो सकेगी। मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का यह काम है कि वे ये देखें कि इकनौमी कैसे हो सकती है। स्पीकर साहब, एक एक कतरे से तालाब भर जाता है। इनको यह देखना चाहिए कि स्टेट की इकोनोमी कैसे स्टेबल हो सकती है, स्टैट का पैसा कैसे बच सकता है ? यह काम चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का है अपोजी इन का नहीं है। हम तो केवल इस बारे में राय दे सकते हैं।

स्पीकर साहब, यहां पर ऐग्रीकल्चर की बात भी कही गयी। ऐग्रीकल्चर के मुताल्लिक मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक मोनो ब्लाक 7.5 हार्स पावर के पम्पिंग सैट पर टैक्स रिडूस किया है। हमारी ऐग्रीकल्चरल स्टेट है, इसमें भाक की बात नहीं है। अपोजी इन भी यह कहती है और सरकार भी यह कहती है लेकिन स्पीकर सर, मैं वित्त मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि ये हमारी पडौसी स्टैटस में जैसे कि हिमाचल प्रदे 1 है, यू0पी0 है, वहां जाकर देखें कि वहां की सरकारों ने ऐग्रीकल्चर के मामले में, वहां कि किसानों को कितनी कितनी ज्यादा सहूलियतें दी हैं। स्पीकर साहब, हमारे वित्त मंत्री महोदय बडे ही इंटैलीजेंट

हैं, भारियूड हैं लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरह से फेर बदल करके फिगर्ज को ऐस्केलेट कर दिया। इसको आम आदमी तो समझ नहीं पाएगा कि यह बजट स्पीच क्या है। चौधरी कटार सिंह जी भारीफ आदमी थे। वे डरते थे और चाहते थे कि फिगर्ज को ठीक रखो बहुत ऐस्केलेट न करो। उन्होंने 45-46 करोड रूपये का घाटा दिखाया था जो बाद में 92 करोड हो गया लेकिन अब उन्होंने सवा करोड का घाटा दिखाया है। भायद वह बढ़कर ढाई करोड होगा। ऐग्रीकल्चर के बारे में खास तवज्जो सरकार को देनी चाहिए। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि एक किसान जो अढाई हैक्टेयर का मालिक है, वह अपनी जमीन में अगर ट्रायल बोर करवाना चाहता है तो सरकार को यह काम करवा के देना चाहिए। इस बात को कृपया चीफ मिनिस्टर साहब नोट कर लें। ऐसा करने से यह भी पता चल जाएगा कि जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। स्पीकर साहब, सरकार को गरीब किसान की हर तरह से मदद करनी चाहिए क्योंकि उसके पास टयूबवैल्ज लगाने के लिये पैसा नहीं है, वह अपने पास से नहीं लगवा सकता, बोर नहीं करवा सकता। इसलिये सरकार यह बोर का काम अपने लैवल पर करवा कर के देवे और यह देखा जाए कि जमीन के अंदर पानी है या नहीं ताकि किसान खर्च से बच सकें।

स्पीकर साहब, मैं एक और बात सरकार के सम्मुख रखना चाहता हूँ। यू0पी0 के अंदर एक कानून बना हुआ है और वहां पर 34 आईटमज पर किसान को सेल्ज टैक्स की छूट दी गई

है। जो वस्तुएं किसान के इस्तेमाल की हैं, उन पर सेल्ज टैक्स नहीं लिया जाता। इसी तरह से हिमाचल सरकार ने भी किसानों के यूज की जो चीजें हैं, जो खेती बाड़ी में काम आती है, उन सभी आईटम्ज पर सेल्ज टैक्स से छूट दे रही है। वहां पर 5000 हजार रूपये ट्रैक्टर यहां से सस्ता पडता है और हमारे लोग वहां से ट्रैक्टर खरीद कर लाते हैं जिससे हमारे हरियाणा को नुकसान होता है। हरियाणा के अंदर हर पांच ट्रैक्टर पर दो ट्रैक्टर बनते हैं या तीन ट्रैक्टर बनते हैं इससे हरियाणा में टैक्टर्ज की सेल पर काफी फर्क पडता है। इसलिये हरियाणा के किसान को भी इन इम्प्लीमेंट्स पर सेल्ज टैक्स से ऐग्जैम्पान होनी चाहिए ताकि हरियाणा के किसान को राहत मिल सके। इस वक्त हरियाणा के अंदर फरीदाबाद और पिंजौर में दो फ़ैक्टरियां ट्रैक्टर बनाने की हैं लेकिन दूसरे राज्यों में ट्रैक्टर किसानों को काफी सस्ते पडते हैं। यहां से किसान खरीद नहीं सकता किसान हर लिहाज से यहां पर सफर कर रहा है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दे। इसके साथ साथ मैं फाइनेंस मिनिस्टर महोदय से यह भी कहूंगा कि किसानों को जो गेहूं का 157 रूपये रेट दिया गया है, यह बहुत थोडा हैं इससे किसानों को कुछ बचने वाला नहीं है। इस तरफ सरकार ध्यान दे। किसानों की हालत बडी ही खस्ता है और सिर्फ कह देने से किसानों के साथ हमदर्दी रखना या लिपसिम्पथी से कोई किसानों की समस्या हल नहीं होने वाली है। स्पीकर साहब, आप भी किसान हैं, आप भी महसूस करते हैं कि यह जो 6-7 हजार रूपया ट्रैक्टर पर यहां पर सेल्ज टैक्स

लगता है, वह जमींदार को देना मुश्किल है। इसलिये यह टैक्स किसानों से नहीं लिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ दूसरी इम्प्लीमेंटस जो किसानों के रोजाना यूज की हैं, उन पर भी हिमाचल और यूपी की सरकारों की तरह सेल्ज टैक्स से माफी होनी चाहिए। तभी किसान फलफूल सकता है और हमारे हरियाणा में खुशहाली आ सकती है। अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारी स्टेट भी खुशहाल होगी। मेरी सरकार से एक हमबल सबमिशन है कि इस तरफ सरकार खास तवज्जो दे और किसानों को हर तरह से राहत दें।

स्पीकर साहब, सरकार ने जो चूड़ियों के ऊपर टैक्स माफ किया है, वह भी एक अच्छा कदम है। चूड़ियां तो और भी किस्म की हैं, प्लास्टिक की चूड़ियां भी बनती हैं, इसलिये उन पर भी यह टैक्स माफ होना चाहिए नहीं तो वे आपसे निराश हो जाएंगे। स्पीकर साहब, मुझे यह नहीं पता कि ये चूड़ियां कहां बनती हैं लेकिन सुना है कि भिवानी में बनती हैं और भायद अम्बाला में भी बनती हैं। इसलिये प्रार्थना है कि प्लास्टिक की चूड़ियों पर से भी टैक्स हटाया जाए।

स्पीकर साहब, सरकार ने मैनुफैक्चररज की जो सेल 20 हजार तक की होती थी उसकी लिमिट बढ़ा कर अब एक लाख तक कर दी है। अगर यह लिमिट बढ़ा कर दो तीन लाख कर दी जाए तो इसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा सिवाये इसके कि इस पर इन्स्पैक्टर्ज कंट्रोल खत्म होता है, और कोई बात नहीं

है। सेल्ज टैक्स की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक कागजीद कार्यवाही है। एक लाख का माल तो एक महीने में ही निकल जाता है। इसलिये सरकार को लोगों को ईमानदार बनाने को तरजीह देनी चाहिए। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक लाख की बजायेयस अगर सरकार दो लाख तक को लिमिट बढ़ा दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल्ज टैक्स देकर जो चीज लाना चाहेगा लाएगा बल्कि इससे बैटर कन्ट्रोल हो सकता है। (घण्टी) स्पीकर साहब, मैंने बोलना तो बहुत था लेकिन आपने घण्टी बजा दी। मैं तो आपको ओबिडिएन्ट हूँ जैसे आप हुक्म करेंगे, सर माथे पर लेकिन आप मुझे डिमांडज पर बोलने का समय दे देना। इन लफ्जों के साथ मैं अपने वित्त मंत्री महोदय और सरकार से यह कहूंगा कि जो जो सुझाव मैंने यहां पर दिये उन पर पूरी तरह से गौर किया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि जो बातें अपोजी उन ने कहीं हैं, चाहे वे कितनी ही अच्छी क्यों न हों, वह तो माननी ही नहीं हैं। अगर नेक बातें हैं ऐग्रीकल्चर के हित में, किसान के हित की हैं, गरीबों के हित की हैं, प्रदेशों के हित की हैं, उन बातों को अब य मान लेना चाहिये ताकि हरियाणा के किसानों को सरकार की तरफ से हर प्रकार की राहत मिल सके। इससे प्रदेशों का भी हित होगा। जय हिन्द!

चौधरी रो मन लाल आर्य (छछरौली): अध्यक्ष महोदय, 1985-86 का बजट सदन में विचार के लिये और अनुमोदनार्थ पेश हुआ है और इस पर एक दो दिनों से चर्चा हो रही है। मैं

भी इस पर अपने विचार रखने के लिये और इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह बजट आगामी पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष का बजट है। इसको पढ़ने से साफ तौर पर यह दिखायी देता है कि यह बजट हरियाणा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और हरियाणा के किसानों को, मजदूरों को, हरियाणा की जनता को राहत दिलायेगा। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्व बोलते हुए मेरे माननीय सदस्य ने यू०पी० और हिमाचल प्रदेश की सरकारों की कारगुजारी का यहां पर जिकर किया। मैं भी एक और बात यहां पर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश राज्यों से प्रति व्यक्ति आय हमारे यहां की ज्यादा है और यह केवल इन दोनों प्रदेशों से ही अधिक नहीं है बल्कि सारे देश में हमारे प्रदेश का स्थान इस लिहाज से तीसरा है और इस बजट के इम्प्लीमेंट होने के बाद यह स्थान प्रथम या दूसरा आने की सम्भावना है। जो केन्द्रीय बजट पेश किया गया है, उसी की लाईन पर, उसी को आधार मानकर हरियाणा सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को पेश किया है। इस बजट को पढ़ने से यह साफ दिखायी पड़ता है कि इसमें किसानों के लिये बहुत सारी राहतें दी गयी हैं और विशेष कर जो ग्रामीण बेरोजगार हैं उनके लिये रोजगार की व्यवस्था की गयी है। जितने हमारे नवयुवक कृषि वर्ग से सम्बंधित हैं, उनको रोजगार देने के लिये बहुत ही व्यापक स्तर

पर इस बजट में प्रबन्ध किया गया है। जैसे डेयरी की बात है और भी इसी तरह के काम हैं जो पृथक पृथक कृषि के साथ साथ कर सकते हैं। फसलें काटने के बाद जो खाली समय होता है उसमें किसान को सहायक धन्धों के तौर पर कार्य करने के लिये सरकार ने काफी तरह की सुविधा किसानों की जुटाई हैं ताकि वह ज्यादा काम काज में लगा रहे और अपनी व अपने प्रदेश की हालत को और सुधारता रहे इसी तरह से प्रशासन तंत्र में तीव्र गति से काम काज को करने के लिये हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 5 दिन की बजाये छः दिवसीय सप्ताह शुरू किया गया है। देश में सब से पहले ऐसा हमारे हरियाणा ने ही किया है। केन्द्र सरकार को छः दिवसीय वीक की बजाए 5 दिन का सप्ताह करना चाहती है। लेकिन हमारे यहां प्रशासन को स्वच्छ बनाने तथा काम को जल्दी करने के लिये ऐसा कदम उठाया गया है। कितने गर्व की बात है ? यह कदम इसलिये उठाया गया है ताकि दफतरों में रोजमर्रा के काम और तेजी से किये जा सकें और काम में कार्यकुशलता लाई जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, पैरा नं० 15 में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि हमारे हरियाणा में रोजगार की, उत्पादक रोजगार की अधिक से अधिक व्यवस्था होगी। इसमें और भी बहुत से प्वायंटस दिये गये हैं। लेकिन समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं सूक्ष्म तौर पर यह कहूंगा कि इस बजट में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उद्योगों को आगे बढ़ाया जाये। हमारे

प्रदेशों के निवासियों को इस पर गौरव होना चाहिये कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सारे भारत में हमारे हरियाणा ने ही सबसे पहले पहल की है और तमाम दूसरे मुल्कों में रहने वाले जो लोग यहां हरियाणा में उद्योग लगाने के इच्छुक हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं यहां पर उलबद्ध करायी जाती हैं और लोग बाहर से आकर हमारे हरियाणा में उद्योग लगाने का प्रयास कर भी रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपने भाइयों से अनुरोध है कि जब कहीं हरियाणा की उन्नति की बात आती है, देश की उन्नति की बात आती है, तो उस समय उन्हें किसी प्रकार की जलन महसूस नहीं होनी चाहिए बल्कि उनको इस बात को महसूस करना चाहिए और गर्व करना चाहिए कि हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जहां तक सरकार की नीति की बात है, अगर मेरे भाइयों ने उसके बारे में अपने विचार रखने हों, तो रखें लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब हरियाणा की और हमारे देश के सम्मान की बात आए तो उनको इस बात का गौरव महसूस होना चाहिए कि हरियाणा हर लिहाज से सारे देश में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में जो भी उन्नति का काम होता है वह हरियाणा के सभी वर्गों के लिये होता है। हमारे प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण के लिये हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाये हैं, जो कि प्रांसनीय हैं और हमारे इन अपोजीटिव भाइयों को इसका गौरव होना चाहिए। हरिजन

कल्याण निगम और वीकर सैव इन निगम द्वारा गरीब लोगों के लिये बड़े पग उठाये गये हैं ताकि जो यहां का गरीब मजदूर हैं, गरीब आदमी है, उसकी हालत को सुधारा जा सके, उसकी आर्थिक स्थिति को ऊपर लाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस बजट ने एक बहुत बड़ा काम किया है जिसको हमारे ये भाई देख नहीं पा रहे हैं। वह काम है ह्यूमन कैपिटल का। इस काम के लिये इस बजट में बहुत प्रावधान है। आप खुद देख लें कि शिक्षा और चिकित्सा के लिये कितना पैसा रखा गया है यानी जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं उनके लिये बहुत पैसा रखा गया है। इन योजनाओं को ह्यूमन कैपिटल समझा जाना चाहिए। भास्त्री लोग इस बात को समझते हैं कि जो पैसा विकास के कामों पर, रोजगार देने पर, शिक्षा और दवाइयां देने पर लगता है उस पैसे से ह्यूमन कैपिटल की फारमे इन होती है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इतना बढ़िया बजट पेश करके हरियाणा के विकास के लिये बहुत बढ़िया मार्ग प्रशस्त किया है। मैं समझता हूँ कि इस बजट में बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। वे सुविधाएं भी हमारे इन भाइयों में से बहुत को समझ नहीं आई होंगी। इस बजट से हमारा आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तो उस समय लगता है कि खर्चा ही खर्चा होता जा रहा है लेकिन जब वह काम पूरा हो जाता है तो हम देखते हैं कि वह प्रदेश की तरक्की का आधार बन जाता है। हमारे साथियों ने कहा कि बजट में बहुत ज्यादा घाटा है, दूसरे प्रदेशों के अंदर यह राहत दी गई

और वह राहत दी गई है लेकिन फिर भी वहां इतना घाटा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कई बातें ऐसी हैं जो मैं किन्हीं कारणों की वजह से नहीं बता सकता। कई ऐसे प्रदेश हैं जिनमें हमारे से दस गुणा ज्यादा आबादी है लेकिन वहां भी ऐसा बजट पेश नहीं किया गया है, जैसा हमारी हरियाणा की सरकार ने किया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बजट को सर्व सम्मति से पास किया जाए ताकि जनता यह समझ सके कि यहां पर राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन बजट के संबंध में सारी विधान सभा ने इसे सर्व सम्मति से पास किया है। इन भावों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ और आशा करता हूँ कि इस बजट को सर्व सम्मति से पास किया जाएगा।

चौधरी धीरपाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हरियाणा के सिवाए कहीं भी 6 दिन का हफ्ता नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि केन्द्र में पहले ही 6 दिन का हफ्ता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया बैठिए।

श्री हरि चन्द हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर महोदय, 1985-86 का जो बजट हाउस के सामने पेश है इसको मैं इन्साफ और सिद्धांत के तराजू पर रख कर आप लोगों के सामने धर्म और अधर्म के पलड़े पर तुलवाना चाहता हूँ। मैं इस बजट को दो सिद्धांतों पर लेता हूँ। मैं इस बजट को दो सिद्धांतों पर लेता

हूँ। एक तो यह कि कोई भी बजट जिसमें घाटा है जैसे इसमें 114 करोड़ रूपए का घाटा है वह क्रम में पैदा करेगा। The deficiency in money always produces corruption. दूसरे कोई भी बजट जिसका बंटवारा ठीक न हो, वह गुरबत पैदा करता है यानी if there is inequality in distribution of Budget it will produce poverty. ये दो सिद्धांत हैं। इन दोनों सिद्धांतों के बारे में मैं एक कोटे में दे रहा हूँ—

J. Hicks says-

“This is not a budget; it is a tug of war of economy between the rich and the poor. the bureaucracy Government is always on the side of rich man. Under the circumstances, the national Budget has never been distributed equally. That is why the rich become richer and the poor become poorer.”

This is a law.

इसलिये ये जो बजट आ रहे हैं इन्होंने गरीब आदमियों को ज्यादा मारा है। अब जब मैं यह कोटे में रखता हूँ और हिन्दुस्तान के आंकड़ों को देखता हूँ तो हिन्दुस्तान के 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे पड़े हैं, हिन्दुस्तान की आधी आबादी भूखमरी का शिकार बन कर खड़ी है। ये जो प्लान हैं ये पूँजीपतियों का एक ड्रामा है और यह ड्रामा हिन्दुस्तान की धरती पर खेला जा रहा है। इसलिये इस बजट और प्लान के बारे में मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तक सोशलिज्म की बात है, इसमें एक आदमी तो मौज उड़ाता है और एक आदमी भूखा मरता है। डिप्टी

स्पीकर साहब, अगर मैं इस बजट को देखकर रिपोर्ट पे आकरू तो आपके सामने आर०के० हजारी की रिपोर्ट है, नै नल सैम्पल सर्वे कमेटी की रिपोर्ट है। इसके अलावा जितने इकौनौमिस्टस हैं जैसे डा० खुसरो है, इनकी रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उनसे सीधी सी बात नजर आती है कि हिन्दुस्तान के इन बजटों में बे गुमार बाते हैं। इनमें आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है, इंडस्ट्री की रफतार कम है। इन चीजों से अपर क्लास पैदा हो गई है और वह इस बजट से अपनी जेब भर रही है। आज टैलीविजन, कार, बंगलें तथा और सुविधाओं से ये लोग ऐ आ कर रहे हैं। इस बजट के जरिये 20 प्रति शत आदमी तो बहुत ऊपर चले गये हैं और बाकी 80 प्रति शत जिनमें किसान मजदूर आते हैं वे बहुत नीचे चले गये हैं। यह इन बजटों की रूप रेखा है। अब इनका बीस सूत्री प्रोग्राम आता है। इसमें मैं देखता हूँ कि—

वायदे ज्यादा काम कम,

कंट्रोल ज्यादा फायदे कम,

भर्ती ज्यादा सर्विस कम,

नहरें ज्यादा पानी कम,

खम्बे और तार ज्यादा, बिजली कम।

16.00 बजे।

डिप्टी स्पीकर साहब, फसलें कागजों पर उगाई जा रही हैं। और लोगों का पेट प्रोपेगण्डे से भरा जा रहा है। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ और मान कर चलूंगा। इस बजट भाषण के पैरा दो के अन्दर स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारे में जिकर किया गया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि वे केवल हिन्दुस्तान की ही नेता नहीं थीं बल्कि दुनिया के महान नेताओं में से एक नेता थीं। इस बात को मैंने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने माना है। डिप्टी स्पीकर साहब, 31 अक्टूबर 1984 हिस्टोरीकल डे है इसमें कोई भाक नहीं। यह एक हिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन मैं साहड बाई साइड एक बात और कहना चाहूंगा कि the year of 1984 has been the year of disorder, violence, recession and disintegration जिसकी वजह से 1984 का साल हिन्दुस्तानी कौम के लिए एक ऐसी भाक्ल पैदा कर गया। The memory of the people is very short. False slogans are given to the hungry people. हम एक गरीब ने उन हैं। मैं समझता हूँ उसका एक रीजन है। जो गवर्नमेंट की पालिसी है वह दो चीजों पर चलती है। पहली यह है कि लोगों की याददा त बहुत कमजोर है और दूसरी गरीब लोगों को झूठे सलोगन देना। उकसका रिजैल्ट हमारे सामने आया कि जो औफि टायल म गिनरी है वह पोलिटीकल म गिनरी बन चुकी है। और जो पोलिटीकल पार्टी म गिनरी थी वह मर चुकी है। इसके अन्दर पोलिटी टायन भी आ गए और पूंजीपति भी आ गए। ये दरअसल मौरल से बहुत पीछे चले गए और उसका रिजल्ट यह निकला कि

दे 1 के अन्दर कमजोरी आती चली गई। दे 1 की कमजोरी का नतीजा यह हुआ कि जितनी पोलिटीकल पार्टीज थीं वे सारी अपने अपने घरों में बैठ गईं। जो औफिियल मीनिंग है उसने सरकार की जगह ले ली। (गोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: हाइजैकिंग और चोरों वाली बात रिकार्ड न की जाए।

श्री हरिचन्द हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, इन हालात में मैं यह कहना चाहूंगा कि पोलिटीकल पार्टीज कासियासी ढांचा, आर्थिक ढांचा और मौरल ढांचा इतना गिर चुका है, इतना खराब हो चुका है कि विधान सभाओं और पार्लियामेंट में जितने भी हिन्दुस्तान के लीडर या हिन्दुस्तान के रहबर हैं, वे केवल भाषण देते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे पिक्चर में एक हीरोइन स्टेज पर अपनी चमक धमक दिखाती है और चली जाती है इसी तरह से हमारे दे 1 की लीडर करते हैं और दे 1 भूखा रह जाता है। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर में मैं इस सरकार के हालात को देखते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा –

पंछी समझते हैं चमन बदला है,

सितारे समझते हैं, गगन बदला है,

मगर भामिनी की भूमि यह कहती है,

है ला । वही सिर्फ कफन बदला है ।

चौधरी धर्मबीर गाबा (गुड़गांवा): डिप्टी स्पीकर साहब, 20 मार्च को वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे । किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। पिछले दिनों हमारे सूबे में काफी खराब हालात पैदा हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी हम तराक्की की तरफ बढे हैं और बढते रहेंगे। मैं इस बजट को यदि थोडे लफजों में समअप करना चाहूं तो हम इतना कह सकते हैं कि यह बजट ग्रोथ ओरिएन्टड, सो गल जस्टिस और एक्वैलिटी के लिए है। डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं रोडज के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस बजट के अन्दर सडकों के लिए 13 करोड 69 लाख रूप्य का प्रावधान किया गया है जो कि बहुत ही थोडा हे। सडकों की रिपेयर्ज के लिए यह राशि रखी गयी है। मैं समझता हूं कि इस पैसे को अगर थोडा और बढा सकते हैं तो बढा दिया जाए। यह बहुत ही थोडी राशि है। इसके अलावा 15 करोड 37 लाख रूप्य का नई सडकें बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। यह भी बहुत थोडा पैसा है। इसको भी बढाया जाना चाहिए। यह भी ठीक है कि स्टेट के अंदर 20 हजार किलोमीटर लम्बी सडकें हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमें और नई सडकें चाहिए। नई सडकें बनाने के लिए जितना पैसा इस बजट में रखा गया है। वह बहुत ही थोडा है। अगर उस पैसे की बढौतरी हो सकती है तो मंत्री महोदय हाउस में बैठे हैं उस पर विचार कर लें और इस राशि को बढा दें। इस बजट में जैसा

मैंने पहले कहा 200 किलोमीटर नई सड़कें बनाने के लिए 15 करोड़ 37 लाख रूपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एप्रोच रोडज सबसे पहले स्कूलों के लिए बनाई जाएं। जिन स्कूलों के लिए एप्रोच रोडज पहले नहीं बनाई गई थीं उनके लिए बना दी जाएं ताकि बरसात के दिनों में बच्चों को कोई तकलीफ न हो जो 13 करोड़ 69 लाख रूपया रोडज की रिपेयरिंग के लिए रखा गया है, इसमें से 7 लाख 17 हजार रूपया एस्टेब्लि मेंट का खर्चा है, एक करोड़ 57 लाख रूपया मीनरी के लिए है और बाकी पांच करोड़ रूपये के करीब बचता है जो कि बहुत ही थोडा है। हमारी स्टेट में जैसा मैंने पहले कहा 20 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं जिनकी रिपेयर के लिए यह पैसा बहुत ही थोडा है। अगर इस पैसे को बढ़ा दिया जाए तो अच्छी बात होगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एजुकेशन के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज हरियाणा के अन्दर एजुकेशन 36 परसेंट के लगभग है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हमें एजुकेशन और चाहिए। इस बजट के अन्दर स्कूलों की नई बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। स्कूलों के लिए बहुत ही थोडा पैसा रखा गया है। स्कूलों के लिए केवल 2 लाख 50 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। अगर इस पैसे को बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ यह बहुत ही नेक काम होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वित्त मंत्री जी से यह भी

गुजारि । करुंगा कि स्कूलों की बिल्डिंगों की मँटीनेंस के लिए भी जो पैसा रखा है वह बढा दें ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अर्बन डिवैल्पमेंट के लिए केवल 70 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । अगर इस पैसे को भी बढा दिया जाए तो बहुत नेक काम होगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं एक्साइज एण्ड टैक्से इन डिपार्टमेंट के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भाक नहीं कि टैक्सिज बढे हैं । टैक्सिज के बगैर न स्टेट चल सकती है और न दे । चल सकता हैं । इस बारे में मेरा एक सुजै इन मंत्री जी से है । मेरा सुजै इन यह है कि टैक्सिज के बारे में हरियाणा और दिल्ली की आपस में यूनिफार्मेटी हो जाये तो उससे हरियाणा को काफी टैक्स आ सकता है । हरियाणा औद दिल्ली में टैक्सों में फर्क होने के कारण हरियाणा का आधा टैक्स दिल्ली को चला जाता है । आप पेट्रोल और डीजल को ही ले लें । हमारे यहां से दिल्ली और हरियाणा में सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है । दिल्ली के अन्दर पेट्रोल हरियाणा की अपेक्ष 40-50 पैसे लिटर कम है और इसी प्रकार से डीजल भी दिल्ली में हरियाणा की अपेक्षा 25-30 पैसे लिटर कम है । दिल्ली में इन चीजों के रेट कम होने पर हमारी सेल कम हो जाती है । मेरी सुजै इन यह है कि मंत्री जी इस बारे में बडी संजीदगी से सोचें । उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि गुड़गांवा से रिवाड़ी तक का इलाका, पलवल से फरीदाबाद तक का इलाका और इधर सोनीपत

व बहादुरगढ़ का इलाक दिल्ली के साथ लगते हैं। ये एरिया दिल्ली के साथ लगने की वजह से पेट्रोल और डीजल की सारी सप्लाई हरियाणा के पेट्रोल पम्पों की बजाये दिल्ली से लेते हैं। इस बारे में मेरी फिर प्रार्थना है कि मंत्री जी दिल्ली के साथ टैक्स की यूनिफार्मिटी करें ताकि हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा टैक्स आ सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, बजट में कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री जी ने काफी सहूलियतें दी हैं। इस बजट के अन्दर कर्मचारियों के लिए इन्- योरेंस की स्कीम है, कर्जों की बढौतरी है और एल0टी0सी0 की सुविधा आदि है। वित्त मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है जिसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने पांच भाहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को 5 प्रति 1000000 दिया है। इन कर्मचारियों की यह डिमांड काफी दिनों से चली आ रही थी। मैं खास तौर से वित्त मंत्री जी को हरियाणा सरकार को, हरियाणा के कर्मचारियों की तरफ से और विशेषकर गुड़गांवा में काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ से उनकी इस मांग के मानने पर बधाई देता हूँ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं अर्बन डिवैल्पमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। इस हाउस के अन्दर बहुत सारे एम0एल0एज0 भाहरों से बन कर आये हैं जो एम0एल0ए0 भाहर से बन कर आया है उसके लिए यह समस्या है कि अर्बन डिवैल्पमेंट के लिये सिर्फ 50 लाख रूपये ही रखे गए हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह रकम

बहुत थोड़ी है। यह बात ठीक है कि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमेंट अथोरिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि किसी ने हुड्डा का काम देखना है तो वह गुडगांवा में आकर देखे। हुड्डा ने वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं हुड्डा को एक बात के लिये जिम्मेवार भी ठहराता हूँ जिसकी वजह से आज भाहरों में अन अथोराइज्ड कालोनियां बन रही हैं। इसका मेन कारण यही है कि हुड्डा ने लोगों से सस्ते भाव पर जमीन ली है और दूसरे हुड्डा ने छोटे छोटे गरीब लोगों के लिये प्लॉटों की कोई व्यवस्था नहीं की। हुड्डा ने ऐसा भाहरों में कोई प्रोवीजन नहीं किया जिससे 100-100 गज के मकान गरीब लोगों को दिए जा सकें। हुड्डा ने 300 गज के 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट जरूर काटे हैं लेकिन गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बारे में मेरी प्रार्थना है कि हुड्डा ऐसे लोगों के लिये भी प्रोवीजन करे ताकि जो अन अथोराइज्ड कालोनियां बन रही हैं उनको रोका जा सके। अन अथोराइज्ड कालोनियां बढ़ने की वजह से ही सरकार अब म्युनिसिपल ऐक्ट के अंदर अमेंडमेंट ला रही है। मेरी फिर गुजारि है कि हुड्डा वालों को ऐसा कोई प्रोवीजन करना चाहिए जिससे गरीब आदमियों के लिये भाहरों के अन्दर रहने के लिये मकान मिल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे विरोधी पक्ष के भाईयों ने कहा है कि बसों

के किराये बढा दिए हैं सरकार जनता को अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदान करती है। सरकार ने यह किराया सिर्फ 1.25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही बढाया है। यह किराया बढाना वाजिब भी है और जरूरी भी। इस समय इतफाक से आनरेबल मैम्बर फतेहचन्द विज जी हाउस में नहीं बैठे। उनका भी ट्रांसपोर्ट का काम है और मेरा भी ट्रांसपोर्ट का काम है। जब हम ट्रांसपोर्ट वाले अपना रेट बढा सकते हैं तो गवर्नमेंट को बसों का किराया बढाने में क्या हर्ज है जबकि आज के दिन पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ गए हैं। यह जरूरी भी नहीं है कि सारे काम घाटे से ही चलें। सरकार ने आज जो थोडा बहुत बोझ हम पर डाला है इसको हम सब को हंसते हंसते बर्दा त कर लेना चाहिए। अन्त में मैं आप सब से गुजारि ा करना चाहता हूं कि इस बजट की मुखालफित न करें और इस बजट को सर्वसम्मपति से पास होने दें।

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, सदन के अन्दर बजट पर परिचर्चा हो रही है। 20 तारीख को हमारे जानकार मित्र श्री सागर राम गुप्ता जी ने अपने भाशण में कदम कदम पर, पग पग पर कहना कि मैं यह कहना चाहता हूं, मैं वह कहना चाहता हूं। आज मैं उनको सुनाना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सदन की मर्यादाओं को तोडा गया है और आनरेबल स्पीकर साहब ने भी इन्हें नहीं रोका। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: डा० साहब यह प्वायंट तो पहले उठ चुका है और इस पर उस समय फैसला भी हो चुका था।

श्री मंगल सैन: ठीक है जी। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट के अंदर संट्रैल बजट का बार बार जिकर किया गया है। इन्होंने वह काम किया जो नहीं करना चाहिए था आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी जिनको ये बापू कहते हैं और उनके नाम से वोट मांगते हैं, ने नमक पर कर लगाने का विरोध किया था। ये उन्हीं के नाम पर वोट मांगते हैं ने नमक पर टैक्स लगाते हैं जिसका महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है। अजीब सी बात है कि केन्द्र का रेलवे बजट भिवानी के संसद सदस्य ने पे । किया और हरियाणा का बजट भिवानी के ही विधायक ने पे । किया है। इन दोनों का एक सूत्री प्रोग्राम था कि जनता पर टैक्स लगाओ। उन्होंने रेल का भाडा बढा दिया और इन्होंने बस का भाडा बढा दिया। इसके साथ साथ रेलवे के जरिए जो सामान ढोया जाएगा उसका रेट भी बढा दिया। इसके अलावा इन्होंने बिजली पर सैस लगाया। (विधन) अब ये कहते हैं कि यह तो किताबों में ऐडजस्टमेंट करना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब किसानों में ऐडजस्टमेंट करना था तो फिर यहां लाने की क्या जरूरत था।

वित्त मंत्री (श्री सागर राम गुप्ता): वह भी आपको बतायेंगे।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, पहली बात यह है कि चौधरी कटार सिंह से यह महकमा खोस कर इनको दिया गया है। हम सोचते थे ये कोई अच्छी बात करेंगे लेकिन इन्होंने कोई खास बजट पे नहीं किया। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैसिव मैनडैट मिलने के बाद भी इन्होंने आम जनता को कोई राहत नहीं दी। ये बजट में फरमाते हैं और एस0वाई0एल0 के बारे में कहते हैं कि राज्य सरकार के मुख्य प्रयासों में से एक प्रयास है। हमारे किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना। इस बारे में यह कहते हैं कि हमारा यह काम प्रमुख कामों में से एक काम है जिसको पूरा करना है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये ऐग्रीमेंट कब का है। आपने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं। आप भागे भागे भी दिल्ली हवाई जहाज से जाते रहे हैं। (विघ्न) श्री लछमन सिंह जी आप तो न बोलें क्योंकि आप हमें छोड़ कर उधर चले गये थे और अब फिर इधर आ गये हैं। आप तो हमें परमाणु ले गये थे। ? (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, ये मेरे गहरे दोस्ते हैं, आडे वक्त के साथी हैं। करनाल की जेल हम दोनों ने इकट्ठी देखी है, भगवान दोबारा ऐसा मौका न दिलाये। ये हमारे आडे वक्त के साथी हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने बजट भाषण में फरमाया कि राज्य सरकार के मुख्य प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास है— सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना का निर्माण करना। यानी सतलुज यमुना के पानी की तरफ बहुत ध्यान देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, 1981 में एस0वाई0एल0 का ऐग्रीमेंट हुआ था और श्री भजन लाल

ने कहा था कि दो सालों में नहर पूरी हो जायेगी। ये स्वर्गवासी श्रीमती इन्दिरा गांधी को भलो भलाकर वहां ले गये थे कस्सी मारने के लिये। उसे कहा कि बहन जी, कस्सी मार दारे, हरियाणा में पानी जाना है और हरियाणा के भोले भाले किसानों को कह दिया कि तुम्हें पानी देंगे। 1981 बीता, 1982 बीता, 1983 भी चला गया, 1984 भी दम तोड गया और अब 1985 भुरू हो गया। लेकिन नहर नहीं बनी। अब श्री सागर राम जी हमको समझा रहे हैं कि काम जोरों भाोरों से भुरू कर दिया और यह काम सेंद्रल गवर्नमेंट प्रगति का परीवीक्षण बहुत बारीकी से करने के लिये सहमत हो गई है। परिवीक्षण यंत्र माइक्रोस्कोप को कहते हैं। इन्होंने अपने दफतरों में माइक्रोस्कोप लगा दिया कि काम हो रहा है। चौधरी भजन लाल जी, माइक्रोस्कोप को तो आप जानते ही होंगे। भायद आपने अपने स्कूलों में, छोटे से छोटे जीव को देखने के लिये लैबोरेटरी में यह यंत्र देखा होगा ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): हमें तो पता नहीं, आप ही बता दो।

श्री मंगल सैन: आपको पता ही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे पहले सैन्द्रल गवर्नमेंट अपनी आंखों पर नीली पट्टी बांधे हुए क्यों बैठी रही ? जब इस पार्टी के प्राईम मिनिस्टर के दस्तखत इस एग्रीमेंट पर थे तो अब तक क्यों पानी नहीं ले पाये।

चौधरी भजन लाल: नीली नहीं हरी पट्टी है डा० साहब! (हंसी)

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इस मामले में नम्बर वन पर सबसे बड़ा मुजरिम मैं सनैट्रल गवर्नमेंट को बनाता हूँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का राज था। यहाँ पर भी ये कांग्रेस आई का दावा करते हैं। अब तो करते हैं, कल तक पता नहीं क्या करेंगे, यह भगवान जाने। डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब में राष्ट्रपति राज है और राज्यपाल उनके हैं, उनका राज है क्योंकि वे हर मामले में दस्तखत करते हैं। सचिवालय में राज्यपाल के सलाहकारों की चलती है। इन्होंने क्या मजाक कर रखा है, क्या प्रतिष्ठा बनाई है। भजन लाल जी, इस कुर्सी पर कई आये और कई चले गये। यहाँ कोई परमानेंट नहीं बैठा। गोपीचन्द भार्गव आये, श्री भीमसैन सच्चर आये, प्रताप सिंह कैरो आये, राम किान आये, चौधरी देवी लाल आये और अब आप आ गये।

चौधरी भजन लाल: जाना तो सब ने है!

श्री मंगल सैन: सबने जाना है, यह निश्चित है लेकिन कुछ के जाइए, नाम कमा के जाइए।

चौधरी भजन लाल: इससे फालतू क्या काम करना है कि आपको उधार बैठा रखा है।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, आप हरियाणा से किसी दूसरी स्टेट में जाएं तो लोग कहते हैं कि आप कहां से

तारीफ लाये, कहां के रहने वाले हैं। क्या यू०पी० के हो, बिहार के हो, या राजस्थान के हो ? जब हम कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के हैं तो आगे से वे मुस्कुरा पड़ते हैं। हम कहते हैं कि क्यों भाई, क्या हमारा रंग ठीक नहीं है ? तो वे कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन और जगह परचून में माल बिकता है, यहां थोक में बिकता है। चौधरी भजन लाल जी, ऐसी प्रतिशठा न बनाएं। जिस दिन हरियाणा के साथ अन्याय हो गया हम तो इस्तीफा दे देंगे। हम आपको कहते हैं कि तुम हिम्मत वाली बात करो और आंखों से देखो। अब तो दोनों आंखें भगवान की दया से ठीक हो गईं।

चौधरी भजन लाल: हम आपके साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डा० साहब, आपको बोलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, आप अपनी बात जल्दी जल्दी कहें।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, सारे सदन के लोग यही चाहेंगे कि आप कृपा करके आधा टाइम मुझे ही दे दें। मैं बड़े भारी मन से खड़ा हुआ हूँ। मैंने किसी मित्र के अन्तिम संस्कार में जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे भिवानी में मजदूरों के नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बजट में मजदूरों के हित की कोई बात नहीं देखी। पिछले दिनों लेबर कंसिलिएशन के लिये एक मिनिस्टीरियल ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इसमें लेबर आफिसर था, वह कई महीने

तक गायब रहा। सारे मजदूर धक्के खाते रहे। इनको पता है, क्योंकि ये लेबर यूनियन की तरफ से पैदा होते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पहले जाते होंगे।

श्री मंगल सैन: ये कभी इन्कार नहीं कर सकते कि मजदूरों के नेता नहीं हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि भजन लाल जी, आपने हमारी बात का बड़ा बुरा मनाया जब हमने हिसार की कुछ चर्चा की कि साहब, हिसार में एक एम0एल0ए0 रहे हैं जो जमीन के बारे में बड़ी गडबड करते हैं, आपको इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए। अब मैं खानों के विषय की ओर आना चाहता हूँ। आपके एक पुराने पार्टनर थे। ये खानों के मालिक हैं। दो तीन खाने जिनकी लीज कैंसिल हो गई थी, अब इनको नये सिरे से पटअे पर ले ली गई।

श्री उपाध्यक्ष: इनका नाम रिकार्ड न किया जाए।

श्री मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, उन खानों के छोटे छोटे हिस्से बना कर लोगों को पटटे पर दिये जा रहे हैं। ये लोग उस इलाके के रहने वाले नहीं हैं। चलो, इलाका कोई भी हो सकता है आदमपुर के आदमी को तो इन्कार नहीं है।

चौधरी भजन लाल: वे तो मजदूरी करते हैं।

श्री मंगल सैन: ठीक है, मजदूरी कहीं भी करो, लेकिन मजदूर को लूटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस बात पर

सैंटर में झगडा हो रहा है और बडा सीरियस मामला है। भजन लाल जी इस मामले में अपनी पोजिशन साफ करें। कुछ लोगों ने ऐप्लीकेशन दी है, उनको खानों की ओर ध्यान करने की बजाये अलाट करने जा रहे हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। इनके वक्त की बात है। भगतु राम जी वहां से बीजेपी का कंडीडेट था, उसने खाने ली है लेकिन इसकी रिकमेंडेशन इनके वक्त की है।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कबूल करता हूं कि वे हमारी पार्टी के थे, उन्होंने डिफैक्ट नहीं किया है। मैं एक बात कहूंगा क्योंकि मेरा नाम इनके साथ जोडा जाता है। मैंने पता किया है, खानों की अलाटमेंट मैंने नहीं की थी आपकी कलम से हुई थी।

चौधरी भजन लाल: आपकी रिकमेंडेशन थी। कायदे के मुताबिक जो आदमी पहले ऐप्लीकेशन देता है, उसका नाम देना पडता है और यह सैंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। आपके रिकमेंडेशन की थी, हमने कर दिया। हम उसको कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन कैंसिल इसलिए नहीं किया कि भायद डा० मंगल सैन कहेंगे कि बीजेपी का आदमी है, इसलिए इसके साथ ज्यादाती कर दी।

श्री मंगल सैन: आप जो कह रहे हैं कि आपने मेरी पार्टी का लाहज किया इसके बारे में मैं कहूंगा कि आप लाज न किजिए बल्कि उसे कैंसिल कर दीजिए। हाउस की कमेटी बना दीजिए। (विघ्न)..

श्री उपाध्यक्ष: यह हिस्से वाली बात रिकार्ड पर नहीं आएगी।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, let there be a judicial probe. अब मैं ला एंड आर्डर की तरफ आता हूँ। (विघ्न) यह ठीक है पुलिस को रूपया चाहिए। रूपये का बंदोबस्त पूरा होना चाहिए लेकिन इन्हें अलर्ट भी होना चाहिए। पुलिस वालों की स्क्रीनिंग भी होती रहनी चाहिए। ऐसा न हो भजन लाल जी कि अपने ही घर में, अपने ही लान में कोई पुलिस वाला गलत काम कर जाए। सारी बातों का ध्यान करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, पड़ौसी राज्य में अराजकता होने के कारण उग्रवादियों की गतिविधियों से हरियाणा के ला एंड आर्डर को भी काफी खतरा रहा है। इनको इसका पूरा बन्दोबस्त करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, ये एक बड़े काबिल आदमी की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि उस वाईस चांसलर के केस में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि इस बजट का पैसा, हरियाणा के गरीब किसान और मजदूर के

गाढे पसीने की कमाई का पैसा अदालतों में गलत आदमी की सुरक्षा के लिये खर्च नहीं होना चाहिए। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐजुके टन बोर्ड की ओर आता हूँ इसके बारे में कल के ट्रिब्यून में बड़ी ताजा तरीन खबर आई हुई थी। उसमें लिखा था कि School Education Board goes down hill. यह भिवानी से खबर थी। It is from Mr. Jatinder Sharma.

श्री उपाध्यक्ष: डा० साहब, इसका काफी रैफरेंस आ गया।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे एक भोले भाले दोस्त को लोकल बौडीज का वजीर बना दिया गया है।
.....

श्री उपाध्यक्ष: यह बात रिकार्ड पर नहीं आएगी।

श्री मंगल सैन: मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात से साफ जाहिर होता है कि आप सरदार प्यारा सिंह जी को रैफर कर रहे हैं।

श्री मंगल सैन: तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रार्थना कर रहा था कि नगरपालिकाओं के चुनाव के बारे में अभी कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 4 महीने तक तो वार्डज बनेंगे। वार्डज बनने के बाद वोट बनेंगे। इन

चुनावों को जल्दी से जल्दी करवाया जाना चाहिए। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, सन 1979 से बार्डज बनने भुरु हुए हैं। सन 1984 दम तोड चुका है लेकिन अभी तक चौधरी भजन लाल जी का वायदा पूरा नहीं हुआ क्योंकि चौधरी साहब का वह वायदा ही क्या जो वफा हो जाए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: डा० साहब, अब आप वाइन्ड अप कीजिए।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, आज सारी नगरपालिकाओं में हाउस टैक्स लगा हुआ है। आज चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। वीर प्रताप में एक खबर छपी है कि "हाउस टैक्स की नई असैसमेंट से परे गानी"। (विघ्न) यह 25 मार्च, 1985 यानि आज के ही अखबार में छपा हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि 'No Taxation without representation' का एक सिद्धान्त है। जहां नगरपालिका ही नहीं है, जहां नगर के रहने वाले लोगों को रिप्रैजेंटेशन नहीं मिलता, चुनाव का मौका नहीं मिलता, वहां अनाप गनाप टैक्स बढ़ रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन पीने के पानी के लिये हाहाकार मची हुई है। मेरे भाहर को तो इन्होंने जान बूझ कर नर्क में डाल रखा है। बडी कहा सुनी करके इनसे मंजूर करवाया है। आज से तीन साल पहले स्कीम मंजूर हुई थी। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: वहां काम तो भुरु है।

श्री मंगल सैन: काम कुछ कुछ भुरु है।

चौधरी भजन लाल: धन्यवाद तो कर दो ।

श्री मंगल सैन: आपका धन्यवाद जरूर करूंगा लेकिन मौका आने पर। काम जब पूरा हो जाएगा तो धन्यवाद कर दूंगा। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक धन्यवाद कैसे कर सकता हूं ? (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने बीस सूत्री प्रोग्राम बना रखा है। कहते हैं कि बीस सूत्री प्रोग्राम में जनता के विकास का मुद्दा है। अगर उसमें सचमुच जनता के विकास की बात है तो इन्हें उनमें सबको शामिल करना चाहिए लेकिन बीस सूत्री प्रोग्राम के जो इन्होंने चेयरमैन लगाए हैं, वे अफसरों के लिए लिए फिरते हैं वे एक हारे हुए एम0एल0ए0 हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए ऐसा करते हैं। फिर इन्होंने एक ग्रिवैन्सिज कमेटी बना रखी है। लेकिन उसमें भी ये किसकी ग्रिवैन्सिज सुनते हैं ? अपनी ही पार्टी की लोगों की। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: आप तो उसमें हो ।

श्री मंगल सैन: मैं तो हूं। एम0एल0ए0 तो उसमें है लेकिन इसमें आपकी क्या मेहरबानी है ? मैं तो एम0एल0ए0 होने के नाते से उसमें हूं। एम0एल0ए0 को तो आप लेंगे ही। हमारी पार्टी का वर्कर उसमें नहीं है। (विघ्न) मेरा कहना है कि असैम्बली में आने वाली हर पार्टी का नुमायंदा उसमें होना चाहिए और उसे वहां अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

Mr. Deputy Speaker: Dr. Sahib, now please resume your seat.

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, बातें तो बहुत करनी थीं लेकिन कुछ तो आपकी घंटियों ने परे तान कर दिया और कुछ मैं भी जाने की जल्दी में हूँ लेकिन अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह बजट बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए क्योंकि आज जनता के लिये बड़ी जहमत का मामला हो गया है। पहली मार रेलवे बजट ने मारी है, दूसरी मार सैन्ट्रल बजट ने मारी है और तीसरी मार सागर राम गुप्ता जी ने चला दी। कटार सिंह जी ने तो अपनी कटार नहीं चलाई लेकिन इन्होंने कुल्हाडा चला दिया। इन भाब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करते हुए बैठता हूँ।

बहिन भान्ति देवी (करनाल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सन 1985-86 का बजट पे त किया। इस बजट के समर्थन में मैं इतना ही कहूंगी कि यह बजट बड़ी ही सूझ बूझ तथा पैनी दृष्टि का प्रयोग करके दूरदर्ितास के साथ तैयार किया गया है। इसमें एक दो कर भी लगाये हैं परन्तु ढेर सारी सुविधायें भी दी हैं जो आम जनता के लिये हैं। बजट अगले वर्ष की अनुमानित आय को लेकर ही तैयार होता है और उसी अनुमानित आय के अनुसार अनुमानित व्यय होता है और उसका आधार पिछले वर्ष की वास्तविक आय और व्यय होता है इसलिए उसमें कमी या कोई त्रुटि रहने का सवाल ही नहीं रहता।

इसलिये यह बजट सही, दुरुस्त और आम जनता के लिये लाभकारी है। हमारा देा विकास िल देा है। इसलिये विकास िल देा में बचत का बजट बनाना सम्भव नहीं तो कठिन जरूर होता है। इस कारण यह प्रदेा का भी घाटे का बजट है क्योंकि किसी भी विकास िल देा और प्रदेा के लिये बडी बडी आायेँ और आकांक्षायेँ होती हैँ। उनकी उन्नति और प्रगति के लिये प्रावधान रखना होता है। इस दृष्टि से भी घाटे का बजट रखने की परम्परा चलती ही रहती है ताकि हमारा प्रदेा धनधान्य पूर्ण और सम्पन्न हो। नागरिकों को सभी सुविधायेँ जुटाने का प्रयत्न सरकार की ओर से होता है ताकि सभी लोग प्रेम एकता और भ्रान्ति से रह सकें। हमारे प्रदेा ने सारे देा के प्रदेाों की अपेक्षा अधिक उन्नति करके एक मिसाल पेा की है। आजादी के बाद भुरु से ही देा की प्रगति योजनाबद्ध तरीके से भुरु की गई। पहले पांच पंचवर्षीय योजनायेँ बनायी और अब यह छठी पंचवर्षीय योजना भी खत्म होने जारही है। यह छठी योजना सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की योजना थी। इसमें गरीबी, बेरोजगारी और अिाक्षिता को दूर करने के सारे प्रयत्न और प्रयास रखे गये थे। इस योजना के दौरान जो चहुंमुखी विकास सभी क्षेत्रों में हुआ है, वह किसी से ओझल नहीं है लेकिन पूरा काम तो कभी किसी भी विकास िल देा या प्रदेा में खत्म नहीं हो सकता और आगे बढ़ने की कामना और आकांक्षा चलती ही रहती है। यह बात सभी भाई जानते हैं कि हमारे प्रदेा में प्रत्येक व्यक्ति की आय बढी है और गरीबी की लाईन से नीचे वाले परिवारों की संख्या

घटी है जैसे महंगाई में मूल्य बढ़ते रहे हैं उसके कारण कुछ कमियां भी रह जाती हैं। इस बजट में और भी बहुत सी सुविधायें सरकार कर्मचारियों को दी गई हैं। जन साधारण के लिये उचित मूल्य की दुकानें खोल कर लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है और प्रदेश का विकास की ओर भी बढ़ा है। लोगों को काफी सुख सुविधायें प्रदान की गई हैं। हमारी सरकार बिजली और कृषि के क्षेत्र में भी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये पूरा प्रयत्न और प्रयास कर रही है। दादुपुर में पन बिजली परियोजना और यमुना नगर में ताप विद्युत परियोजना शुरू होगी। इनके चाले हो जाने से हमें बिजली मिलेगी और हमारी सिंचाई की सुविधायें भी बढ़ेंगी। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए अच्छे खाद और अच्छी कृषि योजनाओं की आवश्यकता है ताकि लोग उन्नत तरीके से खेती करके अपनी आय के साधन बढ़ा सकें। इसलिये किसानों के ज्ञानवर्द्धन के लिये पत्र पत्रिकायें निकाली जा रही हैं और खेती के उन्नत तरीके सिखाने के लिए प्रशिक्षण कैंप लगाए जाते हैं यह हमारे प्रदेश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र के लिये बहुत ही उन्नति का तरीका है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी बात हो रही थी कि हमारे यहां पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पानी की कमी है लेकिन सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना को चलाने का प्रयत्न जोरों से हो रहा है ताकि लोगों को पानी मिल सके और प्रदेश में हरियाली आ सके।

इस बजट में यह भी एक घाटे की मद का कारण है। उसके लिये हमें केन्द्र से सहायता मिल गई तो वह घाटा पूरा होने की आशा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, बाढ़ का प्रबन्ध करने के लिये भी नाला नम्बर आठ की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों की फसल का नुकसान न हो और गेहूं, कपास, चावल और गन्ना अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न हो। जहां हमारी सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए प्रबन्ध किया है उसके साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फल और सब्जी उगाने पर जोर दिया है। इसलिये इस बजट में उसके लिए पैसे का प्रावधान किया गया ताकि लोगों को अच्छा भोजन और सुख सुविधायें मिल सकें। खेती करने वालों की आय भी बढ़ सके और कमजोर वर्गों की अवस्था भी सुधार सकें। इसी प्रकार से कमजोर वर्गों की अवस्था सुधारने के लिये मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और पशु पालन के लिये पैसा रखा गया ताकि वे भी अपनी आय बढ़ा सकें। चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में सरकार की ओर से पूरी देखरेख की जा रही है। बाकी जो भूमिहीन किसान और अन्य लोग हैं उनकी दशा सुधारने के लिये रोजगार की गारन्टी के अनुरूप सौ दिन काम देकर गरीबों को सहयोग दिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, उद्योग भी हमारे प्रदेश की प्रगति का बहुत बड़ा आधार है। उद्योगों की सफलता के कारण ही परिवहन, संचार चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों ने उन्नति की है। इन सबकी प्रगति का

श्रेय उद्योगों को ही है लेकिन इन उद्योगों से जो प्रदूषित और दुर्गन्धपूर्ण पानी निकलता है उसके लिये जो राशि रखी गई है उसमें और पैसे का प्रावधान जरूरी है क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर दुःप्रभाव पड़ता है, मनुष्यों के रोगी होने की सम्भावना रहती है उद्योगों में लगने वाले लोग धन के विशय में ही सोचने लगते हैं। वे मानव की सेहत के बारे में कम और धन के विशय में ही अधिक चिन्तित रहते हैं। इन उद्योगों के ऊपर जो भी कर्मचारी या अधिकारी निरीक्षण या देखभाल करते हैं, उन्हें ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें। दूसरे वे सच्चाई, ईमानदारी, उदारता और दया की भावना अपने अन्दर रखें ताकि गरीब मजदूरों से अमीर लोग एक तरह से दूसरे मनुष्य को मनुष्य समझ कर काम लें।

सरकार ने सडकें भी एक गांव से दूसरे गांवों में मिलाई हैं और भाहरों और मंडियों से मिलाना भी बहुत जरूरी है। जहां पर सडकें नहीं बनी हैं वहां सडकें बनायीं जायें और सडकों की मुरम्मत के लिये भी पैसे का प्रावधान रखा जाना चाहिये। और जहां सडकें नहीं बनी हैं वहां के लिए भी प्रावधान रखा जाना चाहिए।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। बहिन जी की भायद सरकार बात मान जाये। जिस प्रकार से पंजाब में व्हीट पर बोनस दिया है, उसी प्रकार यहां हरियाणा में

भी दे दिया जाये, यह बात भी बहिन जी कह दें तो उनकी बात को भायद सरकार मान लें यह किसानों के हित में है।

बहिन भान्ति देवी: सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जो बात आपको सूझती है वह, आप कहें या जो मुझे सूझती है वह मैं कहूंगी। आप इस बारे में कह सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दे आ और प्रदे आ में हर मनुश्य का शिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा से जहां भारीरिक विकास होता है, वहां मानसिक विकास व आत्मिक विकास भी होता है। इसके अलावा सामाजिक विकास भी होता है। उससे सोच विचार, आचार विचार और व्यवहार अच्छा बनता है। जीवन में नैतिकता आती है। बोल चाल, रहन सहन व एक दूसरे के काम आने की भावना बढ़ती है। इसलिये स्कूल अवयव ही अधिक से अधिक होने चाहिये। मेरी सरकार से प्रार्थना यह है कि भाहरों में प्राईमरी स्कूलों की ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनके लिये न तो भवन ही हैं और न ही उनमें बच्चों के बैठने के लिये अच्छा सामान उपलब्ध होता है भाहरों में केवल वे ही बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं जो बेहद गरीब होते हैं। चूंकि इनमें वर्दी या पुस्तकों आदि की सहायता दी जाती है इसलिए वे बच्चे वहां पर आते हैं। हालांकि प्राथमिक शिक्षा सारी पढाई का आधार है इसलिये सबसे बढिया प्रबन्ध प्राईमरी स्कूलों में चाहिए। गांवों के स्कूलों के बारे में मैंने कई बार देखा है कि बच्चों की हाजरी बहुत कम होती है। केवल ये चीजें जो उनको दी जाती हैं लेने के

लिये ही बच्चे वहां पर पहुंचते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं चिकित्सा केन्द्र और अस्पतालों के बारे में, विशेषकर करनाल के अस्पताल के बारे में जरूर कहना चाहूंगी। मेरा कहना यह है कि करनाल का अस्पताल बहुत पुराना है और इसको जल्दी से जल्दी नया बनवायें और इसी बजट में उसके पूर्ण निर्माण के लिये प्रावधान रखें। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूँ कि सिविल हस्पताल करनाल जल्दी से जल्दी बनावाया जाये। इसके अलावा, मैं सफाई कर्मचारियों के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि इनको सुविधायें देने के लिए ज्यादा पैसा रखा जाये ताकि उनको मल उठाने में सुविधा हो सके। उनको इस सुविधा हेतु रेहडियां आदि मिलनी चाहियें। आप जानते हैं कि भाहर बहुत दूर तक फैल गया है। वहां पर कहीं पर भी नजदीक मल फैंकने के लिये जगह नहीं है। वे लोग गलियों में डाल देते हैं और नालियों में ही डाल देते हैं जिससे वहां पर गन्दगी फैली रहती है। हरिजनों की, भूतपूर्व सैनिकों की और भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की सहायता के लिये भी इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम भी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा, जो टैक्स यहां पर लगाए गए हैं, उनके बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ कि सरकार को कोई दान तो देता नहीं उल्टे सरकार से अनुदान लेते ही हैं। इसलिये सरकार के लिये टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। टैक्स लगाए बिना काम चल ही नहीं सकता। लेकिन सरकार को टैक्स भी सही सही लगाने चाहियें। जो टैक्स आलरेडी लगे हुए हैं, उनकी स्ट्रिक्टली वसूली होनी

चाहिये क्योंकि जैसे इन्कम टैक्स है या कोई भी दूसरा टैक्स है, लोग आजकल बहुत होठियार बन गए हैं और देते नहीं हैं। जो वकील होते हैं, इन्कम टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, वग कोई न कोई टैक्स बचाने का तरीका निकाल ही लेते हैं। इस वजह से स्टैट को टैक्स मिलता ही नहीं है। अभी बसों पर सवा पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। मुझे पता है कि हमारे यहां से दिल्ली का किराया सन 1939-40 में सिर्फ एक रूपया लगता था। 1960-61 में दो रूपया हो गया लेकिन अब यह किराया 12 रूपया के तलगभग हो गया है। देखने की बात यह भी है कि आजकल सुविधायें भी बढ़ी हैं। आय के साधन भी बढ़े हैं इसलिये किराया बढ़ाना भी स्वाभाविक ही है क्योंकि हम तो यह चाहते हैं कि जन साधारण की आमदनी बढ़नी चाहिए। इतनी आमदनी जरूरी होनी चाहिये जिससे प्रदेश में विकास के काम हो सके। भाराब के उपर जो टैक्स लगाया गया है इसके बारे में मैं यह कहती हूं कि यह बेतक और ज्यादा लगाया जाये। यह तो बहुत ही बुरी आदती है। हमारे समय में बहुत कम लोग ऐसे हुआ करते थे जो भाराब पीया करते थे। लेकिन आज उनकी संख्या काफी बढ़ गयी है। मैं यह चाहती हूं कि इस बुराई को टैक्स लगाकर या किसी और तरीके से अब यही प्रदेशों से दूर किया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, यही नहीं, बजट में काफी लोगों को राहत भी दी गयी है। तन्दूर वालों और ढाबे वालों को भी टैक्स से राहत दी गयी है। बस का यात्री अब अपने ठिकाने पर पहुंच कर या बीच में भी सस्ती रोटी खा सकेगा। बहिनों द्वारा पहनने वाली चूड़ियों में भी

टैक्स की रियायत दी गयी है। पैंसिलों पर टैक्स की रियायत देकर भी लोगों को राहत दी गयी है। टैक्स परपजिज के लिये व्यापारियों को भी 25000 से बढ़ा कर 100000 रूप्ये तक की टर्न ओवर अलाऊ की गयी है। कृशि में प्रयोग होने वाले पम्पिंग सैटस के लिये भी राहत दी गयी है। बायोगैस प्लांट में प्रयुक्त होने वाले संयंत्रों पर भी टैक्स से छूट दी गयी है। मैं करनाल के भाईयों की ओर से अपने मुख्यमंत्री जी से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि जो बर्नर्ज बायो गैस के काम ही आते हैं और किसी दूसरे काम नहीं आते हैं, अगर सरकार उनके ऊपर टैक्स की छूट दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, चक्की वालों के लिये डेढ सौ क्विंटल गेहूं से बढ़ाकर सीमा 300 क्विंटल की कर दी गयी है। यह चक्की वाले जरूरत मन्द आदमियों को ठीक आटा दें, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा ताकि यह लोग हमारी इस रियायत का दुरुपयोग न कर सकें। इन भाब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद!

चौधरी मांगे राम (बहादुरगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, वित्त मंत्री ने जो बजट इस हाउस में पे 1 किया है, उससे हरियाणा के आम आदमी को चोट लगी है। बसों के किराये बढ़ाये हैं। बिजली के रेट बढ़ाये हैं। इनके सिवाये लोगों को कुछ नहीं दिया है। पिछले साल के बजट में दी गयी राहत के अलावा कुछ नहीं किया गया है। हरियाणा में आज लगभग 5 लाख के करीब नौजनवान बेरोजगार हैं। पिछले साल डिप्टी स्पीकर साहब, रोहतक

कोआप्रेटिव बैंक में 53 लोगों की भरती की गई। आप यह जानकार हैरान होंगे कि रोहतक जिले का एक भी लडका उनमें नहीं लिया गया। इसके बजाये उसमें ऐसे लोगों को भरती किया गया जिन्होंने दरखास्तें भी नहीं दे रखी हैं या जो मौके पर इन्टरव्यू के लिये भी नहीं आये थे। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे ज्यादा रोहतक जिले के साथ अन्याय क्या होगा ? आज सारे हरियाणा का किसान दुःखी है लेकिन रोहतक जिले का किसान बहुत ज्यादा दुःखी है। इस जिले ने देा की रक्षा के लिये हजारों लाखों नौजवान न्यौछावर कर दिये, लेकिन आज वहां के लोग बिजली और पानी के लिये तरसते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के बहादुरगढ में तहसीलदार ने सरेआम लूट मचा रखी है। यह वही तहसीलदार है जिसको चौधरी बंसी लाल ने अपने टाईम में जेल भिजवाया था। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री ए0सी0 चौधरी पदासनी हुए) 10-15 साल सस्पेंड रहने के बाद बहाल होकर अब यह बहादुरगढ में लगा हुआ है और अपने आपको चौधरी भजन लाल का दोस्त बताता है। (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापति: यह नाम रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी मांगे राम: चौधरी साहब, मैं कभी भी सदन में झूठ नहीं बोलता बेाक आप मंदिर में ले जाकर मुझे कसम उठवा लें। चेयरमैन साहब, यह तहसीलदार रजिस्ट्री पैसे लेकर करता है। लोगों को कहता है कि मुझे इतना पैसा दो तक करूंगा। किसी से

500 किसी से 400 रूपये लेकर रजिस्ट्री करता है। इसी तरह से दाखिल खारिज के वक्त भी कोई न कोई अडंगा लगा देता है, अगर इसको पैसा न दिया जाये। अगर पैसा दे दिया जाये तो सब ठीक हो जाता है। चेरमैन साहब, इसी तरह से हमारे यहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी का सैक्रेटरी भी सरेआम लूट रहा है। भाहर में कमेटी के दफतर के साथ कमेटी की बहुत ही कीमती जमीन थी। उस आदमी ने 10000 रूपये लेकर पिछले सप्ताह जिस आदमी का वहाँ पर खोखा थासा, उसकी पक्की दुकान बनवा दी। इसी सैक्रेटरी ने वाटर वर्कस के ऊपर 70 भी म के दरखत लगाए हुए थे। उनको 40 हजार रूपये का बेच दिया जबकि कमेटी के रिकार्ड में केवल 8000 रूपये के बिके हुए दिखाये हैं। इसी तरह से चेरमैन साहब, सब्जी मंडी के प्लाटस तो खत्म हो गए थे लेकिन उसके साथ ही हाई स्कूल की जमीन थीं, उसने उसमें 4 प्लाट के लाइसेंस जाली तौर पर जारी कर दिये। यही नहीं, इस सैक्रेटरी के बारे में बहुत सी बातें हैं, जो आब्जेक्टिव नबल हैं। वह दिन में दफतर में भी भाराब पीये रहता है। एक दिन जब मेरे भाहर के अखबार वाले उससे मिलने के लिये गये तो वह बुरी तरह से डाउन था, उसने उनको बाहर भगा दिया। जब हम कहते हैं कि भाई, ऐसा न करो तो वह उल्टा पुलटा बोलता है। (व्यवधान व भाोर)

17.00 बजे।

चेयरमैन साहब, मेरे हल्के के स्कूलों में फर्ज नहीं है जिन पर बच्चे बैठ सकें। मास्टर्स के लिये कुर्सी नहीं हैं और बच्चों के लिये पीने का पानी नहीं है। बच्चे पीने का पानी घर से ले जाते हैं। चेयरमैन साहब, चारों तरफ लूट मच रही है। चेयरमैन साहब, मेरे हलके में अस्पतालों को बहुत बुरा हाल है। पिछले हफ्ते सी०एम०ओ० ने प्राईवेट दुकानों पर रेड किया था और वहां पर अस्पतालों की दवाईया पकड़ी गई थी। उन दुकानदारों का चालान हुआ था। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने बसों का किराया तो बढ़ा दिया लेकिन जितनी पुरानी बसें हैं वे रोहतक डिपो को दे रखी हैं। उन बसों का हाल यह है कि वे अपना सफर पूरा तय नहीं कर पातीं और रास्तों में ही खड़ी रह जाती हैं। चेयरमैन साहब, बहादुरगढ़ जी०टी० रोड पर दिल्ली के नजदीक है और यह बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर केवल बस स्टैंड बना हुआ है। अपोजी न का मैम्बर होने की जवह से वहां पर सब डिपो नहीं बनाया जाता। अगर वहां पर सब डिपो बन जा तो लोगों को काफी सहूलियत हो जाए। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने बिजली के रेट तो बढ़ा दिये लेकिन बिजली मिलती नहीं है। मेरे हलके में नांगलाई और नजफगढ़ जगहों से सत्तर फीसदी इंडस्ट्रीज बिजली न मिलने के कारण बाहर चली गई हैं। मेरे हलके के साथ बहुत अधिक भेदभाव किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि 1982 के इलैक्शन में रोहतक जिले की दस सीटों में से नौ सीटों पर अपोजी न ने कांग्रेस को चोट मारी थी। चेयरमैन साहब, अन्त में मैं सारे सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस बजट को पास न करें।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला कौन्ट): आदरणीय चेयरमैन साहब, श्री सागर राम गुप्ता, वित्त मंत्री, हरियाणा ने 20 मार्च को जो वर्ष 1985-86 का बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। (व्यवधान व भाँर) मैंने तो कभी दल बदला नहीं है। आप लोगों में तो ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पांच पांच बार दल बदला है। (भाँर एवं व्यवधान) चेयरमैन साहब, हर सेशन में इनका लीडर दल बदलता है और हर सेशन में नया नाम होता है। चेयरमैन साहब, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की मृत्यु पर सारी दुनिया ने काफी अफसोस जाहिर किया जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। उनकी मृत्यु से देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उनकी वह कमी पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये अपोजीशन वाले उनके साथ भी कुछ जोड़ देते हैं। (भाँर एवं व्यवधान) मौत और मातम के मामले में तो भाँति रखनी चाहिए। चेयरमैन साहब, श्रीमती इन्दिरा गांधी के काम की जितनी तारीफ की जाये उतनी थोड़ी है। (भाँर एवं व्यवधान) चेयरमैन साहब, उनकी मौत के साथ एक भाँनदार पीरियड खत्म हो गया।

प्रो० सम्पत सिंह: चेयरमैन साहब, बहुत ही मजाक में इनको बात को नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही सीनियर मैमबर हैं। इनको बजट पर बोलना चाहिए। (भाँर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग भाँति रखें और इनकी बात को सुनें। मैं समझता हूँ कि मैं हाउस की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराने में पूरी तरह सक्षम हूँ।

सेठ राम दास धमीजा: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की मौत के साथ एक भानदार युग खत्म हो गया। हमारे देश की खुशकिस्मती है कि देश की समझदार जनता ने पूरी समझदारी से नौजवान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को चुन कर अपनी समझदारी का सबूत दिया और अपोजीशन के मुंह पर ऐसी चपत मारी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है।

एक आवाज: चेयरमैन साहब, चपत का भावद ऐक्सपंज होना चाहिए।

श्री सभापति: किसी का नाम नहीं लिया गया। मेरे ख्याल में यह लफज कोई अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

सेठ राम दास धमीजा: चेयरमैन साहब, कांग्रेस पार्टी को या प्रधान मंत्री को आज तक इतना बहुमत नहीं मिला जितना की आज मिला है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत एक युवा प्रधान मंत्री की लीडरशिप में हुई है। चेयरमैन साहब, अभी चन्द्र रोज पहले भारत सरकार का बजट आया है और हर तबके ने इस बजट की तारीफ की है। (गौर एवं व्यवधान) अपोजीशन वाले अपने बारे में सोचें। चेयरमैन साहब, प्राइम मिनिस्टर ने और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय जो वचन जनता को दिया था और कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ अपने मैनिफैस्टों में कहा था उसको पुरा करने के लिए पार्टी और प्रधान मंत्री वचनबद्ध है और उसको

अव य पूरा किया जाएगा। भारत सरकार के बजट को एक बहुत ही बढ़िया बजट कहा जा सकता है। (तोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: मैं समझता हूँ कि आप लोग काफी हयूमरस मूड में हैं। मैं चाहूंगा कि आप कृपया सुनने की कृपा करें।

सेठ राम दास धमीजा: चेयरमैन साहब, हरियाणा सरकार ने फी आदमी की आमदन में वृद्धि की है। चार साल में 61 परसैंट की बढ़ौतरी हुई है। चेयरमैन साहब, छठी योजना जो 1980-85 तक थी और जिस पर 1800 करोड रूपया खर्च होना था और उस पर अन्दाजन 1638 करोड रूपया खर्च होंगे इनमें से कुदरती आफतों के कारण योजना स्कीमों पर 35 करोड रूपए खर्च हुए हैं। सिंचाई विभाग पर तथा बिजली पर 966 करोड रूपया खर्च किया गया है जो कि योजना खर्च का 59 परसैंट है। इससे 3.52 लाख हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई बढी है और ट्यूबवैल्ज की तादाद लगभग एक लाख बढ गई है और बिजली की पैदावार लगभग 362 मैगावाट बढी है। चेयरमैन साहब, फिर भी बिजली की कमी है इसमें कोई भाक की बात नहीं है। हरिजन और पिछडी जातियों और गरीबी की लाइन से नीचे के लोगों की बेहतरी की खास ध्यान रखा गया है और तकरीबन 16.5 करोड रूपया का योजना खर्च किया गया है।

चेयरमैन साहब, हरियाणा की जनता की तरक्की की स्कीमों के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3200 करोड़ रुपये का अनुमान बनाया गया है। आप ही सोचें कि इस सरकार की स्कीमों से कितने गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो आदेश दिये हैं उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने काम करवना आरम्भ किया है। और हरियाणा में खुदहाली लाने के लिये सभी प्रकार के साधन जुटाने के प्रबन्ध (जैसे कि सिंचाई, बिजली, इंडस्ट्रीज आदि) इस सरकार ने किये हैं। और इस तरफ खास तवज्जो दी गयी है ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। लोगों की तरक्की के साथ साथ पीने के पानी की भी सुविधा लोगों को दी गयी है। जहां तक एस0वाई0एल0 का ताल्लुक है। इस बारे में आई0पी0एम0 साहब ने पहले ही तफसील के साथ बता दिया है। मैं आपको बताता हूं कि मैं 23-3-1985 को ननयोला के पास कपूरी गांव में होकर आया हूं और अपनी आंखों से नहर खुदती देख कर आया हूं। वहां पर काम जोरों से हो रहा है। इन अपोजी तान के भाईयों का तो चेयरमैन साहब, काम ही यही है कि हर वक्त सरकार की यूं ही फिजूल में आलोचना करना। वहां पर एक रूडकी गांव है, वहां पर बुल्डोजर चल रहे हैं, और जमीन को साफ और बराबर कर रहे हैं। काम नहर

काच चल तो रहा है लेकिन जिस रफतार से होना चाहिये भायद उस रफतार से वह काम नहीं हो रहा है। इस ओर सरकार को और ध्यान देना चाहिये। यह जो एस0वाई0एल0 है, यह हरियाणा

के लिये एक वरदान है। (गोर) चेयरमैन साहब, मैं इन अपोजी उन के भाईयों से यह कहना चाहता हूँ कि अढाई साल पहले जब इनके चीफ मिनिस्टर थे, इनकी सरकार थी और उधर श्री प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे, दोनों आपस में सगे भाई थे, उस वक्त उन्होंने इस नहर के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर उन्होंने अढाई साल के वक्ते में इस नहर के बारे में कोई काम किया होता तो ये आज बात करने के काबिल होते। आप हमारे चीफ मिनिस्टर और अपने चीफ मिनिस्टर से तुलना करके तो देखों जितना काम अब चौधरी भजन लाल की रहनुमाई में हरियाणा की तरक्की का हो रहा है उतना आपके वक्त में क्या हुआ था। यूँ ही यहां दखल अन्दाजी करने का क्या फायदा ? कोई ठोस काम करके तो दिखाते जितना कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है और कर रहे हैं। मैं तो यह कह सकता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने जो रूपये हमें नहरे पक्की करने के लिये दिये हैं, उनसे काम तसल्लीबख्शा चल रहा है। 1983 में 25 करोड वर्ग फुट नहर पक्की करनी थी उसमें से 8.6 करोड मुरब्बा फुट को पक्का करने का काम पूरा हो गया है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंघ: चेयरमैन साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि जिस बजट स्पीच को वित्त मंत्री महोदय पहले यहां हाउस में पढ चुके हैं उसका क्या कोई दूसरा मैम्बर दोबारा पढ सकता है ?

श्री सभापति: रूलज के मुताबिक यहां इस तरह की कोई मनाही नहीं है। He can make out his points by referring to the Budget speech.

श्री वीरेन्द्र सिंह: चेयरमैन साहब, जो आंकड़े इस किताब में दे रखे हैं उनको ये पैरावाइज पढ़ कर रिपीट कर रहे हैं। आप कृपया टाईम का भी ध्यान रखें आपने बाकायदा तौर पर हर मैम्बर के लिये टाईम अलाट किया हुआ है। आप यह बता दें कि आप ने हरेक मैम्बर को कितना कितना टाईम अलाट किया हुआ है और इनको बोलने के लियें कितना टाईम अलाट कर रखा है ?

श्री सभापति: इनके लिये 15 मिनट का समय अलाटा किया हुआ था। 12 मिनट धमीजा साहब बोल चुके हैं तीन मिनट इनके और रहते हैं। जहां तक इनके बोलने का सम्बन्ध है, किसी चीज की रेफरेंस के लिये अगर ये किसी बात को दोबारा कोट करते हैं, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। धमीजा साहब, आप बोलें।

सेठ राम दास धमीजा: सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि बाढ़ से लोगों को बचाने के लिये इस साल 14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इनको तजवीज देता हूँ कि अगर अम्बाला छावनी को फलड से बचाना है तो इसके लिये और पैसे का प्रावधान रखा जाना चाहिये। इस तरफ सरकार तवज्जो दे। इस काम के लिये इतना थोडा पैसा रखा जाना। हरियाणा के

लोगों के लिये हितकर नहीं है। इसलिये इस राशि को और बढ़ाया जाए।

इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिये अच्छे अच्छे तरीके अपनाये जाने चाहियें जिससे 220 मैगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ पाएगा। यहाँ अम्बाला भाहर और छावनी में तकरीनब 7 हजार के लगभग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, इनको बचाने के लिये बिजली की सप्लई बहुत आवयक है और इसके लिये सरकार को नये नये तरीकों को अपनाना चाहिये ताकि बिजली का उत्पादन ज्यादा हो सके और इंडस्ट्रीज को भी बचाया जा सके। हरियाणा का टोटल ऐक्सपोर्ट का वन थर्ड अम्बाला जिला ही कवर करता है। इसके अनुसार इंडस्ट्रीज के लिये ज्यादा बिजली का दिया जाना हमारा हम भी बनता है।

श्री सभापति: धमीजा साहब, आपका समय हो रहा है। आप वाइंड अप करें।

सेठ राम दास धमीजा: चेयरमैन साहब, अम्बाला की डिवैल्पमेंट के दो आधार हैं। एक मिल्टरी और दूसरा साईंस इंस्ट्रूमेंट्स का बनाया जाना। अगर हमारे इलाके को बिजली की सप्लई कम होगी तो काम भी कम होगा और वहाँ की रौनक आधी रह जाएगी।

अगले वर्ष के दौरान 2500 बायोगैस संयन्त्र लगाने का सरकार का विचार है और बर्नर्ज पर टैक्स लगाने की भी व्यवस्था है। यह टैक्स नहीं होना चाहिये। बर्नर्ज जो होते हैं, वे बायोगैस का दिल होते हैं। इस तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिये।

सरकार की तरफ से पशुपालन, मछली पालन तथा डेरी विकास परियोजनाओं पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। गांवों के विकास कार्यक्रम के लिये 88700 परिवारों को सहायता प्राप्त होगी। इस तरह के बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है। मरुभूमि और सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये 4.89 करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार का विचार है।

चेयरमैन साहब, मैं आगे यह कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा करनाल में 1300 करोड़ रुपये की लागत से एक रिफाइनरी और पंचकुला में 21 करोड़ रुपये की लागत से एक दूर संचार परियोजना का कार्य करवाने का विचार भी एक प्रशंसनीय कदम है। हरियाणा में रेलवे कोच निर्माण फ़ैक्टरी लगाने का मामला भी काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और यह फ़ैक्टरी हरियाणा में अम्बाला में ही होनी चाहिये क्योंकि अम्बाला छावनी एक बड़ा भारी जंक्शन है और एक बड़ा रेलवे का डिवीजन है। यह फ़िरोजपुर से लेकर मुरादाबाद तक के एरिया को कवर करेगा। चेयरमैन साहब, अम्बाला में किंगफ़िगर नाम से एक टूरिस्ट कम्प्लैक्स अगले साल तक बनाये

जाने का विचार है। यह हमारे हलके के लिये एक खुा किस्मती होगी। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 20 सूत्री प्रोग्राम है, वह हरियाणा के लिए एक वरदान है। जितना पैसा इस पर सरकार खर्च करने जा रही है अगर वह सारा रूपया गरीबों के घरों तक पहुंच जाए तो इससे लोगों को काफी भला होगा। इस प्रोग्राम के ऊपर और विचार करने की आवश्यकता है।

चेयरमैन साहब, इस सरकार ने और भी बड़े अच्छे अच्छे काम किये हैं, अन्धे, अपाहिज, दुर्बल, भारीरिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिये सरकार ने सही कदम उठाये हैं। उनका भत्ता 50 रूपये से बढ़ाकर 75 रूपये कर दिया गया है, यह एक अच्छा कदम है। अब मैं टैक्सिज की तरफ आ रहा हूं। सरकार की तरफ से कई नये टैक्स लगाये गये हैं जो कि नहीं लगने चाहिये थे। अगर टैक्स लगाने ही थे तो तनखाहें भी बढ़ाई जानी चाहिये थी, भत्ते भी देने चाहिये थे। टैक्स अगर लगाने हैं तो मुनासिब होने चाहिये। बिजली पर दो, तीन चार पैसे जो रेट बढ़ाया गया है, इस पर अपोजी न वाले कहते हैं कि यह बडा भारी जुल्म है। इसके बारे में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका भार कंज्यूमज के ऊपर नहीं पडेगा। यह तो सरकार के कागजों तक ही है। इसमें किसी पर कोई भार नहीं पडने वाला है। डा0 मंगल सैन जी इस समय बैठे नहीं हैं वरना मैं उनको बताता कि चूडिया क्या होती हैं ? सरकार ने चूडियों पर 12 प्रति 1 की बजाए 4 प्रति 1त सेल्ज टैक्स किया है। लेकिन इसमें

लफज लिखा है कांच की चूडियां। मैं चाहता हूं कि इसके साथ प्लास्टिक और रबड की चुडियों पर भी यह छूट होनी चाहिये। सेल्ज टैक्स के मामले में मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। मैं खुद व्यापारी हूं इसलिये ये बातें कहना चाहता हूं। हरियाणा में ट्रकों पर सेल्ज टैक्स 10 प्रति टन है जबकि गोआ में यह 3 प्रति टन है। हमारे एक ट्रक का टैक्स 18500 रूपए बनता है जबकि गोआ में 5200 रूपए बनता है। इस साल हरियाणा में गोआ दमन से दो हजार ट्रक आए हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोग गाओ से ट्रक मंगवा कर देते हैं वे दो हजार फी ट्रक लेते हैं। जिसमें 1500 रूपया किराए का होता है और 500 रूपया उसका कमी टन होता है। सरकार अगर मेरी तजवीज को माने तो ट्रकों पर 5 प्रति टन टैक्स कर दें। इससे एक ट्रक पर सरकार को 9250 रूपए टैक्स के मिलेंगे। अब जो लोग गोआ से ट्रक मंगवाते हैं उनको तीन परसेंट के हिसाब से 5200 रूपया तो टैक्स देना पडता है और दो हजार रूपया उसको देते हैं जिसके थ्रू मंगवाते हैं। इस तरह से उसको 7200 रूपया देना पडता है। अगर सरकार यहां भी 5 प्रति टन टैक्स कर दे तो उसको केवल 2050 रूपए और देने पडेंगे जो कि वह दे भी देगा। ऐसा करने से सरकार की आदमनी में बहुत इजाफा होगा। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में भी हमारे से कम सेल्ज टैक्स हैं। आन्ध्र प्रदेश में तो तीन टन से पांच टन तक के व्हीकल पर कोई टैक्स ही नहीं है मेरे भाई म्यूनिसिपल

कमेटी के इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बड़ा बावेली कर रहे हैं, उसको भी हम देख लेंगे!

श्रीमती चन्द्रावती: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय धमीजा साहब बड़े अच्छे ढंग से बातें कहते हैं। हम चाहते हैं कि इनके लिए एक दिन सै। इन और बढ़ा दें। उस दिन केवल इन्हीं की स्पीच करवा देना, हम सुनते रहेंगे।

सेठ राम दास धमीजा: चेयरमैन साहब, अठारह साल तक इनकी हकूमत रही इन्होंने म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव क्यों नहीं करवाए ? हमारे सी०एम० साहब ने हाउस के फ्लोर पर वायदा दे दिया है कि इसी साल इलेक्ट्रॉनिक्स करवा देंगे। इन भावों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बजट को सर्व सम्मति से पास किया जाए।

सरदार सुजान सिंह (जुंडला, अनुसूचित जाति): आनरेबल चेयरमैन साहब, मान योग वित्त मंत्री जी ने जो 1985-86 का बजट सदन में पेश किया है इससे प्रान्त की जनता के मन में खुशी होने की बजाये उनके चेहरों पर उदासी छा गई है क्योंकि यह 1 करोड़ 43 लाख की आबादी का छोटा सा सूबा है और यह 114.32 करोड़ रूपए के घाटे वाला बजट उस पर ठोसा गया है। इसके घाटे को पूरा करने के लिये कहते हैं कि प्रोविजन किया गया है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल असिस्टेंस लेकर 70 करोड़ रूपया पूरा किया जाएगा और बाकी जो कमी है उसको

पूरा करने के लिए देना के जो ज्यादा मैजोरिटी के लोग हैं जो बसों में सफर करने वाले हैं उन पर 20 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) एक और बात जो बजट में कही गई है वह यह कि गरीबों को गरीबी की लाइन से ऊपर उठाएंगे। एक साल की जो इन्होंने फिगर बताई है वह 1.5 प्रतिशत है। प्रान्त में रहने वाले गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं वे 30.2 प्रतिशत हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा में जो गरीबी को दूर करने का सवाल है वह बीस प्वायंट प्रोग्राम के अधीन बीस सालों में पूरा होगा। इसी तरीके से जो कर्मचारी हैं, बजाए उनको एडीशनल तनख्वाह देने के जो वे लोन लेते हैं केवल उसको बढ़ाया गया है। आप्रेशन ब्लू स्टार में मरने वाले सैनिकों के परिवारों को जो राहत दी है वह भी नाम मात्र है। तो मैं कह सकता हूँ कि यह बजट समाज के कमजोर और दलित वर्ग के लिए कोई विशेष रिलीफ नहीं देता। इसके साथ साथ सरकार ने क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग योग्य व्यक्ति होते हैं लेकिन पोलिटिकल इंटरफियरेंस की वजह से तमाम सर्विसिज पोलिटिकलाइज्ड को चुकी हैं। रिजल्ट के तौर पर आज जहां ऐडमिनिस्ट्रेशन में डिमौरलाइजेशन आई है वहां इन ऐफिंटेन्सी भी इम्प्रूव हुई है। पिछले नवम्बर के दंगों में ऐडमिनिस्ट्रेशन का बुरा हाल हुआ है। उसको कन्ट्रोल करने में ऐडमिनिस्ट्रेशन अनकलींड रहा है क्योंकि पोलिटिकल इंटरफियरेंस ज्यादा था। स्पीकर साहब, 31 अक्टूबर को देना की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का उनके दो सिख अंगरक्षकों ने वैयाना कत्ल

किया। श्रीमती गांधी ने एडिशन गेम्ज, चोगम और नान एलाइंड कन्ट्रीज मीट करवा कर जहां देना नाम ऊंचा करवाया वहां अपना नाम भी संसार भर में ऊंचा करवाया है। आईपीसी के अधीन चाहे कोई देना द्रोही हो या 302 का मुलजिम हो, दोशी वही होता है जिस पर इलजाम लगाया जाता है। लेकिन बदनसीबी से हुआ क्योंकि श्रीमती गांधी के कत्ल के बाद देना में जितने भी केना धरी लोग रहते थे उनका कत्तेआम किया गया। उनकी जायदाद या तो लूटी गई या जलाई गई माइन्योरिटी कम्युनिटी अपने ही आजाद देना में भारणार्थी बन गई। आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया था कि हरियाणा में सब अच्छा है। लेकिन यहां जबाबंदी है। पाबंदी भी लगाई गई है कि बहुत बात नहीं करनी। मैं देना की बात नहीं करूंगा और पूरे प्रान्त की भी बात नहीं करूंगा। मैं तो केवल एक मिसाल कोट करता हूं। हमारी अपनी हरियाणा विधान में नाम का मुलाजिम है।

श्री अध्यक्ष: आप किसी का नाम क्यों लेते हो ?

सरदार सुजान सिंह: चलो जी ठीक है मैं यह कह देता हूं कि वह हरियाणा विधान सभा का कर्मचारी है जो कि जूनियर ट्रांसलेटर है। उसका गांव होद है, पुलिस स्टेशन जाटुसाना पडता है जो जिला महिन्द्रगढ में रिवाडी के नजदीक है। स्पीकर साहब, 2-11-84 को पटौदी से एक बस और ट्रक दंगाकारियों के भर के आये। उसके परिवार के 17 आदमी जिन्दा जला दिए गए

जिनमें से 4 बच्चे, 6 मर्द और 7 औरतें थीं। पहले उनको लाठियों से पीटा गया और जब वे अध मोये हो गए तो उनके ट्रैक्टर से ही डीजल निकाल कर उनको जिन्दा जला दिया। जहां तक औरतों की बेपत्ती का सवाल है वह मैं बयान नहीं कर सकता। सो मैं आपके द्वारा सरकार से बेनती करता हूं कि जैसे आपने इन ब्ल स्टार के बाद लूट मार का सामान बरामद किया था उसी तरह से एस0एच0ओ0 जाटु साना से भी लूट मार का सामान बरामद करें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, यह बात कह कर तो ये जनरलाइज कर रहे हैं। ये भाब्द रिकार्ड में नहीं आने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ठीक है फौजी अफसरों वाली बात रिकार्ड न की जाए।

सरदार सुजान सिंह: आनरेबल स्पीकर साहब, जब हुक्मरानों के विचारों में वायलेंस आ जाता है तो वह लोगों के हितों में नहीं होता। सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट खोला हुआ है। मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि इसी तरीकै से एक पुलिस सुपरविंग बनाया जाए जो ला एंड आर्डर सिचुएशन को इफैक्टिवली डील कर सके और उसमें जो सैकुलर पुलिस आफिसर्स हैं उनको लगाया जाये। रीलिजयस प्लेसिज मंदिर,

मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को तबाह करने या धार्मिक पुस्तकों का अपमान करने या किसी भी व्यक्ति को धर्महीन करने से हो सकता है करने वाले को अच्छा लगे लेकिन जो सैंटीमेंट्स उनसे जुड़े होते हैं उनको उससे चोट आती है। सरकार का यह फर्ज बनता है कि उनको यह हीलिंग टच दे। आज दे 1 की अखण्डता और एकता को कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारी भाक्ति वाली फौज ने बंगला देश में, आसाम में, पंजाब में बडा इफैक्टिवली काम किया है। दे 1 के अन्दरूनी और बहरूनी खतरों को हमारी फौज अच्छी तरह से डील विद कर सकती है। लेकिन आज जो दे 1 को जरूरत है वह इमोशनल इन्टेग्रेशन को मजबूत करने की है। मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि दे 1 में जो भावनात्मक एकता कमजोर हुई है, उसे यह अपना सारा सरकार मीडिया लगा करके मजबूत करे ताकि दे 1 में सदभावना और भाई चारे का माहौल पैदा हो सके। आखिर में मैं बहुत ज्यादा समय न लेता हुआ यही कहूंगा कि यह जो बजट पे 1 किया गया है यह ऐन्टी दलित मजदूर और ऐन्टी किसान हैं तथा इसमें मुलाजिमों को कोई राहत नहीं दी गई है और न बेरोजगारों को कोई राहत दी गई है इसलिए इसको पास न किया जाए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से बिजली और पानी के बारे में संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहूंगा। माननीय सदस्यों की सारी बातों का जवाब तो हमारे वित्त मंत्री जी देंगे।

काफी माननीय सदस्यों ने अम्बाला जिले के किसानों के बारे में काफी चर्चा की है और कहा है कि अम्बाला जिले के किसानों को पानी और बिजली देने के बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, उनको कोई रियायत नहीं दे रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह पहली सरकार है जिसने अम्बाला जिले के किसानों को सिंचाई के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये बहुत ठोस कदम उठाए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भाहबाद नलवी इरीगे टन स्कीम जो है वह 15 करोड 37 लाख रूपए की स्कीम है। उस प्रोजैक्ट का हरियाणा गवर्नमेंट के पास 12-10-1983 को ऐस्टीमैट आया और इसके अनुसार मुलाना ब्लाक, अम्बाला ब्लाक, रादोर भाहबाद और कुरुक्षेत्र का कुछ इलाका भामिल है जिनकी लगभग 1 लाख 86 हजार एकड जमीन की सिंचाई के लिये 590 क्यूसिक्स कैपेसिटी की नहर बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है और यह स्कीम प्लानिंग कमी टन ने 7वीं पंचवर्शीय योजना में भामिल कर ली है तथा सेंटरल वाटर कमि टन को यह स्कीम 22-3-1984 को सबमिट की जा चुकी है। इस स्कीम के लिए 13 करोड रूपए प्रोवाइड किए गए हैं। वर्ष 1985-86 में सरकार ने इस स्कीम पर 77 लाख रूपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इसी साल में इस स्कीम पर काम भुरू होने की पूरी उम्मीद है। इसी प्रकार से नारायणगढ, रायपुरानी, बिलासपुर और सढौरा आदि के लिए एक दूसरी स्कीम है। इन इलाकों के लिए हथनी कुण्ड परपोज्ड बैराज से एक नहर निकाली जाएगी जिससे लगभग 1.75 लाख एकड

जमीन की सिंचाई होगी और इस नहर की लम्बाई 80 किलोमीटर होगी तथा 400 क्यूबिकस पानी की कैपेसिटी की नहर होगी। यह स्कीम अन्डर इन्वैस्टीगे ान है। इन्वैस्टीगे ान कम्पलीट होने के बाद सरकार सहानुभूति से प्रयत्न करेगी कि इस स्कीम को कार्यान्वित किया जाए। एक नहर दादुपुर से निकाली जाएगी और दूसरी हथनीकुण्ड बैराज से निकाली जाएगी। अम्बाला जिले में यह पहली नहर होगी जिससे फलो इरीगे ान होगी। चालू वर्ष के दौरान इस नहर के लिये 70 लाख रूपए प्रोवाइड किए गए हैं एक दूसरी स्कीम के लिए और पैसे रखे गये हैं। यदि पैसे का प्रावधान किया गया है तो काम भी भुरू होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इनके लिए 13 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्पीकर साहब, अब मैं माननीय सदस्यों को एम0आई0टी0सी0 के बारे में संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहूंगा। काफी माननीय सदस्यों ने यह बात कहीं कि सरकार किसानों को कोई सुविधाएं नहीं दे रही है, कोई रियायत नहीं दे रही है। मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो डायरैक्ट इरीगे ान ट्यूबवैलज हैं जिसको डी0आई0टी0 कहते हैं। पहले उनको बिजली का खर्चा 67 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता था। उसको 1-7-1984 से घटा कर 40 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। किसानों को लगभग 27 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से रियायत दी गई है। इसके अलावा स्पीकर साहब, चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने बोलते हुए यह बात कही कि भिवानी जिले का बहुत सा इलाका पानी के नीचे आ जाता है बिजली चली जाने की वजह से नहरों

में एसकेप वगैरह से फसलें खराब हो जाती हैं। इन्होंने मांग की थी कि सरकार वहां पर जमीन ऐक्वायर करके रिजरवायर बनाए। स्पीकर साहब, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार का यह विचार तो नहीं है कि किसानों से जमीन ऐक्वायर करके उनको उनकी जमीन से वंचित करे लेकिन इस बारे में इरीगे एंड डिपार्टमेंट बहुत गहराई से विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि जहां जहां पर पानी फसलों में जाता है और उनको खराब करता है वहां पर बड़े बड़े पम्प लगा कर उस पानी को वापिस नहर में डालने की योजना कार्यान्वित करेंगे ताकि किसानों की फसलें पानी से खराब न हों। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं रोहतक भाहर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैंने पहले भी हाउस में दो बार जिकर किया है कि सिरसा जिले में एक ओटू झील है जिसमें घग्घर नदी का पानी जाता है। यदि उस झील की खुदाई कर दी जाए तो उससे कम से कम 150 गांवों को फायदा हो सकता है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य चौधरी भागी राम जी को सिरसा जिले के बारे में पूछने की कहां फुरसत रहती है। अब बीच में इनको याद आ गया इसलिये पूछ लिया। इनका तो दूसरी बातों से वास्ता रहता है। मैं इस बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। इससे पहले मैं रोहतक के बारे में बताना चाहूंगा। डा0 मंगल सैन जी ने रोहतक भाहर के बारे

में जिकर किया और आज अखबार में भी इन्होंने खबर छपवा दी है कि “Rohtak City goes thirsty” मैं आपके द्वारा इनको बताना चाहूंगा कि रोहतक भाहर के लिए पीने के पानी के बारे में इरीगे ान डिपार्टमेंट ने जो काम किया है और कर सकता है उस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रोहतक भाहर को भालोट सब ब्रांच जिसको बी0एस0बी0 कहते हैं पानी सप्लाई करती है। यह नहर 17-2-85 से 24-2-85 तक चली और अब 21-3-85 से 28-3-85 तक चलेगी क्योंकि चार गुपों में नहरें चलती हैं और रोहतक भाहर के लिए जो वाटर कोर्स हैं उसको पक्का किया जा रहा है और आने वाली मौनसून तक उसको पक्का कर दिया जाएगा। स्पीकर साहब, 14-3-85 तक 100 क्यूसिक्स पानी देंगे और पिछले दिनों बगैर बारी के 50 क्यूसिक्स पानी दिया गया। इस वक्त रिजरीवायर में काफी मात्रा में पानी है। हमने महकमे को यह भी कहा है कि जब 28-3-85 को नहर बन्द हो जाएगी तो उसे बाद भी उसमें थोडा बहुत पानी छोड दें ताकि लगातार रिजरवायर के लिये पानी जाता रहे और इकटठा होता रहे। इसके अलावा स्पीकर साहब, अब मैं बिजली के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सदन के अंदर पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि हरियाणा प्रान्त के थर्मल काम नहीं करते। एक जनरल इम्प्रै ान क्रिएट करने के लिए लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि हरियाणा में बिजली की परिस्थति अच्छी नहीं है। मैं अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो थर्मल प्लांटस हैं उनकी परफारमेंटस किसी दूसरे थर्मल प्लांटस से कम

नहीं है। प्रोडक्शन के बारे में आज दिन में मैंने बात कह दी है इसलिये उसको दोहराऊंगा नहीं। जो औगजलरी कंजम्पशन और आयल कंजम्पशन है उसकी पिछले 7-8 महीनें में काफी बचत हुई है।

स्पीकर साहब, औगजलरी कंजम्पशन, स्टाफ और मेंटीनैस आदि पर पानीपत थर्मल प्लांट और फरीदाबाद थर्मल प्लांट में वर्ष 1983-84 और 1984-85 में जो बचत हुई वह इस प्रकार है :-

महीना	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन		फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन	
	1983-84	1984-85	1983-84	1984-85
अक्टूबर	23.20	13.85	17.3	12.76
नवम्बर	22.50	12.13	19.0	15.02
दिसम्बर	16.31	14.77	17.14	15.50
जनवरी	17.80	13.09	16.91	15.70
स्पीकर साहब, जो आयल कंजम्पशन हुई है वह इन सालों की इस प्रकार है:- (मिलीलीटर प्रति यूनिट				
अक्टूबर	68.60	25.73	52.18	22.00

नवम्बर	54.90	15.69	58.85	16.40
दिसम्बर	16.00	30.04	40.67	25.00
जनवरी	35.00	26.59	39.71	29.40

स्पीकर साहब, इस प्रकार केवल इन दो आइटम्ज पर ही पिछले साल के मुकाबले में 6 करोड रूपये की बचत की है। (विधन) उस वक्त ज्यादा खर्च था। आप उल्टा समझ रही हैं। हमारा इस समय 50 प्रति शत से कम खर्च है।

श्रीमती चन्द्रावती: ए०^{जी०} की 1982-83 की रिपोर्ट के मुताबिक तो उस समय बिजली पैदा नहीं हो रही थी। जब बिजली पैदा नहीं होगी तो खर्चा ज्यादा कैसे होगा ? (विधन)

चौधरी भाम शेर सिद्ध: स्पीकर साहब, इस समय स्टेट में कोई भी डैमेज्ड ट्रांसफार्मर नहीं है। इस साल 16 ग्रिड सब स्टेशन 33-33 के०वी० के चालू हो जाएंगे। अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगली योजना के अंदर 38 करोड रूपया फरीदाबाद थर्मल प्लांट की रैनोवे शन के लिये और 16 करोड रूपया पानीपत थर्मल प्लांट की रैनोवे शन के लिये रखा गया है ताकि इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। स्पीकर साहब, एक सवाल भागी राम जी ने ओटू लेक के बारे में किया था। ओटू लेक में सिल्ट की वजह से काफी बड़ा एरिया चोक हो चुका है अब उसका एम बैकमेंट ऊंचा किया है ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके।

वित्त मंत्री (श्री सागर राम गुप्ता): स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने हाउस में बजट की प्रोपोजल पर अपने अपने विचार रखे। सरकार के पक्ष के सदस्यों ने अपनी बातें कहीं और विरोधी पक्ष के भाईयों ने अपनी बातें कहीं। मैं आभारी हूँ सभी सदस्यों का, खासतौर से ट्रेजरी बेंचिज के सदस्यों का, जिन्होंने सरकार के इस बजट का खुले तौर पर स्वागत किया। जहाँ तक विरोधी पक्ष के सदस्यों की बातों का सम्बंध है, उन्होंने जो रचनात्मक बातें कही हैं। उनके बारे में मैं उनको सरकार की तरफ से वि वास दिला सकता हूँ कि उन सब बातों पर सरकार विचार करती रही है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। लेकिन जो बातें उन्होंने केवल इसलिये कहीं कि वे विरोधी पक्ष के भाई हैं, उस बोर में मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी तो है कि वे बहुत सोच समझ करके यहाँ बातें कहें लेकिन यह समय यहाँ पर कोई गलत बात का प्रचार करने का नहीं है। यह ठीक है कि यहाँ पर किसी भाई की नाजायज तारीफ नहीं करनी चाहिए। हमें हरियाणा को आगे ले जाना है। हरियाणा बहुत आगे बढ़ा है, इस बात को ये भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन हर बात में नॉक झॉक करें, यह भावना नहीं देता। इनका भी समय आया था। ये अपने गिरेबान में मुँह डाल कर देखें। इन्होंने भी अपना बजट पे 1 किया था। इन्होंने क्या राहत दी थी ? अब ये कहते हैं कि टैक्स लगा दिए गए। यह बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्स लगाये गये हैं। और बसों के किराये भी बढ़ाये गये हैं। स्पीकर साहब, अगर विरोधी पक्ष का कोई भी भाई इकोनोमिस्ट है और

वह फाईनैसिज की मैन्टीनैस का तरीका जातना है तो अब समय है कि वह जब एप्रोप्रिए इन बिल यहां आये और डिमांडज आये तो उन पर डिस्क इन के वक्त अपने रचनात्मक सुझाव दें। स्पीकर साहब, हम सभी दिल से चाहते हैं कि हरियाणा आगे बढ़े। हम यह चाहते हैं कि यहां पर सारी सुविधाएं हों हम चाहते हैं कि यहां पर मैडिकल कालेज हो। हम यह भी चाहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। हम यह भी चाहते हैं कि जो लोग गरीब परिवार के हैं उनको ऊपर उठाने के लिये तेजी से कदम बढ़ाये जाएं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सारा काम बिना धन के मुमकिन हो सकता है ? बिल्कुल नहीं हो सकता। स्पीकर साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि इनको अधिकार है कि ये रचनात्मक सुझाव दें, हम उनको स्वागत करेंगे लेकिन ये जो बातें for the sake of opposition only कहते हैं। वह हमारी समझ में नहीं आती। मैं एक बात आंकड़ों के जरिए कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आज हरियाणा की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये सारे दे । के किसी इकोनॉमिस्ट से इस बजट को एग्जामिन करवा लें और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि हर अच्छा इकोनोमिस्ट हमें सर्टिफिकेट देगा कि इससे अच्छा बजट और कोई नहीं हो सकता। यहां पर यह भी कहाव गया है कि इस बजट के अंदर 114 करोड रूपये का डैफिसिट है। (विघ्न) सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको हमारी बात सुनने का सब्र होना चाहिए। (विघ्न) आप चिन्ता न करें आपकी बात का भी जवाब दूंगा। लेकिन आप

सरकार की बात सुनिये। यहां यह भी कहा गया है कि यह बजट घाटे का बजट है। मैं इनके जवाब में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई डिवैलपिंग कन्ट्री या प्रदे । बिना डैफिसिट के आगे नहीं बढ़ा। सैन्ट्रल सरकार ने भी अपना बजट पे । किया है। उसमें भी टैक्स लगे हैं। हमारे यहां पर भी 114 करोड रूपये का डैफिसिट का प्रावधान इस साल में है। जो बातें मैंने बजट में कही हैं वह आपने पढी होंगी और इसके अलावा बजट से संबंधित जो लिटरेचर आपको दिया है, वह भी आप लोगों ने पढा होगा। इनके पढने के बाद आपने देखा होगा कि हम अगले साल में छलांग मार कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, इस डैफिसिट को हमने करवर करने के लिए बडे अच्छे ढंग से प्रावधान किया है। यह आप लोगों ने इस बजट में देखा भी होगा। मैं इस गरिमापूर्ण हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब यह साल खत्म होगा तो उस समय आप देखेंगे कि यह डैफिसिट को हमने कवर करने के लिये बडे अच्छे ढंग से प्रावधान किया है। यह आप लोगों ने इस बजट में देखा भी होगा। मैं इस गरिमापूर्ण हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब यह साल खत्म होगा तो उस समय आप देखेंगे कि यह डैफिसिट यानि घाटे का बजट नहीं रहेगा। आप इस बजट को सरप्लस में बदला हुआ पाएंगे। (विधान) हमने गैर जिम्मेदारी से काम नहीं लिया है। हम मानते हैं कि पिछले साल की जो प्लान थी उस प्लान में हमने ज्यादा रूपया खर्च किया है जो प्रोवीजन पहले किया था हमने उससे ज्यादा

खर्च किया है। आप हमारी परफोरमेंस को क्यों नहीं देखते ? बोलने से पहले आप परफोरमेंस को सामने रखिए, फिर बात कीजिए। (व्यवधान) आप थोड़ा पैँ टैल सुनें। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप केवल 114 करोड़ के डैफिसिट को न देखें, इस बात को देखें कि हरियाणा ने कितनी तरक्की की है और आने वाले समय में हरियाणा सरकार ने स्टेट को आगे ले जाने के लिये कितना प्रावधान किया है और साथ साथ इस बात को भी देखें कि पिछले साल जो प्लॉड ऐक्सपेंडिचर था, हमने उससे ज्यादा खर्च करके इस बात का सबूत दिया है कि हम रूपया सरंजर नहीं करते, खर्च कम नहीं करत बल्कि ज्यादा करते हैं। स्पीकर साहब, 114 करोड़ रूपये का जो खसारे का प्रावधान किया हे, यह बिल्कुल उचित किया है और इस खसारे को कैसे मीट विद करेंगे, इसका भी प्रावधान किया है। इसलिये यह कहना गलत बात है कि साहब, यह बजट खसारे का बजट है। लीडर आफ दि अपोजी इन ने यह बात कही कि साहब पिछले साल का डैफिसिट इस साल बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ बढ़ा है, जो भुरू में प्रावधान किया था, उसके बाद बढ़ा लेकिन लीडर आफ दी अपोजी इन जब बोलती हैं तो इस बात को ध्यान में नहीं रखतीं कि पिछले साल में क्या हालात पैदा हुए जिनकी वजह से खसारा बढ़ा। आप जानते हैं 1984-85 में हरियाणा सरकार को अपने मुलाजिमां को डी0ए0 की चार कि तें देनी पड़ी। इसके साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि कोर्ट के कई डिसीजन हुए जिनकी वजह से सारे साल की रिकवरी रुकी रही ? इसके अलावा,

स्पीकर साहब, कुछ नैचुरल कलैमिटिज कुछ ऐसी हुई जिनकी वजह से सरकार को लैंड होलिंग टैक्स और आबियाना किसानों को मुआफ करना पडा। भाखडा मेन लाईन कौनाल में ब्रीच हुई, कोल्ड वेव चली जिसकी वजह से किसान भाइयों को मुआवजा देना पडा और ज्यादा खर्चा हुआ। स्पीकर साहब, इसके अलावा कुछ डिस्टर्बड कंडी ान्ज रही, हमारे पडौस के प्रान्त में हालात अच्छे नहीं थे, इसका असर हरियाणा पर भी पडा और हमारा रैवेन्य कम वसूल हुआ। ऐसी बात नहीं कही तजा सकती कि सरकार की किसी गलती की वजह से डैफिसिट बढा है। अगर सदस्य ऐसा सोचते हैं तो बडी भारी गलती की बात करते हैं। बहन जी कहते कहते एक बात यह कह दी कि हरियाणा में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है और खास तौर पर लीडर आफ दी अपोजी ान के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अगर विकास के काम की चर्चा करने की जरूरत है कि कितना विकास हुआ है, तो माननीय सदस्यों की सब बातें बिना जवाब के रह जायेंगी, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा स्पीकर साहब, हम इस हालत में पहुंच गये हैं कि पडौसी पद्रे ा हमसे आगे हुआ करता था प्लानिंग के मामले में, प्रोवीजन के मामले में, लेकिन आज हमें गौरव है इस बात का कि आज हम उनसे आगे बढ गये हैं। हमारी प्लान जो पहले 1800 करोड रूपये की थीं हम उसको बढा कर अंगली प्लान 3200 करोड की बनाने जा रहे हैं। 1985-86 की जो हमारी प्लान है, मुझे कहते हुए खु ि है कि पंजाब की प्लान छोटी है और हमारी

प्लान पंजाब से बडी है। क्या यह बिना विकास से ही हो रहा है ?
जैसा कि मैंने अर्ज किया है, अगर मैं सारी डिटेल्स देने लगू तो
बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि लीडर
आफ दी अपोजी उन के मुंह से ऐसी बातें भाभा नहीं देती।
इन्होंने यह भी कहा कि इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर की बात नहीं
होनी चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने यह नहीं कहा कि
ये नहीं होने चाहिए। मैंने कहा कि आप लोगों को साईकल तो
देते नहीं और बातें करते हैं इलैक्ट्रॉनिक्स की।

श्री सागर राम गुप्ता: साईकल के बारे में अगर बहन जी
को कोई भाव हो तो सारी फिगर्स इकट्ठी करवा देंगे कि कुल
साईकल की तादाद कितनी है, कितनी प्रोडक्शन हरियाणा में
बढ़ी है और कंज्यूमर्स के पास कितनी बढ़ी हैं। सारी फिगर्स
आपको दे देंगे। स्पीकर साहब, आज कम्प्यूटर एज है। अगर हम
इस फील्ड में पीछे रह गये तो हमें पीछे रह जायेंगे। आज हमें
इस बात का गौरव है कि स्टेट की फाइनेंसियल मैनेजमेंट बहुत
ही डिसिप्लिन्ड तरीके से चल रही है और हम इसको और भी
डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं। कि सारी स्टेट में प्लान और ना
प्लान पर जो खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट को इसकी फिगर भाम से
पहले पता चल सके ताकि आने वाले दिनों में हम अच्छे ढंग से
काम कर सकें। इस काम के लिये हम कम्प्यूटर सिस्टम लागू
करना चाहते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स

को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके बारे में माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं होनी चाहिए।

स्पीकर साहब, इस हाउस में एक और बात कही गई कि ऐग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। भाग्यद यह बात चौधरी तैय्यब हुसैन ने कही है। उन्होंने कहा कि 11.8 परसेंट रूपये का बजट में ऐग्रीकल्चर के लिये प्रावधान किया है। स्पीकर साहब, आप मानेंगे, ये पुराने माननीय सदस्य हैं, ये पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, बहुत पुराने जमाने में यानी ज्वायंट पंजाब में ये डिप्टी मिनिस्टर होते थे। ये यदि इस किस्म की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐग्रीकल्चर का ताल्लुक केवल ऐग्रीकल्चर इनपुटस सप्लाई करने से होता है, जैसे बीज हैं, फर्टिलाइजर है और कई किस्म की सुविधाएं हैं। ये चीजें किसान के ज्यादा हक में जाती हैं। सिंचाई और बिजली, इन दोनों आईटम्ज के लिये बजट में जो प्रावधान किया हुआ है, भाग्यद माननीय सदस्य ने इनका ध्यान नहीं किया।

चौधरी तैय्यब हुसैन: आपका जो फाइनेंशियल मैमोरेंडम है, यह उसमें लिखा हुआ है।

श्री सागर राम गुप्ता: आज इन दोनों आईटम्ज को नजरअन्दाज कर गये जो कि किसान के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि आज हरियाणा में जो बिजली पैदा होती है, उसका 40 परसेंट हिस्सा ऐग्रीकल्चर के लिये

इस्तेमाल होता है। आप यह भी जानते हैं कि ऐग्रीकल्चर को जो बिजली सप्लाई की जाती है, वह मोहस्ट सबसिडाइज्ड रेट पर सप्लाई की जाती है। मैंने अर्ज किया था कि 1985-86 की जो योजना बनी है, उसमें 156.82 करोड़ रूपया इरीगे टन और 150 करोड़ बिजली के लिये प्रावधान किया है जो 60 परसेंट आफ दी बजट बनता है। हमारा माननीय सदस्य के मुह से यह बात कि हरियाणा सरकार फार्मर्ज के इट्रैस्ट का ध्यान नहीं रखती भाोभा नहीं देती। मैं इन्हे बताना चाहता हू कि हम बजट का 60 परसेंट पैसा बिजली और इरीगे टन पर खर्च कर रहे हैं ऐग्रीक्लचर के लिए प्रोवीजन अलग है मैं सिर्फ बिजली और पानी की बात कर रहा हूँ।

18.00 बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। टैक्नीकली भाायद इतना न हो । जवाब देते समय आप हाउस को यह बता भी क्लोयर कर दे कि ऐग्रीकल्चर के लिए 11.8 परसेंट बजट में ऐलीके टन क्यों की है जबकि इससे रैवेन्यू 45 परसेंट आता है इरीगे टन के लिए ये कहते हैं कि 156 करोड़ रूपये की ऐलीके टन कर दी है। लेकिन मैं इनसे जानता चाहता हू कि क्यो ये पीन का पानी नहरो के द्वारा प्रोवाइड नहीं करते ? इसी तरह से अगर ये बिजली का सारा पैसा ऐग्रीक्लचरल सैक्टर के लिए ही मान ले तो य कोई जवाब नहीं है। इनके अपने इकनौमिक सर्वे के मुताबिक जंहा 82 प्रति टत जनता ऐग्रीक्लचरल पर डिपैन्डेंट हो

वहा बजट केवल 11.8 परसेट ऐलोके ान की जाए तो कोई प्र ाना की बात नही। इस साल तो वैसे भी खाद महगा है डीजल महगा है और हर चीज महगी है। इस सब बातों को जवाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कृपया बेहतररीन तरीके से दे।

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मै इनकी यह गलतफहमी दूर करना चाहता हू। इन्होंने इसमे ऐग्रीकल्चर का नाम पढ लिया लेकिन बजट की बाकी डिटेल् को देखने के लिए आखे बन्द कर ली। न यह देखा कि कोआप्रे ान का कितान बजट है न यह देखा की बिजली का कितना बजट है न य देखा कि ऐनीमल हसबैंडरी पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और न यह देखा कि रोडज के ऊपर कितने खर्च होने जा रहे है। स्पीकर साहब, मै कहता हू कि आज तकरीबन 80 प्रति त Cf the budget is spent by the Haryana Govt. on the walfare of the farmers in teh State.लेकिन ये कहते है कि ऐग्रीकल्चर के लिए कोई प्रवाधान नही है स्पीकर साहब इनकी तसल्ली हो जाएगी यदि मै यह बताऊ कि पिछले तीन साल मे यह खर्चा किस रफतार से बढता गया है 1983.84 मे कृशि तथा सामुदायिक सेवाओं पर जो खर्चा हुआ वह 44 करोड 76 लाख रूपये था। 1984.85 मे यह खर्चा 56 करोड 22 लाख रूपये हो गया और 1985.86 मे अनुमान है कि 57 करोड 77 लाख रूपये हो जाएगा। इसके जाहिर है कि यह खर्चा हर साल बढता जा रहा है। इसी तरह से स्पीकर साहब, विधुत विकास पर 1983.84 मे 203.20 करोड का ऐक्सपैडीचर हुआ, 1984.85 मे

24992 करोड रूपये का ऐक्सपैडिचर हुआ और 1985.86 में 306.20 करोड रूपये का खर्चा होगा।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, क्या फाइनेंस मिनिस्टर साहब तनखाह और प्र ग्रासन पर होने वाले खर्च की ब्रेकअप देगे ?

श्री अध्यक्ष: मैडम, क्या यह प्वायट आफ आर्डर है ?

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, डिवैल्पमेंट पर कोई खर्च नहीं होता। ये गलत ब्यानी कर रहे हैं लगता है गलत फिगरज आपको दी गई है।

श्री सागर गुप्ता: स्पीकर साहब, चूंकि मैं इकनी गलतहफमी को दूर कर रहा हूँ इसलिए इनको हमारी बाते गलत नजर आ रही हैं।

स्पीकर साहब, यह कहा गया कि कसाइनमेंट टैक्स को हमने चू ही इमेजरनी तौर पर ही पकड लिया है और स्टेट को इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं यह कहूँ कि ये कसाइनमेंट टैक्स को भाायद समझते नहीं तो गलत बात नहीं होगी। अगर समझते होते तो ऐसी बात नहीं कहते। स्पीकर साहब, मैं हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि कसाइनमेंट टैक्स केवल उन ट्राजैक रान्ज पर लगता है जा अभी कोई टैक्स नहीं लगता। इनकी यह गलतहफमी दूर हो जानी चाहिए कि हरियाणा सरकार टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात सोच रही है। अगले साल हमने इनकी आमदनी को

क्यो ध्यान मे रखा है इसके बारे मे स्पीकर साहब मै हाउस को बताना चाहता हू कि यह बात भायद सब सदस्यो को मालूम होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परीशद ने राज्य सरकार को आ वासन दिया हुआ है कि इस टैक्स को कानूनी रूप इस साल मे दे दिया जाएगा। मै इन्हे यह भी बताना चाहता हू कि योजना आयोग से जब हमारे अधिकारी मिले प्लान की रूप रेखा डिसकस करने के लिए तो उन्होने भी इस बात का वि वास दिलाया है।
विघ्न

श्री लछमन सिंह: आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। इन्होने अभी कहा कि भायद हमे यह पता नही कि कसाइनमैट टैक्स क्या होता है स्पीकर साहब, हमे इसका पूरा पता है। हमे यह भी पता है इस बारे मे एक सैन्ट्रल ऐक्ट बनने जा रहा है सारी बाते हो चुकी है केवल रैटिफिके इन नही हुई। It will replace the Central Sales Tax.

श्री सागर गुप्ता: स्पीकर साहब, मै फिर रिपीट करता हू कि इनको गलतफहमी है । कसाइनमैट टैक्स उन ट्राजैक् आज पर लगेगा जिनके ऊपर कोई टैक्स आज नही लगता है। मै यह बात बडी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।(विघ्न)

श्री लछमन सिंह: क्या दोनो टैक्स नही लगौगे ?

श्री सागर गुप्ता: मै इस बारे यही तो समझाने को कोि । । कर रहा हू।

Sh. Lachman Singh: Why are you confusing the matter? I know it very well. आपको भायद उससे आधा पता न हो। क्या आप नहीं समझते कि सेंट्रल टैक्स भी रहेगा और कसाइनमेंट टैक्स भी रहेगा।

श्री सागर गुप्ता: स्पीकर साहब, मैं यही तो बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जिन ट्राजक एन्ज पर सेंट्रल सेल्ज नहीं लगेगा केवल उन पर कसाइनमेंट टैक्स लगेगा। (विध्वन)

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह कानून कब तक बन जाएगा ?

श्री सागर गुप्ता: सन 85 के अन्दर अन्दर यह कानून बन जाएगा और लागू हो जाएगा।

स्पीकर साहब चौधरी भले राम जी ने गवर्नमेंट ऐम्पलाइज के बारे में कुछ बातें की हालांकि इस बजट में, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऐम्पलाइज को जितनी सहूलियतें दी गई हैं उतनी भायद किसी और स्टेट गवर्नमेंट में नहीं दी हो। ऐम्पलाइज के जायज हकों की रक्षा करने के लिये काफी कोशिशें की गई हैं। स्पीकर साहब, उन्होंने एक बात यह कही कि बहत की भांती करने के लिए सरकार की तरफ से जो दस हजार रुपये का कर्जा देने की बात की गई है यह उस हालत में भी दिया जाए जबकि लडकी के माता पिता जीवित हों। मैं हाउस को सूचना के लिए बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा सरकार ने

पहले ही यह फैसला कर लिया है कि सरकारी कर्मचारी बहन या लडकी की भाादी के लिए 10 हजार रूपये का कर्जा ले सकेगा चाहे माता पिता जीवित हो या न हो लेकिन वह उस ऐम्पलाई के ऊपर आश्रित होने चाहिए यह बात ठीक है कि पहले यह कर्जा नहीं मिलता था यदि मा बाप जीवित होते थे

स्पीकर साहब, यहा एक बात यही कही गई कि ये जो ग्रिबैन्सीज कमेटीज होती है, डिस्ट्रक्ट पब्लिक रिले ान्ज कमेटीज होती है इनमे काग्रेस पार्टी के लोग लिए जाते है। स्पीकर साहब, ये कितने गलत बात करते है? (विघ्न)

चौधरी धीर पाल सिंह: आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। मुझे और चौधरी मागे राम जी को तो आज तक नहीं बुलाया गया है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायट आफ आर्डर नहीं है

श्री सागर गुप्ता: स्पीकर साहब, क्या इनको गोदी मे बिठाकर लाया जाए ? They are ex officio members of these committees and they must attend the meetings of these committees अगर ये अटैन्ड नहीं करते तो ये अपनी कास्टिच्यूएँसी के लोगो के साथ इन्साफ नहीं करते। स्पीकर साहब, आपको पता कि डिस्ट्रक्ट कमेटी मे हर एम0एल0ए0 चाहे वह किसी पार्टी का है ऐक्स औफि ायो मैम्बर होता है।(विघ्न)

स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैन्सिज कमेटी में उस इलाके में अभी पोलिटिकल पार्टीज के एम0एल0ए0 और एम0पी0 मैम्बरज होते हैं। उसके अलावा कुछ और भी मैम्बरज होते हैं जो आम जनता से लिए होते हैं। उनको लेते समय पोलिटिकल पार्टीज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। उसमें तो यही ध्यान रखा जाता है कि कौन लोग मकबूल हैं कौन लोग ऐडमिनिस्ट्रेटिव के सामने लोगों की दिक्कत रख सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रख के उस कमेटी में मैम्बरज के लिए जाते हैं। (गोर एवम विघ्न)

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैंने यह बात कही थी कि ग्रिवैन्सिज कमेटी में ये उन्हों को मैम्बरज लेते हैं जो इन्हे अच्छे लगते हैं। अपनी पार्टी के ही मैम्बरज को लेते हैं दूसरी पार्टी के लोगों को मैम्बरज नहीं लेते हैं। (गोर एवम विघ्न)

श्री औमप्रकाश वर्मा: आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मंत्री जी ने एक बात कह दी कि जो एम0एल0ए0 डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैन्सिज कमेटी की मीटिंग में नहीं जाते वह अपने फर्ज में गफलत बरतते हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि ग्रिवैन्सिज तो हमें सरकारी कर्मचारीयों के खिलाफ होते हैं, कमेटी में वही सरकारी कर्मचारी बैठे हुए होते हैं उनके सामने अपने ग्रिवैन्सिज कैसे रखें? मीटिंग में एम.डी.एम. , बी.डी.ओ. और डी.सी. आदि अफसर होते हैं। अगर हम अपने ग्रिवैन्सिज उनके सामने उनके खिलाफ लाते हैं तो उससे उल्टा

असर पडता है बजाए हमे फायदा होने के। इसलिए मैने आज तक डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैन्सिज कमेटी की मीटिंग अटैन्ड नहीं की।

श्रीमती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, रोहतक ग्रिवैन्सिज कमेटी मे कांग्रेस के नोमिनेटिड आदमी है। और उन्ही के खिलाफ रिक्वायत आती है। (और एवम विघ्न)

चौधरी भाम शेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, डाक्टर औम प्रकाश जी ने ऐसी बात कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। अम्बाला जिले मे डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैन्सिज कमेटी मे मेरी डियूटी लगा रखी है। वहा पर जो भी मैम्बरज आते है चाहे वे कितने ही बडे बडे अफसर क्यो न हो उनके खिलाफ भी बडी फीक्विन्टली और औपनली बात सुनाते है। यह बिल्कुल गलत बात है कि अफसरों से लोग बात करते हुए डरते है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमारी हिसार की डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैन्सिज कमेटी के प्रैजिडेन्ट मुख्य मंत्री जी है। इनको फुर्सत ही नहीं होती है। छ छ महीने तक इनके दिन ही नहीं होते है। जब ये जाते है तो हम जरूर पहुचते है जहा डी0सी0 प्रिजाइड करे वहा उस दिन हम नहीं जाते। मंत्रियों को कहे कि वे प्रिजाइड करे। जो प्रिजाइड करने वाला है उसके खिलाफ रिक्वायत नहीं की जा सकती। मै मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूगा कि हिसार के लिए किसी और मंत्री की डियूटी लगा दे आप मीटिंग मे जरूर पहुचा करे।

चौधरी भजन लाल: आपकी बात पर गौर किया जायेगा।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: आप तौर डिप्टी कमी ानर ग्रिवैन्सिज कमेटी को प्रिजाइड करता है जब कि मिनिस्टर की डियूटी लगी होती है इसलिए जब तक वहा मिनिस्टर न जाये मीटिंग नही होनी चाहिए क्यो कि डी०सी० फ़ैसला नही ले सकता। अगर मिनिस्टर वहा पर कई मामले ऐसे होते है जिन पर डी०सी० फ़ैसला नही ले सकता। अगर मिनिस्टर वहा पर हो तो वे हवी पर निपट सकते है। इसलिए मिनिस्टर न पहुचे तो मीटिंग नही होनी चाहिए।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, जीन्द के अन्दर चौधरी राजेन्द्र सिंह इन्चार्ज है। वे वह पर केवल दो बार गये है।(गोर एवम विघ्न)

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, जो बजट की डिसक ान के दौरान प्वायट उठाये गये है उनका मै जवाब देना चाहता हू लेकिन चूकि ये मुझे दूसरी और डायवर्ट कर रहे है। इसलिए मै प्रोपर जवाब नही दे सकूंगा। बाद मे यह कहेंगे कि हमारी बात का जवाब नही दिया। स्पीकर साहब, धमीजा जी ने और कुछ अन्य मैम्बर्ज ने मांग की है कि अम्बाला मे मैडिकल कालेज खोला जाये। हरियाणा सरकार अम्बाला मे मैडिकल कालेज नही खोल सकेगी क्योकि मैडिकल कौंसिल आफ इडिया ने कुछ स्टैन्डर्ड ले डाउन कर रखे है जिनके अनुसार चलना होता है

मैडिकल कौंसिल आफ इंडिया के कुछ स्टैन्डर्ड ने डाउन कर रखे है जिनके अनुसार चलना होता है मैडिकल कौंसिल आफ इंडिया के अनुसार डाक्टरों की तादाद बढ़ गई है जिसके कारण अन एम्पलायमेंट आ गई है इसलिए हरियाणा में मैडिकल कॉलेज नहीं खोला जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी इन्स्टीच्यू इन खोलने से पहले उसके कैचमेंट एरिया का ध्यान रखा जाता है अम्बाला के नजदीक पटियाला, फरीदकोट और पी0जी0आई0 है इन जगहों पर मैडिकल कॉलेज है। इस बात को देखते हुए वहाँ पर मैडिकल कॉलेज खोलना मुनासिब नजर नहीं आता। तीसरी बात यह है कि मैडिकल कौंसिल ने जो स्टैन्डर्ड ले डाउन कर रखे है उनके मुताबिक भी हरियाणा में मैडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता। हमारा रोहतक मैडिकल कॉलेज बड़ा अच्छा चल रहा है। वहाँ पर 115 स्टुडेंट्स एम0बी0एस0 और 20 स्टुडेंट्स बी0डी0एस0 के हैं क्लिनिकल मैटीरियल चाहे वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आखिरी मजबूरी हमारी यह भी है कि पचास करोड़ रूपया खर्च करना हरियाणा सरकार मुनासिब नहीं समझती क्योंकि इतना ज्यादा पैसा डिवलपमेंट के कामों पर खर्च करना हम ज्यादा मुनासिब समझते हैं।

स्पीकर साहब, बहिन चन्द्रावती जी की कुछ आदत ही ऐसी बन गई है कि वे अपनी स्पीच के दौरान कुछ स्वीमिंग रिमार्कस कर जाती हैं। इन्होंने कहा कि हरियाणा में सेनीटे इन की हालत बहुत खराब है। हालत ठीक करवाना चाहती हैं इस बारे

मे कुछ नहीं बताया। वैसे ही कह दिया कि सेनीटे ान की हालत खराब है । अगर वे निचि चत तौर पर बतायेगी कि वहा की हालत खराब है तो सरकार गौर करेगी।

श्रीमती चन्द्रावती: किसी भी टाउन या गांव मे अच्छी कन्डी ान नहीं है। सभी जगहो पर सैनीटे ान की हालत खराब हैं।

श्री सागर राम गुप्ता: आप पिजौर मे जाइये वहा पर सैनीटे ान की बहुत बढिया हालत मिलेगी। आप ऐसी जगहो पर क्यो जाती है जा हालत खराब है स्पीकर साहब इन्होने एक और स्वीपिंग रिमार्कस दिया कि सारी भाहरो की गलियों और सडको पर अन्धेरा ही अन्धेरा है कोई टयूब लाइट नहीं है गलियो मे बल्ब नहीं है स्पीकर साहब, आप और हम सारे के सारे घरों से बाहर निकलते है यह बात नहीं है कि हम घरों मे ही कनफाइन रहते हो, बारह भी निकलते है सारे आनरेबल मैम्बर्ज देखते है सडको पर टयूबलाइट चमकती हुई नजर आती है गांव की गलियो मे बल्ब लगाये हुए है। अगर बहिन जी बताये कि फला जगह पर बल्ब या टयूब लाइट नहीं है तो वहा पर निचि चत तौर पर इन्तजाम करेगे। (गोर एवम विघ्न) इसी तरह से एक बात और स्वीपिंग तौर पर कह दी गई कि स्टैम्प डियूटी बढा दी। इन्होने यह भी कहा कि यहा पर सारे भ्रष्ट है सारे ही खाने पीने वाले है और सारा मामला गडबड हो गया है। स्पीकर साहब छाज ओर छलनी वाली बात मै कहना नहीं चाहता लेकिन मै उनसे पूछना चाहता हू कि वे

तीस लाख रूपये के कूपन कहा पर है जिनके लिये आज भी चौधरी चरण सिंह जी पूछ रहे हैं? पहले आप अपने गरेवाल में मुह डाल कर देखे। (गोर एवम विघ्न) आज हरियाणा की ऐडमिनिस्ट्रे टन में जो भी अफसर है वे बहुत अच्छे हैं। (गोर एवम विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, ये इस बात को जानते हैं कि यह झूठी बात है। ये गीता पर हाथ रख कर कह दे कि ऐसी मैंने किया था। ये सारे जो उधर डिफैक्टर्ज बैठे हैं ऐसी बात कहते हैं। ये सब झूठी बात कहते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। (गोर एवम विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो ऐसप न बहिन जी पर किया गया है वह अच्छा नहीं। सागर राम गुप्ता जी मिनिस्टर हैं उन्हें जिम्मेदारी की बात कहनी चाहिए। कूपन में कोई हेराफेरी नहीं हुई कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इन्होंने ऐसे ही कह दिया कि चौधरी चरण सिंह जी भी पूछ रहे हैं। पता नहीं कि ये किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं हमारी पार्टी में किसी किस्म की कोई कूपन की हेराफेरी नहीं हुई। स्पीकर साहब, जो कूपनो से चन्दा इकट्ठा हुआ उसमें सब से ज्यादा कलैक् टन करने में आज के मुख्यमंत्री का हाथ था। (गोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: हमने कभी चन्दा इकट्ठा नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र सिंह: चौधरी साहब, आप ईमानदारी से कह दे कि आपने किसान रैली के लिए पैसा इकटठा नहीं किया।

चौधरी भजन लाल: आप खुद कहते थे कि पता नहीं बहिन जी से कैसे कूपन्ज की गडबड हो गयी।(तोर एवम विघ्न) मैं दूसरी बात कहूंगा तो आपकी तकलीफ होगी। (तोर एवम विघ्न) आप और चौधरी देवी लाल तो यहा तक कहते थे कि चौधरी चरण सिंह ने जो 78 लाख रुपया इकटठा किया था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है।(तोर एवम विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती: मैं तो परमात्मा के सामने कहती हू कि वह झूठे कहने वाले आदमी को सजा दे।(तोर एवम विघ्न)

एक आवाज: औरो का भी तो परमात्मा है, मैडम।(तोर एवम विघ्न)

श्री सागर राम गुप्ता: मैं बहिन जी की सूचना के लिये यह बताना चाहता हू कि हरियाणा में निरन्तर स्टैम्प डियूटी की आमदनी में, रजिस्ट्रें इन फी की आमदनी में और नम्बर आफ डाकुमैटस रजिस्टर्ड में इन्क्रीज होती रही है। मैं फिगर्ज से यह बात वाजेह करना चाहता हू। 1978-79 में स्टैम्प डियूटी से आमदनी 10 लाख 60 हजार रुपये थी। यह 1979-80 में बढ़ कर 11 लाख 99 हजार रुपये हो गयी और 1980-81 में यह बढ़कर 16 लाख 12 हजार रुपये हो गयी।

एक आवाज: आप गलत ब्यानी कर रहे है। लैड की कीमत बढी है।

श्री सागर राम गुप्ता: नही, डाकुमैटस का नम्बर भी बढा है और रजिस्ट्रे टन फी आमदनी भी बढी है। 1981-82 मे इससे आमदनी 21 लाख 72 हजार थी 1982.83 मे यह बढकर 23 लाख 4 हजार हो गयी और 1984.85 मे यह 25 लाख 25 हजार रूपया हो गयी है। तो इस तरह की बाते कहना कि यह पैसा खा गया वह पैसा खा गया, भाभा की बात नही है। स्वीपिंग बाते कह देना, कोई वाजिब बात नही है। (गोर एवम विघ्न) आपकी बातों का तो हम जवाब नही दे सकते क्योकि हमारे अन्दर तो इतनी हिम्मत ही नही है कि 30 लाख रूपये के कूपन खा जाये। हमारा तो इतना बडा हौसला ही नही है (गोर एवम विघ्न) एक बात चौधरी भले राम जी ने कही कि गरीब बच्चो, ि अडयूल्ड कास्टस के बच्चो की वजीफे वगैर की भाक्ल मे जो इमदाद दी जाती है उसमे कुछ न कुछ बढौतरी होनी चाहिए। उनकी यह बिल्कुल जायज बात हैं स्पीकर साहब, चौधरी भले राम जी की बात को ध्यान मे रखते हुए मै उनको एक बात बताना चाहता हू।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुझे इन्ट्रू टन के लिए आप मुआफ करेगे। मै कोई व्यक्तिगत बात नही कहती। इनकी साइकिल की ब्यौत नही थी लेकिन आज कितने हजार प्रौपर्टी हैं। मुख्य मंत्री जी आप इस बात को दिखा ले। (गोर एवम विघ्न)

आप इनकी और मेरी प्रॉपर्टी दिखा ले पता चल जायेगा कि किसने कितनी इकट्ठी की है।

श्री सागर राम गुप्ता: ठीक है । क्या आप इस बात के लिये तैयार हो ?

श्रीमती चन्द्रावती: बिल्कुल तैयार हूँ।

श्री सागर राम गुप्ता: बिल्कुल ठीक है करवा देगे इन्कवायरी। (हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती: हां करवा दो। इक्वायरी आप सब लोगो की भी हो और हमारी भी हो।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज आर्डर। ग्रेवाल जी आप बैठिये। अब काफी बात हो गई है।

श्री सागर राम गुप्त: स्पीकर साहब, श्री भले राम जी की बात ठीक है कि रिटायर्ड कास्टस और रिटायर्ड ट्राईब्स के बच्चो को वजीफे के रूप में ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं उनको सूचना के लिये बताना चाहता हू कि भारत सरकार की एक स्कीम के मुताबिक उन सब बच्चो को जो हमारी स्टेट में पढते है वजीफ देते है 11 वी कक्षा ओर 12वी कक्षा तक जो बच्चे होस्टल में रहते है उनको 75 रूपये लडको को वजीफा और 85 रूपये लडकियो का वजीफा दिया जाता है जो होस्टलर्ज नहीं है और डे स्कालरज है उन लडको को 50 रूपये और लडकीयो को 60 रूपये

वजीफा दिया जाता है। अगले साल 80 रुपये और 55 रुपये लडको और 95 रुपये और 70 रुपये लडकियों को, होस्टलर्ज और डे स्कालरज को, क्रम 1 दिया जाता है। इसके अलावा जनरल कोर्सिज के लिए 115 रुपये और 70 रुपये लडको और 130 रुपये और 85 लडकियों को होस्टलर्ज और डी स्कालरज को क्रम 1 दिया जाता है। स्पीकर साहब, इसके अलावा जैसे कि आप सब को पता है हरियाणा में एक बुक बैंक खाता खोला हुआ है जिससे सारे हरिजन बच्चों को फ्री किताबें सप्लाई की जाती हैं। इसी तरह से हम और भी वित्तीय सहायता इनके लिये बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी जरूरियात इन हरिजन बच्चों की है, हम यह चाहते हैं कि उनमें तालीम का प्रसार करने के लिये पूरी की जाये ताकि वे अपने जीवन स्तर को दूसरों की तरह से उचा उठा सकें। यह पर बिलो पावर्टी लाईन फैमिलीज का भी जिक्र किया गया है। हम ज्यादा तेजी से उनको भी ऊपर उठाने के लिये कोर्सेज कर रहे हैं। श्री भले राम जी को मैं विन्यास दिलाना चाहता हूँ कि जो सुझाव उन्होंने इसके लिये दिया है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भले राम जी एक बात और कही। उन्होंने यह कहा कि आजकल इम्तहानों में नकल बगैरा कुछ ज्यादा हो रही है उसके लिये एक साल के लिस ट्रायल बेसिज पर छोड़ दिया जाये। अगर कोई टीचर रिजल्ट अच्छा दिखाता है तो उसको प्रोमोशन और एक्सेजमैट देने की पालिसी को एक साल के लिए छोड़ दिया जाये, यह उनका कहना है। स्पीकर साहब मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार

यह ट्रायल नहीं कर सकती क्योंकि आप जानते हैं कि जहा तक टीचर्ज की इन्करेजमैट का या उनकी प्रोमोशन का सवाल है, या उनकी कान्फीडेंसियल रिपोर्ट्स लिखने का ताल्लुक है एक मापदण्ड उसके लिये यह है कि उसका रिजल्ट कैसा है और उन्होंने बच्चों को पढाने में कितनी दिलचस्पी ली है। इसी के आधार पर उनको आगे प्रोमोशन दी जाती है। मैं यह मानता हूँ जैसे उन्होंने कहा कि नकल करना आजकल कुछ बढ़ गया है लेकिन सरकार इसके लिये प्रबन्ध कर रही है। सरकार फ्लाइंग स्कवैड बना रही है और बोर्ड के तथा दूसरे सिविल अधिकारियों की डियूटी लगायी जाती है कि वह खास तौर पर इम्तहानों के दिनों में वहा पर जाकर जांच करे। ऐसा इसीलिये किया जा रहा है ताकि जहा पर एम्प्लोयीनेशन सैटर्ज बन रहे हैं, वहा पर जांच हो सके और बच्चे नकल करने की कोशिश न करे।

श्री अध्यक्ष: कितना टाईम आप औं लेंगे ?

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, अभी कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगे।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि ये 10 मिनट में ही खत्म कर देंगे। (गोर एवम विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने जवाब बहुत बढ़िया दिया है। (गोर एवम विघ्न)

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, अगर ये कहते हैं कि इनकी तसल्ली हो गयी है तो टाईम बढ़ाने की जरूरत नहीं है मैं अपनी बात यही खत्म कर देता हूँ।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं एक बात क्लीयर करना चाहता हूँ। आज श्री मांगे राम जी ने हाउस में बोलते हुए यह कहा कि रोहतक कोआप्रेटिव बैंक में कुछ सिलैव एन्ज हुई थी उसमें रोहतक जिले का एक भी लडका नहीं लिया गया। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी गलत बात हाउस में कही है। वहा पर कुल 42 पोस्टे थी और 42 में 24 क्लर्कर्स रोहतक जिले के लिये गये हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: किस साल की बात कर रहे हो ?

चौधरी भजन लाल: इस साल की बात कर रहा हूँ।

चौधरी भजन लाल: आप वकील हो वकील का यही तो काम होता है कि कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल दे। (गोर एवम विघ्न) आप कोई भी ऐसा साल नहीं बता सकेगे जिसमें रोहतक जिले का कोई आदमी वहा पर न लिया गया हो (गोर एवम विघ्न) मैं यह कहता हूँ कि रोहतक जिले के मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा कुल 42 आदमी लिये गये हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मुख्य मंत्री जी आपके जवाब में हमारी तसल्ली नहीं हुई है, आप कृपया पूरे फ़ैक्ट्स एण्ड फ़िर्गज कल दे देना।

चौधरी भजन लाल: मैं आज ही बता रहा हूँ कि 24 तो रोहतक जिले के लिये गये हैं और बाकी सोनीपत और दूसरे जिले के हैं जो कायदे के अनुसार लिये गए हैं।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रात साढ़े नौ बजे तक के लिये ऐडजर्न किया जाता है।

18.29 बजे

तत्प चात सदन मंगलवार दिनांक 26.3.1985, को प्रातः साढ़े नौ बजे तक के लिये स्थगित हुआ।

APPENDIX

Repairs/overhauling of vehicles in the irrigation Drainage De partment

***855 Shri Kitab Singh:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of turcks cars and jeeps existing at present in the irrigation Department Drainage Circle in Haryana together with total amount of expenditure incurred on their reparis.

(b) whether any of the vehicle referred to in part (a) above have been overhauled: if so, the number thereof together with the number of kilometers covered by each at the time of overhauling and the amout of expenditure incurred for the said purpose speartely and

(c) the quantity of oil and mobil oil consumend by each on of the vehicles referred to in part (b) above separately during the period form 1-81982 to 1-1985

Irrigation and Power Minister(Chaudhri Shamsher Singh Surjewala)

(a) 35 No. Trucks and 63 Jeeps presently exist in Drainage Circle of Irrigation Department and there is no car. Totla expenditure excluding overhauling incurred on their repairs for the year 1984-85 works out of Rs. 515463/-

(b) Yes, out of the total vehicles referred to in part (a) 70 No. (22 trucks and 41 Jeeps) have been overhauled. Details of expenditure incurred on overhauling an dkilometers covered by each vehicle at the time of overhauling are given in Annexure A/I and A/II and

(c) details for uqantity of oil and Mobile oil consumed form 1-1-1982 to 1-1-1985 by each vehicle referred to in part (a) are given in Annexure B/I and B/II

ANNEXURE - A/1

Statement showing details expenditure incurred K.Ms covered at the time of over hauling of each truck of Drainage Admn of Irrigation Deptt, Haryana

Name of Circle	Sr. No.	Truck overhauled	No of Km covered at the time of overhauling	Expenditure

1	2	3	4	5
W.J.C	1	HRG 8443	61122	21656/-
Feeder/ G.C Delhi	2	HRG 5601	159116	25579/-
U.D.D Circle No.	1	HRC 5897	55884	9842/-
Faridabad	2.	HRC 5898	52914 54212	12471/- 1482/-
	3.	HRL 1812	105212	5610/-
	4.	HYA 4349	49244	10671/
	5.	HYA 4530	30836	224454/-
U.D.D Circle	1.	HRU 801	83063	10314/-
No. II Gurgaon	2.	HRU 802	42800	5804/-
	3.	HRU 803	80000	13810/-
	4.	HRU 804	43797	17823/-
	5.	HRC 1713	11223	5729/-
	6.	HRB 4531	22000	16448/-
Drainage Circle	1.	HRK 4022	338378	49692/-

Karnal	2	HRK 4023	274854	43663/-
Drainage Circle	1.	HRP 2896	(i) 277303	11616/--
			(ii) 347247	52474/-
	2.	HRO 3805	143226	16376
	3.	HRA 2376	(i) 145353	9903
			(ii) 184834	24489
	4.	HRB 4480	82773	10963
Drainage Circle	1	HRB 4603	47046	15977
Hissar	2.	HRB 3541	61500	37513
	3.	HRB 6855	47940	22863

ANNEXURE - A/II

Statement showing details expenditure incurred
K.Ms covered at the time of over hauling of each truck of
Drainage Admn of Irrigation Deptt, Haryana

Name of Circle	Sr. No.	Jeep over hauled	No of Km covered at the time of overhauling	Expenditure
1	2	3	4	5

W.J.C	1	HRC 9098	69695	23748
Feeder/ G.C Delhi	2	HRG 675	82529	13910
	3.	HRC 1118	224571	14779/-
	4.	HRC 290	100250	22897/-
	5.	HRC 8866	31200	24475
	6.	HRC 4286	84304	26264
	7.	PUH 2644	3680	16800
	8	HRC 5734	163064	7470
	9.	HRC 5724	28380	8332
	10.	HRM 7830	129631	5300
U.D.D Circle 1, Faridabad	1.	HRP 570	43147	1995
		HRU 802	42800	5804/-
			82548	7134
			133806	10606
	2	HRP 693	190918	169947
	3	HRC 5713	76971	4010
			127238	6673

	4.	HRP 683	41705	3479
			106409	10076
			161816	18521
	5.	HRP 5043	59804	1050
			12840	11000
	6	HRP 5062	82274	15023
			119547	12330
	7.	HRP 5262	63098	10580
			101608	7820
	8.	HRG 4890	---	6884
U.D.D Circle 11 Gurgaon	1.	HRP 571	134404	15000
	2	HRP 5042	11768	5083
	3.	HRC 7981	109999	11029
	4.	HRC 7878	79791	6154
	5.	HRC 7857	118876	7013
	6.	HRC 6481	34531	8591
	7.	HRG 8386	22000	6557
	8.	HRG 7986	87000	9500

	9.	HRG 6945	60000	12000
			86500	4000
			1395000	9000
Drainage Circl	1.	HYA 9202	140000	13624
Krnal	2.	HRA 643	116000	13373
	3.	HRQ 3223	73201	3389
	4.	HRO 981	67643	253
			160573	16325
			81134	18519
	5.	HYC 8225	65322	12950
Drainage Circl	1.	HRO 4291	127147	11824
Rohtak	2.	HRT 1523	71603	14092
	3.	HRR 5624	95000	10432
	4.	HRO 4272	125000	7900
	5.	HRK 2506	55000	7800
	6.	HRM 5563	18137	4453
	7.	HRM 7813	17550	5194

			77832	10727
			84292	4127
Drainage Circl	1.	HRN 7137	85995	3982
Hisar	2.	HRJ 3092	92085	14337
			106350	8560
	3.	HRJ 3093	85364	15123
	4.	HRB 6450	47395	15889
	5.	HRK 3172	41551	6776
	6.	HRT 1007	60000	6000
	7.	HRT 1006	62000	12800
	8.	HRH 6336	17058	8660
			53705	6445

ANNEXURE - B/I

Statement showing quantity of oil/Mobile consumed
by each vehicle during the period from 1-8-1982 to 1-1-1985
of Drainage Admn. Irrigatin Deptt Haryana

Name of Circle	Sr. No.	Truck No.	Oil conumed by each vehicle in	Mobile oil consumed in litres
----------------------	---------	-----------	---	-------------------------------------

			liters	
1	2	3	4	5
W.J.C	1	HRC 8401	7982	375
Feeder/ G.C Delhi	2	HRG 8443	3234	127
	3.	HRC 5601	7678	354
	4.	HRG 8388	7726	296
	5.	HRG 8387	184	16
	6.	HRG 3960	11680	453
U.D.D Circle 1, Faridabad	1.	HRC 5897	7815	183
	2.	HRC 5898	6172	213
	3.	HRL 1812	7055	373
	4.	HYA 4349	175	9
	5.	HRB 4530	550	12
U.D.D Circle II Gurgaon	1.	HRA 7649	4500	80
	2.	HRU 801	14451	733
	3.	HRU 802	10231	181

	4.	HRU 803	14896	663
	5.	HRU 804	10618	153
	6.	HRB 4527	8259	459
	7.	HRC 1713	2724	54
	8.	HRB 4531	11916	10076
Drainage Circle Karnal	1.	HRK 4023	12209	625
	2.	HRK 4022	13930	712
	3.	HRD 8291	4180	184
	4.	HRM 8866	574	24
Drainage Circle Rohtak	1.	HRR 2896	13672	225
	2.	HRO 3805	3998	98
	3.	HRM 8867	5413	99
	4.	HRA 2376	7705	187
	5.	HRB -4480	11307	382
Drainage Circle Hisar	1.	HRB 4603	974	12
	2.	HRB 3542	19384	242
	3	HRB 3541	26563	327

	4.	HRB 6856	18006	225
	5.	HRB 6855	19047	242
	6.	HRO 3439	1295	31
	7.	HRB 3805	350	15

ANNEXURE - B/II

Statement showing quantity of oil/Mobile consumed by each vehicle during the period from 1-8-1982 to 1-1-1985 of Drainage Admn. Irrigatin Deptt Haryana

Name of Circle	Sr. No.	Jeep No.	Oil conumed by each vehicle in liters	Mobile oil consumed in litres
1	2	3	4	5
W.J.C	1	HRC 9098	6945	316
Feeder/ G.C Delhi	2	HRC 675	5854	174
	3.	HRC 1118	8926	235
	4.	HRC 290	7387	115
	5.	HRC 8866	8561	154
	6.	HRC 4286	17842	573

	7.	PUH 2644	515	20
	8.	HRC 5734	10499	145
	9.	HRC 5724	7619	72
	10.	HRM 7830	5264	71
U.D.D Circle II Faridabad	1.	HRP 570	7912	144
	2.	HRC 693	9215	207
	3.	HRC 5713	10271	190
	4.	HRP 683	3854	129
	5.	HRP 5043	10009	278
	6.	HRP 5062	9375	207
	7.	HRP 5262	6372	236
	8.	HRG 4890	1834	36
U.D.D Circle II Gurgaon	1.	HRP 571	7768	238
	2.	HRB 8074	2615	77
	3.	HRC 7977	7841	208
	4.	HRC 7986	8248	211
	5.	HRC 6945	3084	93

	6.	HRC 7878	10297	284
	7.	HRC 6481	5290	164
	8.	HRG 8386	7172	339
	9.	HRG 7802	3900	37
	10.	HRG 7981	6710	103
	11.	HRT 1008	2061	12
	12	HRG 7857	4529	81
	13	HRM 378	6443	139
	14.	HRP 5042	6710	135
Drainage Circle Karnal	1.	HRA 9202	14503	410
	2.	HRA 643	7644	240
	3.	HRK 150	2842	69
	4.	HRL 9093	11010	349
	5.	HRQ 3223	11666	266
	6.	HYK 4150	8078	219
	7.	HRO 981	13912	284
	8.	HYK 3651	7099	201
	9.	HYS 88	6878	249

	10.	HYS 8338	6580	244
	11.	HYS 8225	5500	209
Drainage Circle Rohtak	1.	HRO 4291	8201	212
	2	HRT 1523	4255	157
	3.	HRR 562	8192	254
	4.	HRO 4272	9117	98
	5.	HRK 2506	7276	124
	6.	HRO 984	8602	144
	7.	HRM	7813	7098
	8	HRM 5563	1781	51
	9	HRC 7981	1514	30
Drainage Circle Hissar	1.	HRM 7137	6077	110
	2.	HRL 1181	5894	99
	3.	HRJ 3092	7885	97
	4.	HRB 3093	18414	224
	5.	HRB 6449	18414	224
	6.	HRB 6450	16737	209

	7.	HRB 6464	13109	164
	8.	HRK 3172	886	54
	9.	HRH 6336	7880	196
	10.	HRT 1007	9000	172
	11.	HRT 1006	5085	198